गुवाहाटी व जोरहाट से एक साथ प्रकाशित

सच से समझौता नहीं

प्रातः खबर

www.pratahkhabar.com

RNI NO. ASSHIN/2005/15049 PRATAH KHABAR, Guwahati, Wednesday, 22 July, 2026 वर्ष 23 अंक 82, गुवाहाटी, बुधवार 22 जुलाई, 2026, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष-8 मूल्य : दस रुपये पेज-12

रोहित नहीं गौतम की जगह पर सवाल उठने चाहिए-10

अदाकारी की बेमिसाल मल्लिका पूरबी शर्मा-12

सुप्रभातम्

कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता।

29 को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। राज्य में जारी बाढ़ की गंभीर स्थिति के कारण मिसिंग स्वायत्त परिषद (एमएसी) चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची की तैयारी का कार्य प्रभावित हुआ है, जिसे देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के प्रकाशन की समय-सारणी में संशोधन किया है। राज्य चुनाव आयुक्त रंजन शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में बाढ़ के कारण पूर्व में 30 जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक चुनावी नामावलियां तैयार करने की गतिविधियां पूरी नहीं की जा सकी थीं, जिसके चलते मिसिंग स्वायत्त परिषद (चुनाव) नियम 2005 के नियम 16 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नयी संशोधित तिथियां घोषित की गयी हैं। नयी संशोधित समय-सारणी के अनुसार अब प्रारूप मतदाता-सूची का प्रकाशन 29 जुलाई को होगा, जिसके बाद किसी भी तरह के दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 13 अगस्त निर्धारित की गयी है। दर्ज शेष पृष्ठ आठ पर

त्रिपुरा के डीजीपी का शव ले जाया गया दिल्ली, उप्र में होगा अंतिम संस्कार

अगरतला, 21 जुलाई (भा)। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ का शव आज एयर एंबुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया। धनखड़ का शव कल अगरतला में पुलिस मुख्यालय स्थित उनके आधिकारिक कक्ष के शौचालय में फंदे से लटका मिला था। अधिकारियों ने बताया कि धनखड़ का अंतिम संस्कार कल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले स्थित उनके पैतृक गांव बड़ौत में किया जाएगा। त्रिपुरा के राज्यपाल एन इंद्रसेना रेड्डी, मुख्यमंत्री माणिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारियों ने अगरतला स्थित सिविल सचिवालय में डीजीपी को श्रद्धांजलि दी। धनखड़ को पुलिस मुख्यालय में सलामी भी दी गयी। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस मामले में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। शेष पृष्ठ आठ पर

नेपाल सरकार ने निजी शिक्षा, स्वास्थ्य पर लगे कर लिया वापस लिया

काठमांडू, 21 जुलाई (भा)। नेपाल सरकार ने आज निजी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर लगाये गये तीन प्रतिशत कर को व्यापक विरोध के बाद वापस ले लिया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह फैसला आम लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ को लेकर उठी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ विचार-विमर्श के बाद सरकार ने फिलहाल इस कर को फिलहाल लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। पिछले महीने पेश बजट में इस कर का प्रस्ताव रखा गया था और शेष पृष्ठ आठ पर

असम में बाढ़ से 11 जिलों के 3.10 लाख लोग प्रभावित

गुवाहाटी, 21 जुलाई (भा)। राज्य में आज बाढ़ से एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गयी। राज्य के 11 जिलों में अब भी 3.10 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ब्रह्मपुत्र, दिखौ, देसांग और धनसिरी समेत राज्य की कई प्रमुख नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनमें से कुछ नदियों का जलस्तर अत्यधिक बाढ़ के स्तर को भी पार कर गया है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा सहित कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। ऊपरी असम के कुछ हिस्सों में रेलवे पटरियों पर बाढ़ का पानी भर जाने के कारण लगातार दूसरे दिन भी रेल सेवाएं प्रभावित रहीं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने कई ट्रेनों को रद्द किया और कुछ का मार्ग परिवर्तित किया। साथ ही फंसे हुए यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों की भी घोषणा की। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने एक बयान में कहा कि चराइदेव जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही इस वर्ष बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गयी है। अधिकारियों ने बताया कि बिस्वनाथ, चराइदेव, धेमाजी, डिब्रुगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कार्बी आंगलांग, नगांव, शिवसागर और तिनसुकिया जिलों के 758 गांवों में 3.10 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिला है, यहां दिखौ नदी का शिवसागर शहर में और देसांग नदी का नंगलामोराघाट में जलस्तर अत्यधिक बाढ़ के स्तर से ऊपर दर्ज किया गया है। प्राधिकरण ने बताया कि गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी शेष पृष्ठ आठ पर

मृतकों की संख्या बढ़कर 11

नगालैंड : बाढ़ व भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई नौ

कोहिमा, 21 जुलाई (भा)। नगालैंड के मोन जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण अचानक आयी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गयी है। राज्य सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार आज जारी तलाश एवं बचाव अभियान के दौरान पांच शव बरामद किये गये, जबकि चार लोग अब भी लापता हैं। इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इससे बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और सार्वजनिक संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने आकलन जारी रहने के साथ नुकसान का दायरा और बढ़ने की आशंका जतायी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार बारिश के कारण राज्यभर में कम से कम 7,460 लोग प्रभावित हुए हैं। नगालैंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा से सबसे अधिक मोन जिला प्रभावित हुआ है, जहां भूस्खलन में नौ लोगों की मौत हुई है। इनमें से पांच लोग मोन शहर के शांथम वार्ड में मारे गये हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नागिनीमोरा में अचानक आयी बाढ़ में बहे चार लोगों को बचा लिया गया है। इसके मुताबिक चार लोग अब भी लापता हैं और उनकी तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है।

एनआरसी अद्यतन मामला

अपील प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायालय का केंद्र व अन्य को नोटिस

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें असम में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर किये गये लोगों के लिए अपील प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने का अनुरोध किया गया है। असम राज्य जमीयत उलेमा की ओर से दायर याचिका पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को (प्रकाशित एनआरसी से) बाहर किया गया है, उनके लिए अपील का प्रावधान है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक अलग मामला उच्चतम न्यायालय में पहले से लंबित है। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी किया जाए। न्यायालय ने इस याचिका को पहले से लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया। न्यायालय ने केंद्र और अन्य पक्षों, जिनमें असम सरकार और राज्य समन्वयक का कार्यालय भी शामिल है, से जवाब मांगा है। असम के वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करने वाली अद्यतन एनआरसी 31 अगस्त 2019 को जारी की गयी थी। इस प्रक्रिया में 19 लाख से अधिक आवेदकों के नागरिकता के दावों को खारिज कर दिया गया। एनआरसी राज्य समन्वयक कार्यालय के एक बयान के अनुसार कुल 3,30,27,661 (3.3 करोड़) लोगों ने एनआरसी में शामिल किए जाने के लिए आवेदन किया था। इनमें से 3,11,21,004 (3.1 करोड़) लोगों के नाम दस्तावेज में शामिल किये गये, जबकि 19,06,657 (19.06 लाख) लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया। अपनी याचिका में असम राज्य जमीयत शेष पृष्ठ आठ पर

सीएम ने खारिज की विपक्ष की मांग, कहा

बाढ़ के बावजूद स्थगित नहीं होगा विस का बजट सत्र

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। असम के ऊपरी हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने के बावजूद राज्य सरकार ने असम विधानसभा के जारी बजट सत्र को स्थगित न करने का फैसला किया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के पास रहने और राहत कार्यों में मदद के उद्देश्य से विपक्ष के नेता वाजेद अली चौधरी ने सत्र को स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य के सभी इलाकों में बाढ़ नहीं आयी है और केवल 12 से 13 विधानसभा क्षेत्रों में ही इसका असर है, इसलिए ऐसी स्थिति में चल रहे बजट सत्र को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता वाजेद अली चौधरी विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास को लिखित रूप से आवेदन सौंपकर सत्र स्थगित करने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों का इस संकट के समय में अपनी जनता के बीच मौजूद रहना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदार भी सदन में सरकार से बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर आधिकारिक बयान जारी करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाढ़ पीड़ितों को सरकारी दावों के मुताबिक जरूरी सुविधाएं और राहत सामग्रियां नहीं मिल पा रही हैं तथा पर्याप्त नावों की उपलब्धता न होने के कारण बचाव कार्यों में काफी देरी हो रही है।

सेना ने ऑपरेशन जल राहत के तहत 571 लोगों को सुरक्षित निकाला

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। राज्य में लगातार हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण उपजे भीषण बाढ़ के संकट से निपटने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत चलाकर अब तक 571 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में बढ़े जलस्तर ने ऊपरी असम के कई गांवों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है, जिससे घरों, कृषि योग्य भूमि और प्रमुख संपर्क मार्गों को भारी नुकसान पहुंचा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए सेना की स्पीयर कॉर्प्स ने 19 जुलाई से चौबीसों घंटे मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान की कमान संभाल रखी है। इस राहत कार्य के लिए 45 जवानों वाली तीन विशेष टीमों को सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट में तैनात किया शेष पृष्ठ आठ पर

नीट पेपर लीक पर बोले मोदी

युवाओं के भविष्य से नहीं होने देंगे खिलवाड़

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गयी है, ताकि कोई भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मोदी ने यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों की बैठक में यह बात कही। यह बैठक सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हजारों छात्रों द्वारा नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित संसद चलो मार्च के एक दिन बाद हुई। करीब एक घंटे तक चली मंगल मिलन नामक बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि प्रश्नपत्र लीक की खबर सामने आते ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिजिजू ने कहा कि साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो, इसलिए नीट की पुनर्परीक्षा को प्राथमिकता दी गयी, उसका सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया तथा परिणाम भी बिना विलंब किये घोषित कर दिये गये। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये गये हैं। रिजिजू के अनुसार प्रधानमंत्री ने राजग सांसदों से कहा कि प्रश्नपत्र लीक गिरोह में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक के दोषियों को देश के शीर्ष विधि विशेषज्ञों शेष पृष्ठ आठ पर

प्रधानमंत्री आवास के निकट कांग्रेस का धरना

बलपूर्वक उठाये गये राहुल, प्रियंका व अन्य नेता

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा राहुल गांधी से मिलकर बातचीत के बाद जब धरना समाप्त नहीं हुआ, शेष पृष्ठ आठ पर

अमिताभ ने सर्जरी व अस्पताल में भर्ती होने को लेकर किया पोस्ट

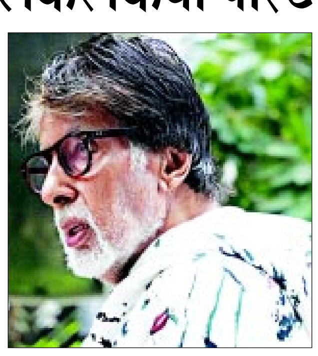

मुंबई, 21 जुलाई (भा)। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने आज अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी का जिक्र करते हुए एक पोस्ट साझा किया, लेकिन उन्होंने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी। बच्चन (83) ने कल देर रात अपने आधिकारिक ब्लॉग पर अस्पताल से घर लौटने को सबसे कठिन दौर बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सर्जरी के दौरान और विशेष गहन कक्ष (आईसीयू) में कुशल डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मियों की देखरेख में रहने के बाद छुट्टी मिली और घर वापसी हुई। शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक रूप से घर लौटने का यह दौर सबसे कठिन चरण होता है। बच्चन की पोस्ट से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह सामान्य तौर पर बात कर रहे थे या किसी खास व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभिनेता रविवार को अपने शेष पृष्ठ आठ पर

यूजीसी-नेट परीक्षा

छह प्रतिशत अभ्यर्थी ही सहायक प्राध्यापक पद के लिए योग्य : सरकार

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। सरकार ने संसद को बताया कि यूजीसी-नेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से छह प्रतिशत ही देशभर के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए योग्य होते हैं और इनमें से हर साल 11,750 अभ्यर्थियों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) दी जाती है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कल कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। थरूर ने नेट परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के आंकड़े मांगने के साथ यह भी पूछा था कि क्या सरकार जेआरएफ की संख्या बढ़ाने या पात्रता मानदंड में बदलाव करने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या मंत्रालय ने इस बात पर गौर शेष पृष्ठ आठ पर

पिछले पांच सालों में 1.42 लाख करोड़ की धोखाधड़ी की मिली जानकारी : सरकार

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने पिछले पांच वित्त वर्ष में 1.42 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जानकारी दी और इस दौरान 6,389 करोड़ रुपये वसूल किये गये। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी मिली है कि वह जानबूझकर चूक करने वालों के खिलाफ की गयी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी नहीं रखता है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2026 तक जानबूझकर शेष पृष्ठ आठ पर

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मप्र विस से यूसीसी विधेयक पारित

भोपाल, 21 जुलाई (भा)। विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों के भारी हंगामे के बीच मध्यप्रदेश विधानसभा ने आज मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि आज विधानसभा में स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद तीन तलाक या हलाला से जुड़े मामले अपराध की श्रेणी में आएंगे, एक से अधिक शादी शेष पृष्ठ आठ पर

गुफ्त-गू

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के आचरण पर उठाये सवाल

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी के आचरण पर आज सवाल उठाये और सुझाव दिया कि वह आत्मसमर्पण कर मुकदमे का सामना करे। मध्यप्रदेश के इंदौर की रहनेवाली सोनम रघुवंशी को उसके कारोबारी पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में पिछले वर्ष जून में गिरफ्तार किया गया था। दंपति 23 मई, 2025 को मेघालय के सोहरा क्षेत्र में घूमने के दौरान लापता हो गया था। बाद में दो जून, 2025 को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ था। पुलिस का आरोप है कि सोनम ने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ सोनम को दी गयी जमानत को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने सोनम से सवाल किया कि आप अपने आचरण पर क्या स्पष्टीकरण देंगी? पुलिस का मामला यह है कि आप अपने पति के साथ उस स्थान पर गयी थीं। घटना वहीं हुई, जहां उन पर हमला हुआ और उनकी मृत्यु हो गयी। इसके बाद आपने क्या किया? यही मुख्य प्रश्न है। दूसरा, गिरफ्तारी के आधार को लेकर क्या आपने शुरुआती स्तर पर ही आपत्ति उठायी थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह या तो मामले के गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करेगा या फिर सोनम को आत्मसमर्पण कर मुकदमे का सामना करने का निर्देश देगा। न्यायमूर्ति सुंदरेश ने सोनम की ओर से पेश वकील से कहा कि हम यह इसलिए कह रहे हैं, ताकि आपको अचानक स्थिति का सामना न करना पड़े और साथ ही आप हमारे रुख को भी समझ सकें। आप निर्देश लेकर हमारे समक्ष वापस आइए। सुनवाई शेष पृष्ठ आठ पर

राजा रघुवंशी हत्याकांड

डोभाल मिले सऊदी अरब के विदेश मंत्री से

दुबई, 21 जुलाई (भा)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान से मुलाकात की और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने तथा समुद्री मार्गों की सुरक्षा सहित क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। डोभाल की यह यात्रा ऐसे समय हुई है, जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है तथा अमेरिका-ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों तथा ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाएं बनी हुई हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के अनुसार डोभाल ने कल रियाद में शहजादे फैसल शेष पृष्ठ आठ पर

आवास क्षेत्र में पहली छमाही में संस्थागत निवेश 85% घटकर 15.4 करोड़ डॉलर

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। भारत के आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश चालू कैलेंडर साल की पहली छमाही (जनवरी-जून) के दौरान 85 प्रतिशत घटकर 15.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह गया। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड ने यह जानकारी दी है। कंपनी ने आज भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश से जुड़े आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 2026 की पहली छमाही में कुल निवेश छह प्रतिशत बढ़कर 3.46 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3.26 अरब अमेरिकी डॉलर था। रिपोर्ट के अनुसार निवेश में यह सीमित वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू निवेशकों की मजबूत भागीदारी के कारण हुई। परिसंपत्ति वर्गों में कार्यालय और डेटा सेंटर परियोजनाओं को सबसे अधिक निवेश प्राप्त हुआ। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी-जून, 2026 के दौरान आवास क्षेत्र में संस्थागत निवेश 85 प्रतिशत घटकर 15.36 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह गया, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 101.99 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। खुदरा रियल एस्टेट क्षेत्र में भी निवेश 54.24 करोड़ अमेरिकी डॉलर से घटकर 16.15 करोड़ डॉलर रह गया। वहीं कार्यालय क्षेत्र में निवेश दोगुने से अधिक होकर 197.07 करोड़ डॉलर रहा जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 72.95 करोड़ शेष पृष्ठ आठ पर

पेज : 6 सीजेपी के संसद मार्च से सुलगते सवाल व राजनीतिक निहितार्थ

पेज : 8 स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी करने में कुछ भी गलत नहीं

पेज : 9 टोंक में शराब की दुकान में घुसकर तेंदुए का हमला, तीन घायल

प्रातः खबर
गुवाहाटी, बुधवार, 22 जुलाई, 2026

असम में उच्च शिक्षा का नया अध्याय

मुख्यमंत्री ने आईआईएम गुवाहाटी के पहले एमबीए सत्र का किया शुभारंभ

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज कामरूप जिले के बोंगोरा स्थित प्रौद्योगिकी नगर में बने अस्थायी परिसर में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) गुवाहाटी के पहले व्यावसायिक प्रबंध स्नातकोत्तर (एमबीए) दल (202628) का उद्घाटन किया। यह असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। इस पहले दल में देश के 18 अलग-अलग राज्यों से आये 52 विद्यार्थी शामिल हैं। यह संस्थान वर्तमान में आईआईएम अहमदाबाद के मार्गदर्शन में अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू कर रहा है। बाद में इसे पलाशबाड़ी राजस्व क्षेत्र के मोराभिटा और दीघलकुची गांवों में 574 बीघा भूमि पर बन रहे इसके स्थायी परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य अगले तीन वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इसे असम की शैक्षिक यात्रा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने प्रथम दल के विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आईआईएम गुवाहाटी के शुभारंभ के साथ ही राज्य में विश्वस्तरीय प्रबंध शिक्षा का नया अध्याय शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस संस्थान की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मई 2022 में पहला पत्र भेजा था, जिसके बाद अप्रैल 2024 में सैद्धांतिक मंजूरी और अगस्त 2025 में केंद्रीय

मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी मिली। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश में केवल 13 आईआईएम थे, जो अब बढ़कर 22 हो गये हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण प्रबंध शिक्षा की पहुंच देश के हर कोने तक हुई है। असम सरकार ने शैक्षणिक गतिविधियों को बिना किसी देरी के शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी नगर में लगभग 39 करोड़ रुपये के निवेश से एक आधुनिक अस्थायी परिसर तैयार किया है। इस परिसर में आधुनिक व्याख्यान कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय, आचार्य आवास और तीन छात्रवास भवन बनाये गये हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को आईआईएम गुवाहाटी के शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन किया था, जिसके बाद यहां कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ और अब महज पांच महीनों में इसका मुख्य प्रबंध कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आईआईटी गुवाहाटी, एम्स गुवाहाटी, ट्रिपल आईटी, नाइपर और आगामी राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ आईआईएम गुवाहाटी के जुड़ने से राज्य का राष्ट्रीय संस्थानों का ढांचा बेहद मजबूत हुआ है। उन्होंने अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करने और राज्य के हित में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। मुख्य प्रबंध कार्यक्रम के उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नगर में डिजिटल प्रारूप एवं त्रि-आयामी मुद्रण उत्कृष्ट केंद्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की पीएम-डिवाइन योजना के तहत 53.84 करोड़ रुपये की लागत से बने इस केंद्र को एम्ट्रॉन द्वारा पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के सहयोग से लागू किया गया है। यह केंद्र स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, तेल और गैस, कृषि जैसे क्षेत्रों में त्रि-आयामी मुद्रण और डिजिटल प्रारूप तकनीकों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पलाशबाड़ी में सह-जिला आयुक्त कार्यालय के नये एकीकृत भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रशासनिक परिसर में सह-जिला आयुक्त कार्यालय, राजस्व क्षेत्र कार्यालय, कोषारू कार्यालय और उप-पंजीयक कार्यालय एक ही छत के नीचे आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को नागरिक सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इन कार्यक्रमों में शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगू, विधायक हिमांग्शु शेखर वैश्य, आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक प्रो. भारत भास्कर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा पाक शरीफ व मुनीर से करेगा बातचीत

इस्लामाबाद, 21 जुलाई (भा)। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी के नेतृत्व में देश का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा है, जहां वह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत करेगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने उनके निमंत्रण पर कल शाम इस्लामाबाद पहुंचे मोमेनी का स्वागत किया। मोमेनी ने यादगार-ए-शुहदा पर पुष्पचक्र अर्पित किया। इस दौरान, संघीय कांस्टेबुलरी के एक दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मोमेनी ने इस्लामाबाद में जीरो प्वॉइंट के पास स्थित पहाड़ी क्षेत्र शकरपरियां पार्क का भी दौरा किया, जहां से उन्हें शहर का दिलकश नजारा देखने को मिला। पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल ने अपनी खबर में बताया कि इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान मोमेनी प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर से मिलेंगे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका और ईरान के एक-दूसरे के खिलाफ फिर से हमले शुरू करने से पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ गये हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान सहित अन्य मध्यस्थों ने हमलों को रोकने और दोनों पक्षों के बीच बातचीत फिर से शुरू कराने के लिए पर्दे के पीछे की अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध-विराम के लिए मध्यस्थता की थी। वह दोनों देशों के बीच पिछले महीने हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को विफल होने से रोकने की कोशिशों में जुटा है। यह एमओयू 14-सूत्रीय एक अंतरिम शांति समझौता है, जिसका मकसद ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को खत्म करना है।

पंचांग

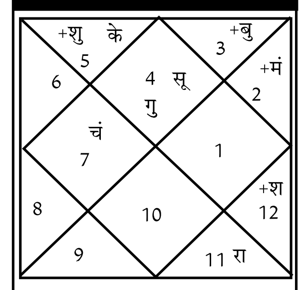

तिथि संवत: आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी। विक्रम संवत 2083 शाके 1948, सूर्य दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, नव सवंत्सर (रौद्र) तारीख 22 जुलाई बुधवार।
सूर्योदयकालीन नक्षत्र : स्वाति।
योग :- साध्य। करण :- बालव सायंकाल 6.06 तक तदुपरांत कौलव करण रहेगा।
ग्रह विचार : (प्रातः 4.41) सूर्य-कर्क, चंद्र-तुला, मंगल-वृष, बुध-मिथुन, गुरु-कर्क, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुंभ, केतु-सिंह राशि में स्थित है।
राहुकाल : दोपहर 12.00 बजे से 1.30 बजे तक रहेगा।
सूर्योदय : 4.41 बजे सूर्यास्त 6.16 बजे।

ज्योतिर्विद विकास तिवाड़ी
गुवाहाटी मो.9529781915।

गिरिडीह में 15 मामलों में वांछित महिला माओवादी ने किया आत्मसमर्पण

गिरिडीह, 21 जुलाई (भा)। झारखंड के गिरिडीह जिले में 15 मामलों में वांछित प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) की एरिया कमेटी सदस्य अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक बिमल कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि किस्कू ने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नयी दिशा, एक नयी पहल से प्रभावित होकर हथियार डाला। वह 2009 से माओवादी गतिविधियों में सक्रिय थी और 2017 में संगठन की एरिया कमेटी सदस्य बनायी गयी थी। उन्होंने बताया कि किस्कू सुरक्षा बलों पर हमलों, हथियारों की आपूर्ति समेत माओवादी गतिविधियों से जुड़े 15 मामलों में वांछित थी। एसपी ने अन्य माओवादियों से भी पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण करने, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी। किस्कू ने आत्मसमर्पण के बाद कहा कि उसे एहसास हो गया है कि वह गलत रास्ते पर थी। उसने अन्य माओवादियों से भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की।

कोई भी प्रदर्शनकारी हिरासत में नहीं : दिल्ली पुलिस

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। दिल्ली पुलिस ने आज कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च का कोई भी प्रदर्शनकारी अब हिरासत में नहीं है। इससे पहले कॉजपा ने दावा किया था कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी अब भी पुलिस हिरासत में हैं, लेकिन बाद में घोषणा की कि उसके सभी समर्थकों को रिहा कर दिया गया है। पुलिस का यह बयान तब आया जब सीजेपी ने एलान किया कि प्रदर्शनकारियों को रिहा न किये जाने पर रात 8 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस ने लोगों को असत्यापित सामग्री साझा या प्रसारित न करने की सलाह देते हुए कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति हिरासत में नहीं है। इससे पहले, सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने बर्बर बल का उपयोग करने के बाद सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था और दावा किया था कि वकीलों को उनसे मिलने या हिरासत में लिए गये लोगों की पूरी सूची नहीं दी जा रही है। हालांकि, बाद में एक्स पर पोस्ट में दास ने कहा कि संगठन के वकीलों ने उन्हें सूचित किया है कि हिरासत में लिए गये सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है।

अलीगढ़ के एक होटल में एक नाबालिग से दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार

अलीगढ़, 21 जुलाई (भा)। अलीगढ़ के एक होटल में 15 साल की एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कल देर शाम यह वारदात हुई, जिसके बाद मुख्य आरोपी और होटल के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि लड़की के परिवार की शिकायत पर बन्नादेवी थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि झूठा बहाना बनाकर लड़की को होटल में बुलाया गया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी और होटल के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उन पर पोक्सो की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। असम और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार ने त्वरित और प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मीता नाथ बोरा ने जानकारी दी कि मौसम विभाग द्वारा भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी के बीच सरकार ने आपदा तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री और विधायक प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति को संभाल रहे हैं। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने भी सभी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरकर राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करने का आह्वान किया है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एएसडीएमए, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए 101 राहत शिविर और वितरण केंद्र शुरू किए हैं, जिनमें तिनसुकिया, शिवसागर, जोरहाट, चराइदेव, डिब्रुगढ़ और गोलाघाट प्रमुख हैं। वर्तमान में 9,606 लोग इन सरकारी शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि शिविरों से बाहर रह रहे 34,905 लोगों तक सीधे राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है, जो साफ पानी, दवाइयां और महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों के लिए पोषण सामग्री सुनिश्चित कर रही हैं। किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना को भी स्टैंडबाय पर रखा गया है। सरकार ने इस आपदा में 10 लोगों की दुखद मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्षों के जरिये हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और नुकसान का आकलन कर सड़कों व बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक अंतिम प्रभावित व्यक्ति तक मदद नहीं पहुंच जाती, तब तक राहत और बचाव अभियान पूरी तीव्रता से जारी रहेगा।

अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हरजीत सिंह ग्रेवाल ने आज कार्यभार संभाल लिया। आधिकारिक बयान के अनुसार, उनकी नियुक्ति अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण, समावेशन, सशक्तीकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में आयोग की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। बयान में कहा गया कि सार्वजनिक जीवन और संगठनात्मक नेतृत्व का व्यापक अनुभव रखने वाले ग्रेवाल ने सामाजिक सद्भाव, जनकल्याण और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम किया है।

रेलवे अधिसूचना
केंद्रीय अस्पताल, मालीगांव में
मानद विजिटिंग स्पेशलिस्ट की सूचीबद्धता

सं. H/207/6(B)/Vol III/2023 — दिनांक: 07-07-2026

[illegible]

नियम एवं शर्तें:
(1) [illegible]
(2) उम्र सीमा/आयु: [illegible]
(3) [illegible]

घंटे	स्पेशलिस्ट (रु)	सुपर स्पेशलिस्ट (रु)
सप्ताह में 6 दिन	रु.67,000/- प्रतिमाह	रु.82,000/- प्रतिमाह
प्रत्येक दिन 24 घंटे	रु.1,00,000/- प्रतिमाह	रु.1,23,000/- प्रतिमाह
सप्ताह में 4 दिन	रु.41,000/- प्रतिमाह	रु.51,000/- प्रतिमाह
प्रत्येक दिन 24 घंटे	रु.61,000/- प्रतिमाह	रु.77,000/- प्रतिमाह
सप्ताह में 2 दिन	रु.20,000/- प्रतिमाह	रु.25,000/- प्रतिमाह
प्रत्येक दिन 24 घंटे	रु.30,000/- प्रतिमाह	रु.38,000/- प्रतिमाह

(4) [illegible] www.nfr.indianrailways.gov.in [illegible]
(5) [illegible]
(6) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन है।

चिकित्सा निदेशक/केंद्रीय अस्पताल, मालीगांव
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के हितों का रखा जाएगा ध्यान : ढिल्लों

चंडीगढ़, 21 जुलाई (भा)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध कर रहे किसानों से आज नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि उनके हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यहां एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि धान, गेहूं, दाल, दूध और अन्य कृषि उत्पादों को प्रस्तावित व्यापार समझौते के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया गया और केवल बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए किसानों के गुमराह होने या अफवाहों का शिकार होने की कोई वजह नहीं है। ढिल्लों का यह बयान ऐसे समय आया है, जब किसानों ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ दिल्ली में किसान महापंचायत विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनायी थी। हालांकि, पंजाब से राष्ट्रीय राजधानी की ओर जा रहे किसानों को आज शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। हरियाणा पुलिस ने पड़ोसी राज्य में प्रवेश करने वाली जगह पर अवरोधक और सीमेंट के ढांचे खड़े कर दिये हैं। भाजपा नेता ने राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप)और मुख्य विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दलों ने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की है और लगातार दुष्प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि इसके उलट भाजपा हमेशा चट्टान की तरह किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रही है और भविष्य में भी ऐसा ही करती रहेगी। ढिल्लों ने पंजाब के सभी किसानों से अपील की कि वे गलत जानकारी और दुष्प्रचार से सावधान रहें और प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान संगठन को कोई संदेह या आशंका है, तो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए उनका स्वागत है।

परीक्षा धांधली पर प्रदेश कांग्रेस का राजभवन घेराव

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन के सामने एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों द्वारा छात्रों के समर्थन में प्रधानमंत्री आवास के समक्ष दिये गये धरने के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता वाजेद अली चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजभवन घेराव कार्यक्रम को अंजाम दिया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा धांधली की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा कराने तथा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर को अविलंब वापस लेने की पुरजोर मांग की गयी। इस दौरान राजभवन की ओर बढ़ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर रोकने का प्रयास किया, जिससे स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गयी। पुलिस के कड़े विरोध के बावजूद विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही बैठकर भाजपा सरकार के खिलाफ धरना दिया तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में विधानसभा में विपक्ष के उपनेता डॉ. जयप्रकाश दास, विधायक जाकिर हुसैन सिकदर, आफताबुद्दीन मुल्ला, अमीनुल हक लश्कर, जुबेर अनम, तंजील हुसैन समेत कई प्रमुख जन प्रतिनिधि शामिल रहे। इनके अलावा पार्टी के प्रशासनिक महासचिव विपुल गोगोई, संगठनात्मक महासचिव रामन्ना बरुवा, मीडिया विभाग के अध्यक्ष वेदव्रत बोरा, सेवा दल के अध्यक्ष दीप बायन, शांतनु बोरा, अरुण तिवारी, महानगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वपन दास, प्रवक्ता विदिशा नेउग और एनएसयूआई अध्यक्ष कौशिक कश्यप सहित सैकड़ों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

आरपीएफ की मदद से 19 बीमार यात्रियों को मिला सहारा

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) का रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब/आरपीएफ) यात्रा के दौरान अस्वस्थ होने वाले यात्रियों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर यात्री सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का निरंतर परिचय दे रहा है। रेलवे अधिकारियों और स्थानीय चिकित्सा संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय के जरिए आरपीएफ यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति में यात्रियों को तत्काल राहत और उपचार मिल सके। पूसीरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने मंगलवार को बताया कि 17 जुलाई को न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने ट्रेन संख्या 15607 तिरुवनंतपुरम सेंट्रलसिलचर अरुणई एक्सप्रेस से यात्रा कर रही एक महिला यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई। प्राथमिक कार्रवाई के तहत उन्हें एम्बुलेंस से न्यू जलपाईगुड़ी स्थित रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें एक उच्च स्तरीय चिकित्सा केंद्र में रेफर कर दिया गया। इसी दिन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ट्रेन संख्या 13174 सबरूमसियालदह कंचनजंघा एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री को भी समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई। स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीपीआरओ ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आरपीएफ लगातार सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। चिकित्सा आपात स्थिति की सूचना मिलते ही आरपीएफ के जवान रेलवे चिकित्सा अधिकारियों, स्टेशन प्रशासन और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल राहत कार्य शुरू कर देते हैं। उन्होंने बताया कि जून 2026 के दौरान पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र में कुल 12 यात्रियों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। वहीं जुलाई 2026 में अब तक सात यात्रियों को आपात स्थिति में तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा चुका है। यह आंकड़े यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति आरपीएफ की त्वरित प्रतिक्रिया तथा मानवीय सेवा की भावना को दर्शाते हैं। पूसीरे ने कहा कि वह सुरक्षित, सुगम और यात्री-अनुकूल रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रेलवे चिकित्सा अधिकारियों और अन्य विभागों के साथ समन्वित प्रयासों के माध्यम से आरपीएफ चिकित्सा आपात स्थितियों में लगातार त्वरित कार्रवाई कर रही है। इससे यात्रियों का भरोसा मजबूत होने के साथ-साथ भारतीय रेल की संवेदनशील और मानवीय कार्यशैली भी परिलक्षित होती है।

महत्वपूर्ण अपडेट
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

विशेष रेल सेवा

तिनसुकिया मंडल में जलभराव के कारण रेल परिचालन में उत्पन्न परिस्थितियों से फँसे हुए यात्रियों की सुविधा हेतु

रेल सं.	से-तक	सेवा की तारीख	प्रस्थान	आगमन
07641	लामडिंग-मरियाणि	25-07-2026 तक	08.30	13.30
07642	मरियाणि-लामडिंग	25-07-2026 तक	14.00	19.00
07643	लामडिंग-मरियाणि	25-07-2026 तक	20.00	01.00
07644	मरियाणि-लामडिंग	26-07-2026 तक	01.30	06.30
05832	रंगिया-मरियाणि	29-07-2026 तक (25-07-2026 को छोड़कर)	07.20	17.00
05831	मरियाणि-रंगिया	29-07-2026 तक (25-07-2026 को छोड़कर)	18.00	03.20

टिप्पणी:
स्टॉपेजों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया एनटीईएस (राष्ट्रीय रेल पूछताछ प्रणाली) देखें।

हमसे जुड़ें / हमें फॉलो करें:

स्वत्वाधिकारी प्रातः खबर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, खबर बिल्डिंग, दूसरा तल्ला, साइकिल फैक्ट्री, कालापहाड़, गुवाहाटी- 781016 के लिए **श्याम सुंदर लाटा** द्वारा प्रकाशित तथा उनके लिए पीजी इंडिया लिमिटेड, मिनी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, कालापहाड़, गुवाहाटी-16 (असम) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
E-mail : pratahkhabar5@gmail.com, pratah_khabar@yahoo.com, **दूरभाष+फैक्स** : 0361-2492131, **मो. :** 091270-70355, **जोरहाट कार्यालय** : 0376-2370042, **फैक्स :** 0376-2370043, **E-mail :** pkhabarjrt@gmail.com
एडिटर इन चीफ : चंद्रप्रकाश शर्मा
*प्रकाशन से उत्पन्न सभी विवाद गुवाहाटी न्यायालय के अधीन।
संपादक : परमेश्वर सिंह

नमस्कार गुवाहाटी

मंगलवाणी

जीवन में सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से होता है।

- श्री कृष्ण

प्रातः खबर

बुधवार, 22 जुलाई, 2026

मौसम

अधिकतम 32

न्यूनतम 25

Ph. : 2548109 2730431

L. GOPAL JEWELLERS

9-11-14, Kuber A.C. Market Guwahati - 781001

शुद्ध चांदी के बर्तनों एवं शुद्ध चांदी की सिल्ली व चांदी के सिक्कों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान

22/22 KDM Gold Jewellery, Hallmark Gold Jewellery Branded Diamond Jewellery.

0361-2601385 9678211156

D. M. Jeweller's

(As You Like We are)

7/8 (L) Akram's Business Fancy Bazar, Guwahati-1

शुद्ध सील चांदी के बर्तन एवं असली सिक्कों का प्रतिष्ठित स्थान

We also deal in 22/22 KDM hallmark Jewelleries

सावन मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक

दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। कामरूप महानगर जिला आयुक्त के सभागार में आज अतिरिक्त जिला आयुक्त हेमांग नवीश की अध्यक्षता में सावन मेला (बोल बम) के सुचारू आयोजन को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में उप-पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) मंटू ठाकुरीया, संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक संजीव कुमार सैकिया, पूर्व, पश्चिम और मध्य गुवाहाटी के उप-पुलिस आयुक्त, दिसपुर राजस्व चक्र अधिकारी, कामरूप महानगर जिले के सहायक आयुक्त, गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण, गुवाहाटी नगर निगम और आबकारी निरीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा वशिष्ठ मंदिर और सुकलेश्वर देवालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अतिरिक्त जिला आयुक्त हेमांग नवीश ने सावन मेले को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए

आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मंदिरों में स्वयंसेवकों की नियुक्ति करने, एपीडीसीएल द्वारा मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था करने तथा शौचालय सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पामही स्थित भीमाशंकर मंदिर में भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा, भीमाशंकर और वशिष्ठ मंदिर क्षेत्रों में जंगली हाथियों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि आगामी 29 जुलाई से शुरू होने वाली यह बोल बम यात्रा 27 अगस्त को समाप्त होगी। इस दौरान 29 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त और 27 अगस्त को श्रद्धालु बोल बम का पावन पर्व मनाएंगे। कामरूप महानगर जिला प्रशासन ने पवित्र सावन मेले को शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आयोजित करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। बैठक के दौरान मंदिर समितियों के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं से भी प्रशासन को अवगत कराया।

कृत्रिम बाढ़ से राहत के लिए जमीनी स्तर पर पहल

मंत्री ने अधिकारियों के साथ किया प्रभावित इलाकों का दौरा

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। कृत्रिम बाढ़ की समस्या से निपटना गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी सिलसिले में राज्य के शहरी विकास एवं आवास मामलों के मंत्री कौशिक राय ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ गुवाहाटी के जलभराव से प्रभावित विभिन्न इलाकों का व्यापक दौरा किया। इस दौरान न्यू गुवाहाटी के विधायक दिप्लू रंजन शर्मा, जीएमसी के मेयर मृगेन शरणिया, एमआईसी सदस्य असीम सैकिया, आयुक्त चिन्मय प्रकाश फुकन और विभागीय इंजीनियरों के साथ टीम ने वशिष्ठ, लताकाटा, पातरकुची, खानापाड़ा, कोइनाधारा, लास्ट गेट, बरबाड़ी, शिलसांको, जुरीपार, छहमाइल, सिल्ट ट्रैप और ज्योति-विष्णु प्रेक्षागृह के पास के क्षेत्रों का जायजा लिया। दौरे के दौरान मंत्री और अधिकारियों की टीम ने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और जमीनी स्थिति का आकलन किया। इसके साथ ही मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जल निकासी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, चल रहे कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने और इसमें तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। जीएमसी और राज्य सरकार आम नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा और एक आपदा-रोधी गुवाहाटी के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और जनसहयोग के माध्यम से कृत्रिम बाढ़ का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

चोरी के मामले में नाबालिग धरायी

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। बिरूबाड़ी आउटपोस्ट की टीम ने चोरी के मामले में एक नाबालिग को पकड़ा। उसके पास से दो चोरी की स्कूटी बरामद की। नाबालिग को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए किशोर निरोध केंद्र भेज दिया गया है।

चोरी की साइकिल समेत एक धराया

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। गीतानगर पुलिस ने अनिल नगर में दर्ज साइकिल चोरी के मामले में एक आरोपी रकीबुल अली (20) को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की गयी साइकिल बरामद की गयी। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

दो चोर चढ़े पुलिस के हत्थे

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। वशिष्ठ पुलिस ने मंदिरों में चोरी और सेंधमारी के कई मामलों में वांछित दो चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजीबुल इस्लाम (22), सेमिम अली (23) के रूप में की गयी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5,049 के सिक्के तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

चोरी की मोटरसाइकिल समेत एक बंदी

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। दिसपुर पुलिस ने जयानगर से चोरी हुई रॉयल एनफील्ड हंटर को महज छह घंटे के भीतर बरामद कर लिया और इस मामले में सोनापुर निवासी मनुय राभा (24) को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक मास्टर चाबी भी बरामद की गयी। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मूक अभिनय के जरिये जनगणना 2027 को लेकर नागरिकों को किया गया जागरूक

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। शब्दों से ज्यादा असरदार काम होते हैं की कहावत को चरितार्थ करते हुए जनगणना 2027 के सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के तहत नगर केंद्र व्यापार भवन में एक आकर्षक मूक अभिनय प्रस्तुत किया गया। इस कलात्मक प्रदर्शन के जरिये आम नागरिकों को जनगणना में अपनी सक्रिय भागीदारी का महत्व समझाया गया। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश प्रमुखता से दिया गया कि एक मजबूत, समृद्ध और सूचित भारत के निर्माण में हर एक नागरिक की गिनती और उनका दिया गया हर उत्तर बेहद मायने रखता है। इसके साथ ही जनगणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों के लिये भी सख्त

हिदायत जारी की गयी है। जनगणना 2027 के दायित्व में तैनात कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का अवकाश (आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, बाल देखभाल अवकाश आदि) प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जनगणना अधिनियम 1948 का सख्ती से पालन करना पूरी तरह अनिवार्य होगा।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी ने गुवाहाटी जोन का किया दौरा

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपने प्रबंध निदेशक की पहली यात्रा के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कुमार ने गुवाहाटी जोन का दौरा किया। पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए बैंक की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पूर्वी क्षेत्र और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करता है। विकास यात्रा के हिस्से के रूप में कल्याण कुमार ने ग्राहकों, हितधारकों, कर्मचारियों के साथ बातचीत की। मीडिया को संबोधित करते हुए कल्याण कुमार ने बैंक की प्रमुख रणनीतिक पहलों पर प्रकाश डाला। ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, व्यापार वृद्धि को मजबूत करने, एमएसएमई को समर्थन देने, कृषि, स्टार्टअप, महिला उद्यमी और क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास। इस अवसर पर बोलते हुए कल्याण कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यह भारत के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यक्तियों, व्यवसायों और को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ट्रैफिक व प्रदूषण कम करने का नया मॉडल किया विकसित

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने आईआईएम काशीपुर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सहयोग से ऑटोरिक्शा, मिनीबस और वैन जैसी अनौपचारिक परिवहन सेवाओं को शहरी परिवहन व्यवस्था में बेहतर ढंग से शामिल करने के लिए एक नया नीति-ढांचा विकसित किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार अनियमित परिवहन सेवाओं को नियंत्रित और व्यवस्थित करने से ट्रैफिक जाम, वायु प्रदूषण और असंगत सेवा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है। अध्ययन में सरकार, अनौपचारिक परिवहन संचालकों, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म और यात्रियों के बीच संबंधों का विश्लेषण किया गया। इसमें भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निजी वाहनों के प्रवेश पर शुल्क, परिवहन संचालकों को वित्तीय सहायता और यात्रियों को सब्सिडी जैसे विकल्पों का अध्ययन किया गया। शोधकर्ताओं के निष्कर्ष के अनुसार कंजेशन प्राइसिंग (भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शुल्क) और लक्षित सब्सिडी को एक साथ लागू करना किसी एक उपाय को अकेले लागू करने की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। इससे नियंत्रित अनौपचारिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और सड़कों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी महिला शाखा की कार्यकारिणी सभा संपन्न

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी महिला शाखा के आतिथ्य में 8 एवं 9 अगस्त को आयोजित होने जा रहे तेजस्विता महिला अधिवेशन की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी क्रम में आज शाखा की एक महत्वपूर्ण कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दो दिवसीय अधिवेशन के सभी सत्रों, कार्यक्रमों एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गयी। शाखा अध्यक्ष संतोष शर्मा के नेतृत्व में सभी सदस्याएं उत्साहपूर्वक अधिवेशन की तैयारियों में जुटी हुई हैं। कार्यकारिणी सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर अधिवेशन को सफल बनाने का उत्साह, उमंग और जोश स्पष्ट दिखाई दे रहा था।

स्वागत अध्यक्ष सरोज मित्तल एवं स्वागत मंत्री सरला काबरा ने सभी सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक अधिवेशन को पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे। सभा में शाखा मंत्री मंजू भंसाली एवं कोषाध्यक्ष शांति कुंडलिया की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यकारिणी सभा में बड़ी संख्या में सदस्याओं ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर 600 सदस्यों की डायरेक्टरी का भी भव्य विमोचन किया गया। इस डायरेक्टरी का संकलन लिजी कुंडलिया द्वारा किया गया, जिसके लिए उन्हें विशेष रूप से बधाई एवं शुभकामनाएं दी गयीं। कार्यक्रम में शाखा की उपाध्यक्ष रश्मि जैन का भी सम्मान किया गया। उन्हें दिगंबर महासभा महिला की अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। अंत में शाखा अध्यक्ष संतोष शर्मा ने सभी सदस्याओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग, समर्पण और टीम भावना से तेजस्विता अधिवेशन निश्चित रूप से ऐतिहासिक एवं सफल आयोजन सिद्ध होगा।

शंकरदेव शिशुकुंज में तीन दिनी ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का शुभारंभ

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। विद्या भारती से संबद्ध शिशु शिक्षा समिति, असम के अंतर्गत अंबिकागिरी नगर स्थित शंकरदेव शिशुकुंज में संगीत, अभिनय, नृत्य, चित्रकला आदि विषयों पर आधारित तीन दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन विद्या भारती पूर्व छात्र भारती की क्षेत्रीय संयोजिका, पार्षद तथा शंकरदेव शिशुकुंज की पूर्व छात्रा स्वप्ना देवी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा के विकास के लिए ऐसी कार्यशालाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। शिशु शिक्षा समिति, असम के प्रचार संयोजक मुकुटेश्वर गोस्वामी ने बताया कि

कार्यशाला के उद्देश्य पर शिशुकुंज की प्रधानाचार्य कमला गोस्वामी ने विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन आचार्य अनामिका डेका ने किया। कार्यशाला के प्रथम दिन के संगीत प्रशिक्षक के रूप में मालीगांव शंकरदेव शिशु निकेतन के आचार्य एवं प्रसिद्ध संगीतज्ञ मृणाल दास उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी सरल, मधुर एवं बाल-सुलभ शैली से 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विभिन्न बालगीत सिखाए। बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर वातावरण को आनंदमय बना दिया। इस अवसर पर स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र की पांच सहायिका शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 50 से अधिक छात्र-छात्राओं तथा उनके अभिभावकों की उपस्थिति रही। आचार्य भारती के तत्वावधान में आयोजित इस ग्रीष्मकालीन कार्यशाला के प्रथम दिवस का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इक्कीस वर्ष बाद बहन के घर पहुंचे मुनि विकास कुमार, भाव-विभोर हुआ परिवार

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। आचार्य महाश्रमण के सुशिष्य मुनि आनंद कुमार कालू एवं सहवर्ती मुनि विकास कुमार का का कल मंगल प्रवेश शैलेश-प्रियंका सेठिया के निवास पर हुआ। यह अवसर विशेष रूप से भावनाओं से ओत-प्रोत रहा, क्योंकि मुनि विकास कुमार दीक्षा के लगभग 21 वर्ष बाद अपनी संसार पक्षीय बहन प्रियंका सेठिया के निवास पर पधारे। संत मर्यादा के अनुरूप यह मिलन आध्यात्मिक गरिमा और आत्मीय भावनाओं का अद्भुत संगम बन गया। परिवारजनों ने श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के साथ दोनों संतों का भावपूर्ण स्वागत किया। इस अवसर पर सेठिया परिवार की बहनों ने भावपूर्ण स्वर में गीत प्रस्तुत कर सभी को भाव-विभोर कर दिया। ज्ञानशाला के बच्चों चेतना सेठिया, चिन्मय सेठिया, उत्कर्ष छाजेड़, हर्षित नाहटा एवं अर्पित नाहटा ने गीत की सुंदर प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में आध्यात्मिक उल्लास का संचार किया। मुनि विकास कुमार ने गीतिका की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। प्रियंका सेठिया की लंबे समय से यह हार्दिक भावना थी कि उनके निवास पर ऊं भिक्षु जय भिक्षु

के सामूहिक जाप का आयोजन हो। उनकी यह मनोकामना पूर्ण हुई। दोपहर 2 से 3 बजे तक आयोजित जाप में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। उल्लेखनीय है कि प्रियंका सेठिया के पिता चांदमल श्रीमाल एवं माता सोभाग (शोभा) देवी वर्तमान में जलालगढ़ में निवास करते हैं। दीक्षा से पूर्व मुनि विकास कुमार अपने संसार पक्षीय चाचा के परिवार के साथ जलालगढ़ में रहे थे, जहां भाई-बहनों के साथ उनका स्नेहपूर्ण पारिवारिक जीवन व्यतीत हुआ था। वर्षों बाद वही पारिवारिक स्मृतियां इस पावन अवसर पर पुनः सजीव हो उठी। इस अवसर पर अपने मंगल उद्बोधन में मुनि आनंद कुमार कालू ने कहा कि संसार के रिश्ते समय और परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं, किंतु धर्म और आत्मा का संबंध शाश्वत होता है। दीक्षा के पश्चात साधु का जीवन समता, संयम और समर्पण का जीवन बन जाता है। परिवार के प्रति आसक्ति नहीं, बल्कि समस्त समाज के प्रति आत्मीयता उसका लक्ष्य होती है।

मंत्री दैमारी ने निर्माणाधीन तामुलपुर मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण

नलबाड़ी, 21 जुलाई (ख.सं)। तामुलपुर क्षेत्र के लोगों के लिए राहत और खुशी की खबर है। निर्माणाधीन तामुलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का कार्य तेजी से प्रगति पर है। परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य भी निर्धारित समय के भीतर पूरा किए जाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक विश्वजीत दैमारी ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर का दौरा कर परियोजना की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यों की गुणवत्ता तथा गति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाये, ताकि क्षेत्र के लोगों को शीघ्र आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री विश्वजीत दैमारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी दो से तीन महीनों के भीतर शेष निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा निर्माणाधीन तामुलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा करेंगे और परियोजना की प्रगति का स्वयं निरीक्षण करेंगे। मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के बाद तामुलपुर तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही, यह संस्थान क्षेत्र के स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होने की उम्मीद है।

असमिया कवयित्री व लेखिका यशोदा कुंवर का निधन

विश्वनाथ, 21 जुलाई (ख.सं)। प्रसिद्ध असमिया कवयित्री, लेखिका और साहित्यिक व्यक्तित्व यशोदा कुंवर का आज सुबह विश्वनाथ जिले के गोहपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 84 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थीं। चारिदुआर कॉलेज की सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक कुंवर ने सुबह करीब 8.30 बजे अंतिम सांस ली। उन्होंने असमिया साहित्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और पत्रकार नगेन कुंवर की बड़ी बहन थीं। यशोदा कुंवर अखिल असम कवि सम्मेलन, लेखिका समारोह, असम साहित्य सभा और कवि कानन सहित कई साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़ी रही थी। सरल जीवन, सांस्कृतिक मूल्यों और साहित्य के प्रति समर्पण के लिए जानी जाने वाली यशोदा कुंवर के निधन से गोहपुर और असम के साहित्यिक जगत में शोक की लहर है।

बोकाखात के बन बागान चाय बागान प्राथमिक विद्यालय में स्थापित राहत शिविर में बच्चों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते मंत्री अतुल बोरा।

रंगिया में चोरों ने एसबीआई एटीएम को बनाया निशाना

रंगिया, 21 जुलाई (ख.सं)। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रंगिया के भूटान बस स्टैंड के समीप स्थित एसबीआई एटीएम का है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की कोशिश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलमेट पहनकर एटीएम में घुसे चोर ने सबसे पहले अपनी पहचान छिपाने के लिए अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर कीचड़ पोत दिया। इसके बाद अपने साथ लायी गयी लाठी से अन्य सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, चोर ने एटीएम के मॉनिटर को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि पूरी वारदात देर रात हुई। हालांकि, चोर एटीएम से नकदी निकालने में सफल हुए या नहीं, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बैंक अधिकारियों द्वारा एटीएम की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही रंगिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी है। उल्लेखनीय है कि लगातार सामने आ रही चोरी और चोरी के प्रयास की घटनाओं ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिये हैं। बहरहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

सिलचर में तीन भुवनेर बंगाली पुस्तक का विमोचन

सिलचर, 21 जुलाई (ख.सं)। पूर्व छात्र नेता और बराक के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप दत्ता रॉय द्वारा लिखित निबंधों की तीसरी पुस्तक तीन भुवनेर बंगाली का औपचारिक विमोचन सिलचर के एक होटल में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रूपम सामाजिक, संगस्थिका और क्रीड़ा संस्था के सदस्यों द्वारा गाये गये एक गीत से हुआ। कार्यक्रम का संचालन मनोज देब ने किया। इस कार्यक्रम में अनुभवी कवि-पत्रकार अतीन दास, अनुभवी पत्रकार हरन दे, शिक्षाविद हिलाल उद्दीन लस्कर, प्रख्यात पत्रकार विकास चक्रवर्ती, सामाजिक कार्यकर्ता शांतनु दास, सांस्कृतिक आयोजक निखिल पाल, व्यवसायी महावीर प्रसाद जैन और पुस्तक के लेखक प्रदीप दत्ता रॉय उपस्थित थे। वक्ताओं ने पुस्तक की विषयवस्तु, बंगाली समाज के इतिहास,

पहचान, भाषा और भविष्य पर विस्तार से चर्चा की। अतिन दास ने कहा कि 21 जुलाई बंगाली समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन दूसरा बराक भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भाषा शहीदों के बलिदानों का उचित मूल्यांकन और बंगाली भाषा के संरक्षण के लिए अधिक प्रभावी पहलों की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 19 मई, 1961 को सिलचर रेलवे स्टेशन पर पुलिस फायरिंग की घटना की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि छोटी-बड़ी हर तरह की किताबें समाज को विचारों की एक नयी दिशा दिखाती हैं। उनके अनुसार तीन भुवनेर बंगाली पुस्तक ने बंगाली समाज के विभिन्न संकटों, चुनौतियों और संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि समाज में एकता और आपसी सहयोग की कमी ही कई मौजूदा समस्याओं की जड़ है। विकास चक्रवर्ती ने पुस्तक को बंगाली समाज के वर्तमान और भविष्य पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। निखिल पाल ने अन्याय के खिलाफ लगातार मुखर रहने के लिए लेखक प्रदीप दत्ता रॉय की प्रशंसा की। सामाजिक कार्यकर्ता शांतनु दास ने भी लेखक के सामाजिक सेवा में योगदान का उल्लेख किया।

पुलिस चौकी से सटे बनिक ज्वेलर्स में चोरी

रंगिया, 21 जुलाई (ख.सं)। रंगिया के तुलसीबाड़ी पुलिस चौकी से सटे बनिक ज्वेलर्स में देर रात चोरों ने सीलिंग तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और लॉकर लेकर फरार हो गये। देर रात हुई सनसनीखेज चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए तपन बनिक के ज्वेलरी प्रतिष्ठान की सीलिंग तोड़कर दुकान में प्रवेश किया। इसके बाद सोने-चांदी के कीमती आभूषण, नकदी और यहां तक कि लॉकर भी लेकर फरार हो गये। पुलिस चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिस चौकी के ठीक बगल में ही चोर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे सकते हैं, तो आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश तेज कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने तुलसीबाड़ी बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त करने की मांग की है।

होली क्रॉस स्कूल प्रबंधन व शिकायतकर्ता आमने-सामने

सिलचर, 21 जुलाई (ख.सं)। सिलचर के होली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल को लेकर चल रहा विवाद करीब दो महीने बाद एक बार फिर गरमा गया है। स्कूल की प्राचार्य और संबंधित कक्षा शिक्षिका ने हाल ही में पत्रकार सम्मेलन कर अपने खिलाफ लगाये गये सभी आरोपों को निराधार बताया। इसके जवाब में शिकायतकर्ता छात्र के परिवार ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए स्कूल प्रबंधन के दावों पर कई सवाल उठाये हैं। परिवार का आरोप है कि यदि घटना के दिन ही स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर स्थिति स्पष्ट कर दी होती, तो विवाद इतना नहीं बढ़ता। परिवार के अनुसार उन्होंने शुरुआत में कानूनी कार्रवाई का रास्ता नहीं अपनाया था, बल्कि पहले स्कूल प्रबंधन की ओर से ही थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी। छात्र की मां ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें थाने बुलाकर फेसबुक पर साझा किया गया एक वीडियो हटाने के लिए कहा गया था। परिवार ने सवाल उठाया कि यदि वास्तव में कोई अनियमितता नहीं हुई थी, तो स्कूल प्रबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करने में करीब दो महीने क्यों लगे? वहीं स्कूल की प्राचार्य और कक्षा शिक्षिका का कहना है कि घटना के बाद वे मानसिक रूप से काफी परेशान थीं और कुछ दिनों तक अवकाश पर रही थीं। छात्र की मां का एक अन्य आरोप है कि थाने की घटना के अगले दिन उनके बेटे को करीब 45 मिनट तक कक्षा के बाहर खड़ा रखा गया और एक शिक्षिका ने उसके प्रति कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की। उनका कहना है कि इसके बाद ही परिवार ने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया। परिवार ने पिछले शुक्रवार को आयोजित स्कूल प्रबंधन के पत्रकार सम्मेलन में शिकायतकर्ता छात्र की पहचान कथित रूप से उजागर किए जाने पर भी आपत्ति जतायी है।

लमडिंग की पेयजल व्यवस्था पर उठे सवाल

लमडिंग, 21 जुलाई (ख.सं)। लमडिंग में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की गुणवत्ता को लेकर लोगों के बीच चिंता गहराती जा रही है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग की जलापूर्ति अवसंरचना के हालिया निरीक्षण में सामने आयी स्थिति ने स्थानीय नागरिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनके घरों तक पहुंचने वाला पेयजल निर्धारित स्वच्छता मानकों के अनुरूप है या नहीं। स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। जल शोधन संयंत्रों में पानी का उपचार किए जाने के साथ-साथ भंडारण टंकियों, पाइपलाइन और वितरण प्रणाली का नियमित रखरखाव भी अनिवार्य माना जाता है। यदि इन व्यवस्थाओं की समय-समय पर देखभाल नहीं की जाए, तो शुद्ध किया गया पानी भी दूषित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। मैदानी निरीक्षण के दौरान पीएचई विभाग के कार्यालय परिसर की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। परिसर में

चारों ओर उगी झाड़ियां, ऊंची घास और फैली हुई वनस्पतियां इस बात का संकेत दे रही थीं कि लंबे समय से साफ-सफाई और रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी सरकारी कार्यालय की ऐसी स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करती है। निरीक्षण के दौरान पश्चिम लमडिंग पंचायत के चार वार्डों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया। इन इलाकों में पानी को पहले फिल्ट्रेशन प्लांट में शुद्ध किया जाता है, इसके बाद ओवरहेड जलाशयों में संग्रहित कर पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। स्थानीय नागरिकों ने विशेष रूप से ओवरहेड जलाशयों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि इन जलाशयों की नियमित सफाई और रखरखाव होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी कारण लोगों के मन में यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि भंडारण के बाद भी पानी की गुणवत्ता पहले जैसी बनी रहती है या नहीं। निवासियों का कहना है कि केवल पानी को शुद्ध करना पर्याप्त नहीं है। यदि जल भंडारण और वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी तथा सफाई न हो, तो जल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ भी समय-समय पर यह चेतावनी देते रहे हैं कि जलाशयों और पाइपलाइन की नियमित सफाई नहीं होने पर उनमें गंदगी, तलछट तथा सूक्ष्मजीव पनप सकते हैं, जिससे जलजनित रोगों की संभावना बढ़ जाती है। राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। नयी परियोजनाएं शुरू की गयी हैं और जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास भी किए गए हैं। इसके बावजूद लमडिंग के अनेक नागरिकों का मानना है कि रखरखाव के स्तर पर अपेक्षित सुधार अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय के साथ सरकारें और अधिकारी बदलते रहे, लेकिन जलापूर्ति प्रणाली की देखरेख में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को नहीं मिला।

ढेकियाजुली में नाटक धुंआ का मंचन

ढेकियाजुली, 21 जुलाई (ख.सं)। सांस्कृतिक संस्था रनली ने गत 18 और 19जुलाई को ढेकियाजुली त्रिमूर्ति भवन प्रेक्षागृह में मंचन किया रफीकुल हुसैन का विख्यात नाटक धुंआ। नाट्यकार स्व. रफीकुल हुसैन की स्मृति में नाटक का मंचन किया गया। नाटक के दोनों दिन ढेकियाजुली शहर के साथ-साथ निकटवर्ती गांव के सैकड़ों लोगों ने इसका आनंद लिया। नाटक के प्रथम दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया विशिष्ट नाट्यकार, परिचालक पंकज ज्योति भुइयां और विशिष्ट अभिनेत्री तथा नाट्यकर्मी सिमी गोस्वामी ने। ठीक इसी क्रम मे नाटक के दूसरे दिन नाटक संध्या का उद्घाटन किया विशिष्ट अभिनेत्री, परिचालक तथा चिकित्सक डॉ. जाहानारा बेगम ने। भास्कर डेका द्वारा मंचित नाटक में रंजुल बरुवा, अरिंदम कुमार डेका, गौतम राजवंशी, मृदुल डेका, ध्रुवप्रसाद नाथ,बाबलू अंसारी, रिंटू सैकिया, बंदना कलिता, अर्पणा दास और ध्रुवज्योति दास ने अभिनय किया जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। रनली के अध्यक्ष रंजुल बरुवा और सचिव लिमाकृष्णा बोरा ने बताया कि नाटक के दोनों दिन रफीकुल हुसैन और जुबिन गर्ग की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गयी।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से पूर्व कोकराझाड़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

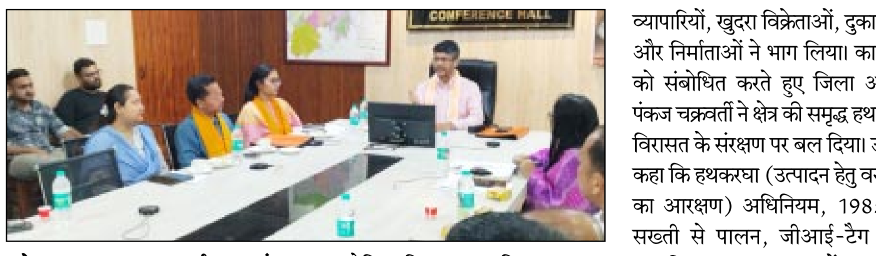

कोकराझाड़, 21 जुलाई (ख.सं)। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में कोकराझाड़ में आज हथकरघा अधिनियम, 1985 के प्रभावी क्रियान्वयन, असम एवं बोड़ोलैंड के जीआई (भौगोलिक संकेतक) पंजीकृत हथकरघा उत्पादों के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार तथा प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने में व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों एवं निर्माताओं की भूमिका पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला आयुक्त कार्यालय, कोकराझाड़ के सम्मेलन कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से हथकरघा एवं वस्त्र विभाग, बीटीसी तथा जिला प्रशासन, कोकराझाड़ ने आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आयुक्त पंकज चक्रवर्ती ने की। इसमें सहायक आयुक्तों, हथकरघा एवं वस्त्र विभाग के सहायक निदेशक सह प्रभारी निदेशक, विभागीय अधिकारियों तथा व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों और निर्माताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला आयुक्त पंकज चक्रवर्ती ने क्षेत्र की समृद्ध हथकरघा विरासत के संरक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का सख्ती से पालन, जीआई-टैग प्राप्त प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों का प्रचार तथा सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय समय की आवश्यकता है। उन्होंने व्यापारियों, निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं से स्थानीय बुनकरों के हितों और आजीविका की रक्षा करते हुए केवल असली हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने तथा पारदर्शी एवं टिकाऊ हथकरघा व्यवस्था के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया।

एनटीपीसी बंगाईगांव ने गोल्डन लंगूर संरक्षण में किया सहयोग

कोकराझाड़, 21 जुलाई (ख.सं)। पर्यावरण स्थिरता और जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए एनटीपीसी बंगाईगांव ने कोकराझाड़ जिले के नादंगिरी-बक्समारा-आमगुड़ी-नायकगांव-चकराशिला वन परिसर में कृत्रिम चंदवा पुलों की स्थापना करके लुप्तप्राय गोल्डन लंगूर की रक्षा के लिए एक अभिनव परियोजना का समर्थन किया। कोकराझाड़ में नादंगिरी-बक्समारा-आमगुड़ी-नायकगांव-चक्राशिला वन परिसर में ग्राम गलियारे के माध्यम से लुप्तप्राय गोल्डन लंगूर की आबादी को जोड़ने के लिए सड़क ओवरपास के रूप में कृत्रिम चंदवा पुलों की स्थापना शीर्षक वाली परियोजना को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एनटीपीसी बंगाईगांव द्वारा अपनी सतत विकास पहलों के तहत 10 लाख के वित्तीय सहयोग से कार्यान्वित किया गया था। यह पहल हाल्टुगाँव वन प्रभाग और पूर्वोत्तर भारत के प्राइमेट अनुसंधान केंद्र के सहयोग से कार्यान्वित की गयी थी, जिसमें गोल्डन लंगूर के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए संस्थागत समर्थन, वैज्ञानिक विशेषज्ञता और क्षेत्र-स्तरीय संरक्षण उपायों को एक साथ लाया गया था। स्वर्ण लंगूर (ट्रैकीपिथेकस गीई) विश्व के सबसे दुर्लभ प्राइमेट्स में से एक है और मुख्य रूप से पश्चिमी असम और पड़ोसी भूटान में पाया जाता है। यह प्रजाति आवास विखंडन, सिकुड़ते वन गलियारों और बढ़ते सड़क नेटवर्क से बढ़ते खतरों का सामना कर रही है। जैसे-जैसे वनों की ऊपरी परतें आपस में कटती जा रही हैं, वृक्षों पर रहने वाले ये प्राइमेट्स अक्सर जमीन पर उतरने और सड़कों को पार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे वे वाहनों की टक्कर, चोटों और अन्य मानव-जनित जोखिमों के शिकार हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, नादंगिरी-बक्समारा-आमगुड़ी-

नायकगांव-चक्राशिला वन क्षेत्र में रणनीतिक रूप से चिह्नित स्थानों पर छह कृत्रिम छत्र पुल स्थापित किए गए। ये हवाई पुल खंडित वृक्षों की छतरियों को जोड़ते हैं और सुनहरे लंगूरों को सड़क पर उतरे बिना वन क्षेत्रों के बीच सुरक्षित रूप से आने-जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। इस पहल से पर्यावासों की परस्पर संबद्धता में सुधार होने, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु का जोखिम कम होने और अलग-थलग वन क्षेत्रों के बीच गोल्डन लंगूरों की सुरक्षित आवाजाही में सहायता मिलने की उम्मीद है। बेहतर संबद्धता से अलग-अलग आबादी के बीच आनुवंशिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिल सकता है, जो इस प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व और पारिस्थितिक लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। वन्यजीवों की आवाजाही और कैनोपी पुलों के उपयोग का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए, चयनित स्थानों पर तीन कैमरा ट्रैप लगाये गये। यह निगरानी प्रणाली शोधकर्ताओं को लंगूरों की आवाजाही का दस्तावेजीकरण करने, व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करने, पुलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और भविष्य की योजना के लिए संरक्षण संबंधी डेटा तैयार करने में मदद करेगी। इस परियोजना में कॉरिडोर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर वन्यजीव जागरूकता और सड़क सुरक्षा संबंधी चार संकेत चिन्ह लगाना भी शामिल था।

Onyx®
high technology batteries
An ISO 9001 : 2015 Certified Company
SUPREME POWER INDUSTRIES
Mfg. of all types of Inverter, Automotive & E-Rick Batteries
Mariani Road, Cinnamara, Jorhat (Assam) 785008
E-mail : onyxbatteries@gmail.com
For Trade Enquiry Dial :
94350-52877/91018-74862
DEALER
JORHAT- 99546-01024, 98540-10510, 70026-10137, 94350-96629 NAGAON-94351-62696 LAKHIMPUR- 94351-82787 BORPATHAR-94357-42389 SARUPATHAR- 70020-37117 BOKAJAN- 94351-82777, 70026-02799, 75770-99894, 99545-87019, 70028-58905 AMGURI-73990-23273 SIVASAGAR- 99545-65426, 99545-55870, 94351-56225, 70027-45052 DIBRUGARH- 99544-75308 TINSUKIA- 70027-10942 MOKOKCHUNG- 98626-72609, 84138-48878 DIMAPUR- 94366-02206, 98561-08750, 70051-20250

लायंस क्लब ऑफ बंगाईगांव ने मनाया 50वां स्थापना दिवस

बिजनी, 21 जुलाई (ख.सं) बंगाईगांव शहर के होटल जान्हवी रीजेंसी में लायंस क्लब ऑफ बंगाईगांव का 50वां स्थापना दिवस गरिमापूर्ण एवं भव्य वातावरण में संपन्न हुआ। क्लब की पांच दशकों की गौरवपूर्ण सेवा यात्रा के इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव भी मनाया गया। समारोह क्लब के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हुआ, क्योंकि सेवा, समर्पण और मानवीय मूल्यों की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए क्लब के 50वें अध्यक्ष का विधिवत पदस्थापन किया गया। समारोह के इंस्टॉलेशन ऑफिसर एवं प्रथम उप-जिला गवर्नर लायन राजेश अग्रवाला ने वर्ष 2026-27 के लिए अध्यक्ष लायन कमल शर्मा, सचिव लायन हरजोत सिंह, कोषाध्यक्ष लायन मनीष लखोटिया सहित नवगठित कार्यकारिणी एवं निदेशक मंडल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में उन्होंने कहा कि लायंस का उद्देश्य केवल सेवा कार्य करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक एवं स्थायी परिवर्तन लाना है। उन्होंने सभी सदस्यों से सेवा, अनुशासन, नेतृत्व एवं टीम भावना के साथ कार्य करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर एलसीआईएफ कोऑर्डिनेटर लायन सुनील सर्राफ ने नए सदस्यों का विधिवत इंडक्शन संपन्न कराया। उन्होंने लायंस इंटरनेशनल की सेवा-परंपरा, एलसीआईएफ की वैश्विक मानवीय परियोजनाओं तथा संगठन के मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए नए सदस्यों से निष्ठा, समर्पण और सेवा-भाव के साथ समाजहित में कार्य करने का आह्वान किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में लायन कमल शर्मा ने वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना, क्लब की सेवा-दृष्टि तथा वार्षिक

थीम का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह वर्ष केवल नये कार्यकाल का प्रारंभ नहीं, बल्कि पांच दशकों की गौरवशाली विरासत को नयी ऊर्जा, नवाचार और व्यापक जनसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का अवसर है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, युवा सशक्तिकरण एवं मानवीय सेवा के विविध क्षेत्रों में प्रभावी सेवा परियोजनाएं संचालित करने का संकल्प दोहराया। समारोह के दौरान पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें लायंस सेवा गतिविधियों तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सदस्यों एवं विशिष्ट व्यक्तियों को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लायंस सदस्य, पूर्व पदाधिकारी, गणमान्य अतिथि एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। सभी ने नवगठित नेतृत्व को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह टीम क्लब की गौरवशाली परंपराओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और समाज सेवा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन, लायंस प्रार्थना एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। यह आयोजन केवल नेतृत्व परिवर्तन का समारोह नहीं था, बल्कि पांच दशकों की गौरवशाली सेवा-यात्रा को नमन करते हुए मानव सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ एक नये युग के शुभारंभ का प्रेरणादायी उत्सव भी सिद्ध हुआ।

सिक्किम टनल हादसा : पीएम मोदी ने किया सहायता का ऐलान, गृह मंत्री ने हरसंभव मदद का दिया भरोसा

दस शव निकाले गये, जहरीली गैस के बीच जारी रेस्क्यू ऑपरेशन

गंगटोक, 21 जुलाई। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग क्षेत्र में एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। प्रशासन को आशंका है कि सुरंग के भीतर अभी भी कई मजदूर फंसे हो सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), एसडीआरएफ, राज्य पुलिस, दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। हालांकि भारी बारिश, सुरंग में भरा पानी, जहरीली गैस और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां अभियान को लगातार चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। नामची की पुलिस अधीक्षक सोनम डोल्मा भोटिया ने बताया कि अब तक सुरंग से 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें सात मृतकों की पहचान हो चुकी है, जबकि तीन शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। मृतकों में पश्चिम बंगाल के तीन, जबकि सिक्किम, उत्तराखंड, पंजाब और असम के एक-एक निवासी शामिल हैं। प्रशासन मृतकों के परिजनों से लगातार संपर्क में है और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। लगातार बारिश के कारण सुरंग में बड़ी मात्रा में पानी भर गया था, जिसके चलते कुछ समय के लिए राहत अभियान रोकना पड़ा। पानी निकालने के बाद अभियान दोबारा शुरू किया गया, लेकिन फिसलन, सीमित दृश्यता और खराब मौसम अब भी बचाव कार्य में बाधा बने हुए हैं। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट विवेक कुमार ने बताया कि हादसे का स्थान सुरंग के प्रवेश द्वार से करीब डेढ़ किलोमीटर भीतर है। संकरी सुरंग, सीमित ऑक्सीजन और जहरीली गैस की आशंका के कारण बचावकर्मियों को विशेष सुरक्षा उपकरणों के साथ अभियान चलाना पड़ रहा है। प्रारंभिक जांच में सुरंग के भीतर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के संकेत मिले हैं, जो अत्यंत विषैली मानी जाती है। वहीं गैस रिसाव की वैज्ञानिक जांच के लिए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और आसनसोल से विशेषज्ञों की टीम सिक्किम पहुंच रही है। प्रशासन का कहना है कि जब तक किसी मजदूर के सुरंग में फंसे होने की संभावना बनी रहेगी, तब तक खोज एवं बचाव अभियान जारी रहेगा। हादसे के कारणों और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच बचाव अभियान पूरा होने के बाद की जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ( ) से प्रत्येक मृतक के परिजन को दो-दो लाख रुपये तथा प्रत्येक घायल को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बातचीत कर बचाव अभियान की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियां समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। उन्होंने इस कठिन समय में केंद्र सरकार के सहयोग और संवेदनशीलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्राथमिकता सुरंग में फंसे मजदूरों तक सुरक्षित पहुंचना और उन्हें बाहर निकालना है, जबकि पूरे घटनाक्रम पर राज्य सरकार लगातार नजर बनाए हुए है।

नेरिस्ट डायरेक्टर के इस्तीफे के मुद्दे पर हुई चर्चा

इटानगर, 21 जुलाई (एजें)। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नाटुंग की अध्यक्षता में 'ऑल न्यिशी स्टूडेंट्स यूनियन' (अनसू) और 'ऑल न्यिशी यूथ एसोसिएशन' (अन्या) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में 'नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी' (नेरिस्ट) के डायरेक्टर के इस्तीफे के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना, विधायक मुत्चू मिथी, प्रधान सचिव (गृह), आयुक्त (शिक्षा), वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और गृह विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान, नेरिस्ट में मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई और रचनात्मक बातचीत व आपसी समझ के जरिए मामले को सुलझाने के तरीकों पर विचार किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अन्या के सदस्यों ने बताया कि नेरिस्ट के निर्देशक के इस्तीफे के बाद, हम अन्या और अनसू की सरकार से यह मांग है कि वह उनका इस्तीफा स्वीकार करे, उन्हें पद से मुक्त करे और तुरंत नया निर्देशक नियुक्त करे। इसी सिलसिले में हमने सोमवार को विरोध प्रदर्शन भी किया था। हमारी मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने हमें बातचीत और मामले को सुलझाने के लिए बुलाया। बैठक के दौरान हमने अपनी बात रखी और मामले पर विस्तार से चर्चा की। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और सुलझाने की कोशिश के तहत नेरिस्ट के निर्देशक का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखने का फैसला किया। साथ ही, इस मुद्दे के गहराई और असली कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति भी गठित की जाएगी ताकि दोषियों पर कारवाई की जा सके।

तीन महिला ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। गुप्त सूचना के आधार पर वशिष्ठ पुलिस ने बेहारबाड़ी स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी कर तीन महिला ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान धर्मशाला की जमीले खातून (35), कलगाछिया की आसातुन बेगम (32) और दक्षिण सालमारा की सफीना खातून (34) के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

चोरी गयी ई-रिक्शा समेत एक धराया

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। जालुकबाड़ी थाने के अंतर्गत गोशाला आउटपोस्ट की टीम ने छापेमारी कर एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मालीगांव और जालुकबाड़ी क्षेत्र में हुई चोरी की वारदातों में इस्तेमाल किये जाने वाले औजार तथा एक चोरी गया ई-रिक्शा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

मणिपुर : प्रतिबंधित केसीपी के 46 कैडरों ने किया आत्मसमर्पण

इंफाल, 21 जुलाई (एजें)। मणिपुर में उग्रवाद विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को सोमवार को बड़ी सफलता मिली। प्रतिबंधित संगठन कांगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) (पीपुल्स वॉर ग्रुप) के 46 सक्रिय कैडरों ने मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह की उपस्थिति में इंफाल ईस्ट जिले के मंत्रिपुखरी स्थित असम राइफल्स (साउथ) मुख्यालय में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया। इस दौरान उग्रवादियों ने 28 अत्याधुनिक हथियारों के साथ बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री भी सुरक्षा बलों को सौंप दी। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में राज्य सरकार के गृह मंत्री, कला एवं संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री के अलावा कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। इनमें मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव, सुरक्षा सलाहकार, स्पियर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी), मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), असम राइफल्स (साउथ) के महानिरीक्षक (आईजी), गृह आयुक्त, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के उपमहानिरीक्षक (डीआईजी), विधायक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों ने स्वेच्छा से 28 हथियार सुरक्षा बलों के हवाले किए। इनमें एके श्रृंखला की राइफलें, .303 राइफलें, इंसास राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल (एसएलआर), कार्बाइन, पिस्तौल, डबल बैरल और सिंगल बैरल बंदूकें तथा रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) लॉन्चर शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मैगजीन, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, यह आत्मसमर्पण इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस समूह के सदस्य पहले किसी भी शांति समझौते का हिस्सा नहीं रहे हैं। कांगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) की स्थापना 14 अप्रैल 1980 को वाई. इबोहानबी और इबोपिशाक ने की थी। समय के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण संगठन कई गुटों में बंट गया, जिनमें पीपुल्स वॉर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) सबसे सक्रिय और हिंसक गुटों में से एक माना जाता रहा है। इस गुट की गतिविधियां मुख्य रूप से इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट और काकचिंग सहित घाटी के कई जिलों तक सीमित रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अतीत में केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के पांच से 12 सदस्य ही अलग-अलग समय पर आत्मसमर्पण करते रहे हैं। ऐसे में एक साथ 46 सक्रिय कैडरों का हथियार डालना अभूतपूर्व घटना है। हालांकि अधिकारियों ने यह दावा नहीं किया कि इससे संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन उनका मानना है कि इस घटनाक्रम से संगठन की परिचालन क्षमता और उसके नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, जिससे घाटी क्षेत्र में उसकी गतिविधियां और प्रभाव काफी कमजोर पड़ने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार यह सफलता असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पिछले कई सप्ताह से चलाए जा रहे समन्वित अभियान का परिणाम है। राज्य सरकार के सहयोग और सुरक्षा बलों के संयमित एवं जन-केंद्रित दृष्टिकोण ने उग्रवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस सामूहिक आत्मसमर्पण से राज्य में लंबे समय से प्रभावित विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में आ रही बाधाएं कम होंगी और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को नई मजबूती मिलेगी।

गुवाहाटी में प्रो हेल्थ फिजिकल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन क्लिनिक की सेवाओं का विस्तार

गुवाहाटी, 20 जुलाई (ख.सं)। मणिपुर के जाने-माने और भरोसेमंद फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन संस्थान प्रो हेल्थ फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन क्लिनिक ने असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एविडेंस-बेस्ड फिजियोथेरेपी और होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन सेवाओं को और आसान बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। इस पहल के तहत, नेडफी के डिप्टी जनरल मैनेजर प्रशांत कुमार तालुकदार ने गुवाहाटी में संस्थान की नई ब्रांच का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। नई ब्रांच का उद्घाटन असम और नॉर्थ ईस्ट में साक्ष्य-आधारित फिजियोथेरेपी और कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेवाओं को बढ़ावा देने में एक अहम मील का पत्थर है। प्रो हेल्थ ने मरीज़ों को ध्यान में रखकर रिहैबिलिटेशन सर्विस देने में पहले ही खास नाम और भरोसा कमा लिया है। इस संस्थान ने हज़ारों लोगों को चलने-फिरने में मदद की है, दर्द कम किया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौटने में मदद की है। अच्छी क्वालिटी की फिजियोथेरेपी सर्विस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसने गुवाहाटी में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मस्कुलोस्केलेटल (मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी) समस्याएं, स्पोर्ट्स इंजरी, सर्जरी के बाद की जटिलताएं, नसों और मस्तिष्क से जुड़ी स्थितियां और लंबे समय तक रहने वाला दर्द आम हो गया है। कई लोग देर से इलाज, दर्द की दवाओं पर निर्भरता या खास पुनर्वास सुविधा न मिल पाने के कारण दर्द के साथ ही जीने को मजबूर हैं। 'प्रो हेल्थ' वैज्ञानिक, निजीकृत और लक्ष्य-आधारित ट्रीटमेंट प्लान देकर इस कमी को दूर करने की कोशिश करता है। ये प्लान सिर्फ़ लक्षणों के अल्पकालिक समाधान ढूंढ़ने के बजाय दर्द की असली वजह का पता लगाने और उसका इलाज करने पर ध्यान देता हैं। क्लिनिक गर्दन और पीठ दर्द, फ्रोज़न शोल्डर, गठिया, खेल चोटों और लिगामेंट और टेंडन चोटों के लिए विशेष पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा। इसी तरह, यह फ्रैक्चर के बाद पुनर्वास, संयुक्त प्रतिस्थापन और रीढ़ की सर्जरी के बाद पुनर्वास, स्ट्रोक के बाद पुनर्वास और विभिन्न न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के लिए उपचार की पेशकश करेगा। संतुलन और चाल प्रशिक्षण, वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास, महिलाओं की फिजियोथेरेपी और एर्गोनोमिक परामर्श भी क्लिनिक की विशेष सेवाओं में शामिल हैं। प्रत्येक रोगी की शारीरिक स्थिति, जीवनशैली और पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों का आकलन करने के बाद ही विशेषज्ञ उसके अनुसार उपचार योजना विकसित करते हैं। प्रो हेल्थ ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में अच्छी रिहैबिलिटेशन सर्विस को और आसान बनाने के लिए गुवाहाटी में एक नई ब्रांच खोली है। साथ ही, इंस्टिट्यूट ने समय पर इलाज शुरू करने की ज़रूरत और प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी के फ़ायदों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने को भी समान महत्व दिया है।

चलती कार में लगी आग, बाल-बाल बची सवारों की जान

तिनसुकिया, 21 जुलाई (एजें)। तिनसुकियामाकुम बाईपास पर सोमवार को एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जल उठी। घटना के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर काबू पाया, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। इस दौरान जलती कार को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मायुमं कामाख्या शाखा ने किया कैंडल और पाइप क्लीनर वर्कशॉप का आयोजन

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। महिलाओं और लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच, कामाख्या शाखा के तत्वावधान में 20 और 21 जुलाई को दो दिवसीय कैंडल एवं पाइप क्लीनर वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। वर्कशॉप में टेडी कैंडल, बबल कैंडल, लोटस कैंडल के साथ-साथ पाइप क्लीनर से गुलदस्ता और लिली का फूल बनाना सिखाया गया। इस दौरान महिलाओं ने न केवल सृजनात्मकता का आनंद लिया बल्कि घर बैठे छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा भी ली। कार्यशाला का संचालन शालिनी नाहर के द्वारा किया गया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीके से प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर मंच की अध्यक्ष नमिता दुधोड़िया, सचिव ममता सेठी, कोषाध्यक्ष नम्रता सुराणा और कार्यक्रम संयोजिका चांदनी बैद उपस्थित रहीं। जनसंपर्क अधिकारी निष्ठा पोद्दार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगी।

लायंस अर्पण ने जरुरतमंदों को कराया भोजन

गुवाहाटी, 21 जुलाई (ख.सं.)। लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी अर्पण ने अपने फील्ड द हंगर (एक आहार दिल) के अंतर्गत एबीसी तरुण नगर पूजा पंडाल समिति की जगह खीर, पूरी, सब्जी का वितरण किया । 250 लोगों ने इस गरमा गरम खाने का प्रेम से आनंद लिया । सुमित्रा गुप्ता, रेणु गग्गड़, साधना छावछरिया, साधना खेमका, गरिमा कासलीवाल, सुधा माहेश्वरी, अनीता गोयल, सविता पटवारीकी उपस्थिति से कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हुआ ।

मेघालय की लकाडोंग हल्दी के लिए गोल्डन स्पाइस मिशन का शुभारंभ

शिलांग, 21 जुलाई (एजें)। केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (एमडीओएनईआर), श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के. संगमा के साथ मिलकर आज मेघालय राज्य में हल्दी की खेती और मूल्य श्रृंखला विकास के लिए छ175.45 करोड़ की समन्वित पहल 'मिशन गोल्डन स्पाइस - एकीकृत लकाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना' का शुभारंभ किया। इस मिशन को पांच साल (20252030) के चरणबद्ध रोडमैप के तौर पर तैयार किया गया है, जिसे दो चरणों में लागू किया जाएगा पहला चरण वैल्यू-चेन को मजबूत करना और दूसरा चरण विस्तार और बड़े पैमाने पर काम करना। इसका मकसद मेघालय की खास पहचान (यूएसपी), जीआई-टैग वाली लाकाडोंग हल्दी को बढ़ावा देना है। एमडीओएनईआर और उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के नेतृत्व में, यह मिशन राज्य में एक एकीकृत हल्दी मूल्य-श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, साथ ही एपीईडीए, मसाला बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, आईसीएआर, मीत्यवाई, नाबार्ड, एसएफएसी और मेघालय सरकार की योजनाओं और हस्तक्षेपों के साथ समन्वय पर आधारित है। निवेदिता शुक्ला वर्मा, सचिव, एमडीओएनईआर, ने अपने प्रारंभिक संबोधन में मिशन के कार्यान्वयन ढांचे पर विस्तार से चर्चा की और मेघालय के लकाडोंग हल्दी की पूर्ण आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए मिशन-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि इसमें असाधारण रूप से उच्च करक्यूमिन सामग्री (7-10%), विशिष्ट सुगंध और प्रबल पोषक गुणों के बावजूद, अपर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, कमजोर बाजार संबंधों और उच्च मूल्यवर्धन के अभाव के कारण छोटे किसानों की आय सीमित बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रसंस्कृत और निर्यात योग्य उत्पादों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में काफी अधिक कीमत प्राप्त करने की क्षमता है। सचिव ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि मिशन का उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान, एकीकृत कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे की कमी, वाणिज्यिक पैमाने पर प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव, कमजोर ब्रांडिंग और संरचित जीआई मुद्रीकरण और क्रेता संपर्क प्रणालियों की कमी सहित क्षेत्र में मौजूद प्रमुख संरचनात्मक कमियों को व्यवस्थित रूप से दूर करना है। कार्यक्रम के तहत, गोल्डन स्पाइस मिशन पर एक लघु फिल्म दिखाई गई, जिसके बाद मेघालय के प्रगतिशील हल्दी किसानों के साथ बातचीत हुई और निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। केंद्रीय मंत्री, एमडीओएनईआर, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि यह लॉन्च प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'अष्टलक्ष्मी' यानी भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों के विज़न का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि पिछले बारह वर्षों में ये राज्य भारत के विकास के नज़रिए में हाशिए से हटकर केंद्र में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर प्रत्येक राज्य के लिए एक विशिष्ट विक्रय प्रस्ताव (यूएसपी) परिभाषित किया है और प्रत्येक यूएसपी को 'ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर' के दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया है। उन्होंने बताया कि लाकाडोंग हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा दुनिया के औसत से लगभग चार गुना ज़्यादा है, और हल्दी के उत्पादन और प्रोसेसिंग में महिलाओं की असाधारण भूमिका पर ज़ोर दिया।

स्पेन की जीत

फुटबॉल को अक्सर व्यक्तिगत प्रतिभाओं का खेल माना जाता है। जब लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, जूड बेलिंघम या लामिन यामाल जैसे सितारे मैदान में उतरते हैं तो दर्शकों की निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं। लेकिन 2026 फीफा विश्व कप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिरकार ट्रॉफी उसी टीम के हाथ लगती है, जो सामूहिकता, अनुशासन और स्पष्ट रणनीति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाती है। स्पेन की विश्व कप विजय इसी सत्य की सबसे प्रभावशाली मिसाल है।

कोच लुइस दे ला फुएंते के नेतृत्व में स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का फुटबॉल खेला, वह आधुनिक खेल की नयी परिभाषा बन गया। गेंद पर नियंत्रण, सटीक पासिंग, मजबूत रक्षापंक्ति और हर खिलाड़ी की सामूहिक जिम्मेदारी ने उसे बाकी टीमों से अलग पहचान दी। आठ मुकाबलों में केवल एक गोल खाना और आक्रमण में सात अलग-अलग खिलाड़ियों का गोल करना बताता है कि स्पेन किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं था। मिडफील्ड में रोड्री की अद्भुत भूमिका और रिकॉर्ड पासिंग ने यह दिखाया कि मैच केवल गोल करने वाले नहीं, बल्कि खेल को नियंत्रित करने वाले खिलाड़ी भी जिताते हैं। यही कारण है कि रोड्री को लगातार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जा रहा है।

स्पेन की यह सफलता कोई संयोग नहीं है। पिछले डेढ़ दशक में उसने विश्व फुटबॉल के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। 2008 से अब तक दो विश्व कप और तीन यूरोपीय चैंपियनशिप जीतना इस बात का प्रमाण है कि वहां प्रतिभा तैयार करने की प्रक्रिया लगातार मजबूत होती गयी है। पुरुष ही नहीं, महिला फुटबॉल में भी स्पेन विश्व चैंपियन है। यह उपलब्धि बताती है कि सफलता केवल एक पीढ़ी के खिलाड़ियों की देन नहीं होती, बल्कि मजबूत अकादमियों, प्रशिक्षकों और दीर्घकालिक खेल नीति का परिणाम होती है।

इस विश्व कप का दूसरा बड़ा आकर्षण 39 वर्षीय लियोनेल मेसी रहे। अर्जेंटीना भले ही फाइनल हार गया, लेकिन मेसी ने एक बार फिर साबित किया कि महान खिलाड़ी उम्र के आंकड़ों से नहीं, अपने खेल से पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपनी टीम को लगातार प्रेरित किया और फाइनल तक पहुंचाया। दूसरी ओर, किलियन एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट जीतकर विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में स्थान बना लिया, लेकिन सेमीफाइनल में स्पेन के खिलाफ उनका प्रभाव सीमित रहा। इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने भी अपनी टीम को तीसरे स्थान तक पहुंचाया, किंतु खिताब जीतने के लिए केवल व्यक्तिगत चमक पर्याप्त नहीं होती।

हालांकि यह विश्व कप केवल शानदार फुटबॉल के लिए ही याद नहीं रखा जाएगा। टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर भी कई सवाल उठे। अमेरिका में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान आव्रजन नियमों को लेकर विवाद, खेल से जुड़े मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका, व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देते हुए बार-बार कराये गये हाइड्रेशन ब्रेक और फाइनल में आयोजित लंबे हाफ-टाइम शो ने फुटबॉल प्रेमियों को निराश किया। फुटबॉल की सबसे बड़ी खूबी उसका निरंतर प्रवाह है। खेल बार-बार रुकने लगे तो उसकी स्वाभाविक लय टूट जाती है। व्यावसायिक लाभ और मनोरंजन के नाम पर खेल की आत्मा से समझौता नहीं होना चाहिए।

फीफा को यह समझना होगा कि विश्व कप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है। इसकी प्रतिष्ठा निष्पक्षता, पारदर्शिता और खेल भावना पर टिकी है। यदि व्यावसायिक हित खेल के मूल स्वरूप पर हावी होने लगेंगे तो दर्शकों का विश्वास कमजोर होगा। आयोजन को आधुनिक बनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सुधार ऐसे हों जो खेल को बेहतर बनाएं, उसे बोझिल नहीं।

स्पेन की जीत यह संदेश देती है कि सफलता का सबसे बड़ा सूत्र सामूहिकता है। चाहे खेल का मैदान हो, कोई संस्था हो या कोई राष्ट्रजब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं टीम के लक्ष्य के साथ जुड़ जाती हैं, तब असाधारण उपलब्धियां संभव होती हैं। विश्व कप 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सितारे मैच जिता सकते हैं, लेकिन इतिहास वही टीम लिखती है जो एकजुट होकर खेलती है। यही इस विश्व कप का सबसे बड़ा संदेश और सबसे मूल्यवान सबक है।

| संपादकीय |

सीजेपी के संसद मार्च से सुलगते सवाल व राजनीतिक निहितार्थ

कमलेश पांडे

देखा जाए तो इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में नीट पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही, कुछ नेताओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ संवाद आदि हैं, लेकिन जो उत्पात दिखायी-सुनायी दिया, वह विपक्षी संस्कार नहीं तो क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का 'संसद चलो' आह्वान केवल एक विरोध मार्च नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक राजनीतिक रणनीति है। खासकर जिस तरह से इस आंदोलन को छात्र आंदोलन का स्वरूप दिलवाया जा चुका है, वह डीप स्टेट के इशारे पर बनी विपक्ष की शातिर सरकार घेरो रणनीति का कमाल भी करार दिया जा रहा है। देखा जाए तो संसद के मानसून सत्र के दौरान गत 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च करने के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और कूच किया, वह बिल्कुल संगठित राजनीतिक आंदोलन के तर्ज पर हुआ।

मजे की बात तो यह कि संसद के निकट पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो पूर्व प्रायोजित झड़प हुई और उसके बाद हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, इससे यह संसद मार्च राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया। बड़े-बड़े न्यूज चैनल्स और अखबारों के दफ्तरों में इससे जुड़े कई नीतिगत सवालों पर भी बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर जहां सरकार विरोधी भड़काऊ वीडियो वायरल होने लगे, वहीं सत्ताधारी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलनकारियों की कारगुजारियों के वीडियो साझा कर दिये, जिससे लोगों की सहानुभूति पुलिस और सरकार के साथ बनी रही।

यदि संसद मार्च के घटनाक्रमों पर संतुलित नजर डालें तो यही प्रतीत होता है कि जब बड़ी संख्या में सीजेपी समर्थक 'संसद चलो' मार्च के लिए जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़े, तो भले ही उनकी मुख्य मांगें शिक्षा सुधार, परीक्षा-पत्र लीक और जवाबदेही था, लेकिन इरादे तोड़फोड़ वाले और खतरनाक थे, अन्यथा पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ता। चूंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान माननीयों की सुरक्षा के दृष्टिगत दिल्ली पुलिस ने व्यापक बैरिकेडिंग की थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को रोका, हिरासत में लिया तथा कुछ स्थानों पर आंदोलनकारियों द्वारा उपद्रव करने के बाद आंसू गैस और बल प्रयोग की घटनाएं सामने आईं। इससे अफरातफरी मच गयी।

देखा जाए तो इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में नीट पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही, कुछ नेताओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ संवाद आदि हैं, लेकिन जो उत्पात दिखायी-सुनाई दिया, वह विपक्षी संस्कार नहीं तो क्या है? फिर भी, केंद्र सरकार ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से बातचीत की पहल भी की, जो टकराव के बीच संवाद की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और मांगपत्र ग्रहण किया। बावजूद इसके आंदोलनकारी अपनी मांगों पर कायम हैं। सवाल है कि संसद मार्च के क्रम में जो कुछ गड़बड़ हुआ, क्या वह लोकतांत्रिक है, सही था या गलत? तो जवाब होगा कि युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र का वैध हिस्सा है। वहीं, सरकार द्वारा आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप कदम है। फिर भी संसद मार्च के दौरान आंदोलनकारियों की ओर से कुछ कुछ गलत हुआ जो अनुचित लगा। यदि प्रदर्शनकारियों ने निषिद्ध क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने या बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो वह कानून-व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा।

वहीं, यदि पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक कार्रवाई हुई, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि, इस पर अलग-अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं और सभी तथ्यों के गोलमोल जवाब ही मिले हैं, जिनपर एतबार करना मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जिसका अंतिम सत्यापन अभी होना बाकी है, कई अनकही कहानियां गढ़ रहे हैं। इससे सरकार सांसत में है और विपक्ष तरह-तरह के आरोप लगाकर सिस्टम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि लोकतांत्रिक समाधान का सर्वोत्तम रास्ता संवाद और कानून के दायरे में रहकर समस्या का समाधान है।

भले ही किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी मांगें रखना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन इस संसद मार्च के क्रम में देश की राजधानी नयी दिल्ली के हृदय स्थल पर, जिस प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़, सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या सुरक्षा बलों से टकराव की जो प्रवृति दिखायी दी, वह विपक्षी दलों का परोक्ष कुचक्र नहीं तो क्या है? आखिर इस देशद्रोही प्रवृति को कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि पुलिस बल का प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ हो, तो उसकी भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। सवाल है कि क्या स्थानीय जिलाधिकारी और डीसीपी के पास छात्र समूह को काबू में रखने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी? और यदि थी तो फिर इतना सबकुछ कैसे हुआ? वहीं कोई पुलिस कर्मी कैसे पिट गया और घायल हुआ? आखिर किसी दुकानदार को तोड़-फोड़ का सामना क्यों और कैसे करना पड़ा? जनपथ बाजार की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त क्यों नहीं किये गये थे। वहीं, अनियंत्रित युवा भीड़ क्यों जुटने दी गयी और उनको काबू में रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त क्यों नहीं किये गये थे? कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो आह्वान के राजनीतिक मायने केवल एक विरोध मार्च तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय राजनीति में युवाओं के असंतोष, डिजिटल आंदोलन और पारंपरिक दलों के प्रति अविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। हालांकि सीजेपी स्वयं को व्यंग्यात्मक आंदोलन बताता है, लेकिन इसके मुद्दे गंभीर राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं।

यही वजह है कि राजनीतिक दृष्टि से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं :- पहला, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दबाव की राजनीति। दूसरा, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के असंतोष को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास। तीसरा, विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का अवसर और चौथा, सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाये रखते हुए आंदोलनकारियों से संवाद की चुनौती आदि।

हालांकि, इसके प्रमुख राजनीतिक संकेत इस प्रकार हैं : एक, युवा असंतोष का राजनीतिक रूपांतरण : बेरोजगारी, परीक्षा-पत्र लीक, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी को संगठित करने का प्रयास दिखायी देता है। *दो, डिजिटल से सड़क तक :* सोशल मीडिया पर शुरू हुआ अभियान अब वास्तविक जन-प्रदर्शन में बदलता दिख रहा है, जो यह संकेत देता है कि ऑनलाइन असंतोष भी राजनीतिक दबाव का माध्यम बन सकता है।

तीन, सरकार पर दबाव: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन मार्च का समय चुनना सरकार और संसद का ध्यान आकर्षित करने की रणनीति माना जा सकता है। सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू होने की खबर भी इसी दबाव का संकेत है।

चार, विपक्ष के लिए अवसर : यदि विपक्ष इस असंतोष को राजनीतिक समर्थन देता है, तो यह सरकार को घेरने का एक नया मुद्दा बन सकता है। वहीं यदि आंदोलन स्वतंत्र बना रहता है, तो यह पारंपरिक दलों से अलग एक नयी राजनीतिक शैली का संकेत होगा।

पांच, प्रतीकों की राजनीति: कॉकरोच जैसे अपमानजनक शब्द को पहचान और प्रतिरोध के प्रतीक में बदलना राजनीतिक संचार की एक प्रभावी रणनीति है, जो विशेषकर युवाओं के बीच ध्यान आकर्षित करती है। छठा, सीजेपी की कई मांगें और उसकी प्रस्तुति व्यंग्य एवं प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह एक स्थायी राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति बन जाएगी। दरअसल उसकी वास्तविक राजनीतिक क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वह सोशल मीडिया की लोकप्रियता को लंबे समय तक संगठित जनसमर्थन और ठोस राजनीतिक संगठन में बदल पाती है। *निष्कर्षत :* यही कहना उपयुक्त होगा कि लोकतंत्र में न तो हिंसक टकराव समाधान है और न ही वैध असंतोष को केवल बल पूर्वक दबाना। लिहाजा सबसे उचित रास्ता यही है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, कानून का सम्मान हो, और सरकार ठोस संवाद के माध्यम से शिक्षा सुधार तथा परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों का विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत करे। अन्यथा छात्र आंदोलन यदि राष्ट्रीय स्वरूप अख्तियार कर लेगा तो सनातनी सत्ता को लेने के देने पड़ जाएंगे।

जंग जरूरी है खाने में मिलावट करने वालों के खिलाफ

विवेक शुक्ला

जरा कल्पना करो कि सुबह आप चाय में दूध डालते हो लेकिन उस दूध में पानी और कुछ कैमिकल मिला हुआ है। या फिर मिर्च पाऊडर में सिंथैटिक कलर मिला है। अफसोस कि यह भारत में रोजमर्रा की हकीकत है। खाने के सामान में मिलावट आज देश की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। यह सिर्फ पैसे बचाने का लालच नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। भारत में खाने की मिलावट की जड़ें काफी गहरी हैं। एफएसएसएआई (खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारत) के आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026 में टैस्ट किये गये हर 6 खाद्य नमूनों में से 1 फेल हो गया। मतलब करीब 16-17 फीसदी सैंपल स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरे। दूध, घी, मसाले, पनीर, तेल, चाय पाऊडर, ये सब आम टार्गेट हैं।

महाराष्ट्र में हाल ही में एफडीए की रेड के दौरान ट्रक वाले दूध फैंकने लगे क्योंकि उन्हें डर था कि मिलावट पकड़ी जाएगी। शोलापुर में 37,000 लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध जब्त और नष्ट किया गया। अब तक 359 गिरफ्तारियां, 235 एफआईआर और करोड़ों के सामान जब्त किये गये। दूध कलैक्शन 20-25 प्रतिशत तक गिर गया, जो दिखाता है कि पहले कितना घोटाला चल रहा था। दिल्ली-यूपी में पनीर की हालत और खराब है। 83 फीसदी सैंपल फेल, 40 फीसदी हानिकारक। पाम ऑयल, यूरिया और कैमिकल मिलाकर बनाया जाता है फेक पनीर। मसालों में सिंथैटिक डाई, मछली में फॉर्मेलिन, घी में वनस्पति तेल आदि। लिस्ट लंबी है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक, छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी सप्लाई चेन तक यह फैला हुआ है। गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि वे सस्ता सामान खरीदते हैं। दिल्ली में नवरात्रि के समय मिलावटी आटा खाने से सैंकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गये। पंजाब में घी और मिठाइयों की रेड में हजारों किलो सामान जब्त किया गया।

दुष्परिणाम क्या हैं : खाने की मिलावट के नुकसान 2 तरह के हैं। पहला-पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, फूड प्वॉइजनिंग। लंबे समय में लिवर-किडनी डैमेज, कैंसर, हार्मोनल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल जैसी समस्याओं से दो-चार होना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनियाभर में मिलावटी खाने की चीजों से 60 करोड़ लोग बीमार हो रहे हैं या जान गंवा रहे हैं। भारत में ये आंकड़े और भयावह हैं। सिंथैटिक कलर वाली मिर्च से पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं। डिटर्जेंट मिले दूध से बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है और हड्डियों को कमजोर कर रहा है। दूसरा, लंबे समय तक इस तरह के खाद्य पदार्थों के सेवन से डायबिटीज और दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं।

सरकार की कोशिशें : पर अब सरकार लड़ने के मूड में है। एफएसएसएआई की तरफ से भारत नियमित सैंपलिंग, रेड, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह भारत सरकार का वह मुख्य संगठन है जो पूरे देश में खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा, गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करता है। राज्यों में एफडीए, हैल्थ डिपार्टमैंट रेड कर रहे हैं। पैनल्टी, जेल और खराब सामान को नष्ट किया जा रहा है। स्कूलों में फूड सेफ्टी एजुकेशन के अभियान चलाये जा रहे हैं। लेकिन चुनौतियां हैं। संसाधन कम हैं, ग्रामीण इलाकों में पहुंच मुश्किल है पर प्रयास हो रहे हैं। उदाहरण के रूप में दिल्ली- हरियाणा सीमा पर भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का संस्थान है नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फूड टैक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमैंट (निफ्टेम)। यहां खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केंद्रों में खाने की मिलावट डिटैक्शन, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता पर काम किया जा रहा है। इधर रैपिड टैस्टिंग्स किट्स, एडवांस्ड एनालिसिस टैक्निक्स, खाद्य सुरक्षा मानकों पर अनुसंधान किया जाता है। प्रख्यात वैज्ञानिक और निफ्टेम के निदेशक डॉ. हरिंदर सिंह ओबेरॉय कहते हैं कि हम थोड़ा कम, ईट राइट के विचार को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों की टीम उद्योगों के साथ मिलकर नयी तकनीकें विकसित और सांझा करती है। मतलब, नयी मशीनें और तरीके फैक्टरियों तक पहुंचा दिये जाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक कई रिसर्च करके उन्हें किताबों और जर्नल में छापते हैं। इससे दूसरे लोग भी सीख पाते हैं।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर निफ्टेम खास कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें सड़क के ठेले वाले विक्रेताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें साफ-सफाई, सही तरीके से खाना रखने और मिलावट न करने की जानकारी दी जाती है। डॉ. ओबेरॉय कहते हैं कि हमें भारत को एक इस तरह के देश के रूप में विकसित करना है, जहां खाने-पीने की वस्तुओं में कतई मिलावट न हो। दरअसल खाने की मिलावट से निपटने के लिए सस्ती और तेज टैस्ट किट्स बनायी जा रही हैं। इनसे गांव-शहर में कहीं भी आसानी से चैक किया जा सकता है। दूसरे, ये रिसर्च एफएसएसएआई को बेहतर नियम बनाने में मदद करती हैं। तीसरे, फैक्टरियों को साफ-सुथरी प्रोसैसिंग तकनीक दी जाती है, जिससे मिलावट करने की जरूरत ही कम पड़ती है। चौथे, जागरूकता कार्यक्रमों और ट्रेनिंग से पूरी सप्लाई चेन मजबूत होती है। इससे किसान से लेकर दुकानदार तक सब सतर्क रहते हैं। पांचवें, लंबे समय में लोगों की बीमारियां कम होंगी, स्वास्थ्य पर खर्च घटेगा और भारत का खाना विदेशों में भी ज्यादा बिकेगा।

उदाहरण के तौर पर, अगर निफ्टेम की तकनीक से मसाले या दूध की जांच सिर्फ 10 मिनट में हो जाए, तो अधिकारी तुरंत छापा मार सकेंगे। ठेले वाले विक्रेता ट्रेनिंग लेकर साफ-सुथरा और असली खाना बेचेंगे, जिससे ग्राहक भी खुश रहेंगे। सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। खरीदते समय लेबल अच्छे से पढ़ें, एफएसएसएआई का लोगो देखें और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो शिकायत जरूर करें। अगर हर स्तर पर ईमानदारी आये, तो स्वस्थ भारत का सपना सच हो सकता है। इस सपने को पूरा करने में निफ्टेम जैसे संस्थानों का अहम रोल होने वाला है। याद रखें, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सेहत बनाने के लिए होता है। आइए, मिलकर ईट राइट अभियान को आगे बढ़ाएं!

बड़ा सवाल : दिपके का यह दीप *बुझ* जाएगा या *लौ* में बदलेगा?

अजय बोकिल

देश की राजधानी नयी दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आह्वान पर आयोजित संसद मार्च में जिस तरह से हजारों युवाओं की भीड़ जुटी, उसे रोकने लाठी चार्ज हुआ, भीड़ ने हिंसा की, विपक्ष ने इसको लेकर संसद में हंगामा किया और अनशन स्थल से हटाये जाने के बाद दूसरे दिन आंदोलनकारियों का फिर से जंतर मंतर पर धरने पर जम जाना कई सवाल खड़े करता है। उधर पंजाब के किसानों ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील (जो अभी अंतिम रूप से हुई ही नहीं है) को लेकर दिल्ली कूच कर दिया है। क्या ये घटनाक्रम महज संयोग अथवा किसी दूरगामी राजनीतिक अभियान की ओर संकेत करता है? इसके पीछे आधार यह है कि भारत में कई बार सत्ता परिवर्तन का मूल कारण कुछ और रहता है और बाद में वह शुद्ध रूप से राजनीतिक आकार ले लेता है। फिर चाहे वह बोफोर्स घूस कांड हो, मंडल-कमंडल आंदोलन या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन हो।

सभी की शुरुआत व्यवस्था में सुधार की मांग से हुई थी और अंजाम सत्तारूढ़ दल की रवानगी से हुआ। तो क्या इस बार भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है या फिर यह भी चाय की प्याली में उठा तूफान है, जिससे मोदी सरकार अपने तरीके से निपट लेगी। बीते 12 वर्षों में उठे आंदोलनों के बुलबुलों की माफिक यह भी जल्द फूट जाएगा। क्योंकि आंदोलनों से निपटने की प्रति रणनीति पहले से तैयार है। हालांकि प्रति रणनीति हर बार सफल ही हो, यह जरूरी नहीं है। विपक्ष में इच्छाशक्ति और संगठन क्षमता की कमी?

दरअसल दिल्ली में पांच साल पहले किसान आंदोलन के कारण जो जबर्दस्त हलचल मची थी, वैसी फिर देखने में नहीं आयी। ऐसा नहीं है देश में मुद्दे खत्म हो गये हैं, लेकिन उसे उठाने के लिए जरूरी इच्छाशक्ति और संगठन क्षमता विपक्ष में नहीं दिखायी दी। दरअसल विपक्ष स्वयं किसी मुद्दे को व्यापक राजनीतिक आंदोलन में बदलने में नाकाम रहा है, लेकिन दूसरों द्वारा शुरू किये आंदोलनों में अपनी राजनीतिक संभावनाएं जरूर खोजता रहा है। जबकि सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी प्रेरक शक्ति आरएसएस इन आंदोलनों के पीछे की मंशा को भांपकर अपने तरीकों से उसकी हवा निकालने में कामयाब रहे हैं। क्योंकि इन आंदोलनों का जनता का व्यापक समर्थन कभी नहीं मिला। वह किसी एक वर्ग अथवा समुदाय तक सीमित होकर रह गया। विपक्ष की मानें तो उसका असल उद्देश्य मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है ताकि देश और संविधान को बचाया जा सके। जबकि मोदी सरकार और संघ भी इसे इसलिए कामयाब नहीं होने देता क्योंकि देश और उसकी संस्कृति को बचाये रखना है। इसमें कौन सही है, यह निरपेक्ष भाव से तय करना कठिन है, क्योंकि हकीकत में दोनों की दृष्टि एकांगी है।

उदाहरण के लिए 20 जुलाई को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और सीजेपी के आव्हान पर छात्रों की मांगों को लेकर आयोजित संसद मार्च के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जाने से पहले मीडिया से भारत की युवाशक्ति की उपलब्धियों का तो जिक्र किया, लेकिन उसी समय जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हजारों नाराज युवाओं के बारे में एक शब्द नहीं कहा। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद में आंदोलनकारी युवाओं के दमन और सरकार की उनके प्रति असंवदेनशीलता का तो मुद्दा उठाया, लेकिन आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और बड़ी संख्या में घायल सुरक्षाकर्मियों के बारे में मौन साध लिया। लेकिन इससे इस आंदोलन की महत्ता कम नहीं होती। क्योंकि यह बात ही अपने आप में चिंता का विषय होनी चाहिए कि देश का भविष्य युवा अगर अपनी समस्याओं और तकलीफों को लेकर सड़कों पर उतर रहा है तो यह स्थिति बनी क्यों? वैसे भी असंगठित सीजेपी की मांगों और सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के प्रति सरकार ने शुरू से सकारात्मक रवैया अपनाया होता तो यह स्थिति शायद बनती ही नहीं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलनकारियों से जो बात जंतर-मंतर पर हंगामे के बाद की, वह अगर पहले ही कर ली जाती तो संसद मार्च की नौबत ही नहीं आती। वैसे भी सरकार आंदोलनकारियों की सारी मांगे माने, यह जरूरी नहीं है, लेकिन वह युवाओं को यह तो बता सकती थी कि सरकार उनकी मांगों के संदर्भ में क्या करने जा रही है। यहां बात मूलत: कोई भी काम सदाशयता के साथ दूसरों को विश्वास में लेकर करने की है। लेकिन सरकार को शायद यही मंजूर नहीं है। वह बात भी करती है तो रायता फैल जाने के बाद। इस पूरे मामले को भी ठीक से हैंडल नहीं किया गया, यह राय खुद भाजपा और संघ में कई लोगों की है। वैसे भी सरकार युवाओं से लड़कर संदेश क्या देना चाहती है?

कहा यह भी जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो हुआ, उसके पीछे युवा कम दूसरे राजनीतिक तत्वों का हाथ ज्यादा है। वामपंथी पार्टियों के छात्र संगठनों ने तो आंदोलन को खुला समर्थन दे ही दिया था। उसके अलावा आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के लोग भी बड़ी तादाद में आंदोलन में पहुंचे। इस वजह से पूरा आंदोलन शुद्ध रूप से छात्रों का रह नहीं गया था। लेकिन यह भी सही है कि हजारों छात्र-छात्राएं देश के कई हिस्सों से अपने खर्चे पर इस मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि उनकी समस्याएं जायज हैं। उनका दर्द वाजिब है कि अगर परीक्षाएं ही ईमानदारी से नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे? कहां जाएंगे? यही व्यक्तिगत आक्रोश जंतर मंतर पर सामूहिक रूप से व्यक्त हुआ। हालांकि सरकार ने भी उसे शुरू में नहीं रोका। लेकिन तभी संवाद होता तो बात कुछ अलग होती। यह तर्क भी लचर है कि संवाद सरकार करती तो किससे, जो बात बाद में जिनसे की गयी, उन्हीं से पहले भी की जा सकती थी। आंदोलनकारियों की तीन मुख्य मांगों में पहली केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। आंदोलनकारियों को लगता है कि परीक्षा में पेपर लीक के लिए वो नैतिक जिम्मदारी लें। दूसरी मांग सोनम वांगचुक की रिहाई की है। तीसरी मांग पेपर लीक से दुखी होकर खुदकुशी करने वाले परीक्षार्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रू. का मुआवजा दिया जाए।

जहां तक किसी भी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफे की बात है तो वह भाजपा के राम राज्य में वह फिट नहीं होती। आखिर किसी भी अनैतिक काम की नैतिक जिम्मेदारी कोई क्यों ले? अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। सत्ता में रहते हमारा काम चोरों को पकड़ना है, आत्मावलोकन करना नहीं है। यही मानस हमने श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में देखा। दूसरी मांग मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोनम वांगचुक अस्पताल में हैं, किसी जेल में नहीं। अलबत्ता तीसरी मांग मानी जाएगी, इसमें संदेह है, क्योंकि किसान आत्महत्या की तरह भानमती का नया पिटारा खुल जाएगा। कोई छात्र किसी भी कारण से खुदकुशी करे, मुआवजे के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।

भाजपा समर्थक इस छात्र आंदोलन को मोदी सरकार के खिलाफ एक और टूलकिट मान रहे हैं। यहां तक कि इसके मीडिया कवरेज में यह सोच हावी दिखी। लेकिन सरकार के हित में यही है कि वह शांति और विवेक कायम रखकर इसे निपटाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि जंतर मंतर और संसद के सामने हंगामा और हिंसा करने वाले छात्र थे ही नहीं। संभव है कि पुलिस द्वारा पकड़े गये लोगों में छात्र न हों, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे और यही सरकार के लिए आगे चलकर खतरे की घंटी हो सकती है।

इस आंदोलन का एक और अहम पक्ष सोशल मीडिया के वर्च्युअल वर्ल्ड में जीने युवाओं का स्वप्रेरणा से सड़कों पर वास्तविक दुनिया में उतरना है। जबकि सरकार और राजनीतिक प्रेक्षक यह मानकर चल रहे थे कि सोशल मीडिया और सड़क मूवमेंट का आपस में सीधा रिश्ता नहीं है। भारत में जेन जी ऐसा नहीं कर सकती। इस अर्थ में सीजेपी की यह सफलता है कि महज कटाक्ष के तौर पर सोशल मीडिया में बनी एक पार्टी नाराज युवाओंको सड़क पर उतारने में कामयाब हो गयी। यह सोच अगर राज्यों और जिलों तक फैल गयी तो एक बड़ा आंदोलन भविष्य में खड़ा हो सकता है। इस बीच सोनम वांगचुक ने अस्पताल में भी अनशन जारी रखने का एलान कर दिया है तो दूसरी तरफ सीजेपी के संस्थापन अभिजीत दिपके और सोनम की पत्नी गीतांजलि ने जंतर मंतर पर धरना जारी रखने का एलान किया है। यह बात अलग है कि खुद गांधीवादी में सोनम के अनशन को गांधीवादी आंदोलन नहीं मान रहे। लेकिन ये सिलसिला जारी रहे, यह विपक्षी पार्टियों के लिए भी मुफीद है, क्योंकि उसे यह आरोप लगाने का मौका मिलता रहेगा कि यह सरकार युवा विरोधी है। विपक्ष की नजर 2029 के लोकसभा चुनावों पर है। उसका मानना है कि देश में मोदी की लोकप्रियता लहर अब मंद पड़ने लगी है। लोकसभा चुनाव तक इसे किसी तरह चरम पर पहुंचाया जाए। सीजेपी जैसे संगठन इसमें मददगार हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष की सोच को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों ने गलत ही साबित किया है। फिर भी राजनीति संभावनाओं का खेल है। कौन जानता था कि अन्ना शब्द का राजनीतिक अनुवाद मोदी में होगा।

संक्षिप्त समाचार

बैनामे में 11.19 लाख रुपये के स्टांप शुल्क की कमी, वाद दर्ज करने की संस्तुति

मेरठ। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने एक संपत्ति के बैनामे पर 11 लाख 19 हजार 990 रुपये के स्टांप शुल्क की कमी पाई है। इस मामले में नियमानुसार वसूली के लिए स्टांप वाद दर्ज करने की संस्तुति की गई है। यह कार्रवाई बिमला देवी की शिकायत पर की गई है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन नवीन कुमार एस. के अनुसार, यह बैनामा 28 फरवरी, 2025 को किया गया था। इसके तहत राजीव कुमार वर्मा और राज रानी ने धीरेंद्र कुमार त्यागी को 539 वर्ग गज की संपत्ति बेची थी। संपत्ति अशोक नगर, यूनिवर्सिटी रोड, मेरठ में स्थित है। इसका सौदा 5.60 करोड़ रुपये में तय हुआ था। सौदे के अनुसार, 11.20 लाख रुपये का स्टांप शुल्क देय था। हालांकि, बैनामे पर केवल 10 रुपये का स्टांप शुल्क अदा किया गया था। इस सौदे पर दो फीसदी स्टांप शुल्क लगना था। इस हिसाब से 11.20 लाख रुपये का शुल्क बनता है। जांच में बैनामे में 11 लाख 19 हजार 990 रुपये के स्टांप शुल्क की कमी पाई गई है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने इसके वसूली और स्टांप वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।

शहर में जाणता राजा महानाट्य की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार

मेरठ। दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के तत्वावधान में 22 से 28 अक्तूबर 2026 तक गाजियाबाद के सनसिटी में आयोजित होने वाले महानाट्य जाणता राजा के आयोजन को लेकर सोमवार को यहां होटल हार्मनी इन में बैठक हुई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गौतम तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक महेंद्र की मौजूदगी में कार्यक्रम के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन किया गया। डॉ. आशीष गौतम ने बताया कि जाणता राजा केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, उनके आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और स्वराज्य की भावना को समाज तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। महेंद्र ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कवि डॉ. हरिओम पंवार की विशेष उपस्थिति रही। अध्यक्षता अजय गुप्ता और जाणता राजा आयोजन समिति के संयोजक विनय चौधरी भी मौजूद रहे। संचालन दीपक शर्मा और विजय राज सिंह ने सभी का आभार जताया।

40 साल बाद 20 जुलाई को रहा सबसे ठंडा दिन

कानपुर। लगातार बादलों के डेरा जमाने और शुक्रवार की रात से बारिश होने के चलते कानपुर में 20 जुलाई को मौसम ने 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोमवार को अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 1986 में इससे कम अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक पहुंचा था। दो दिन से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और मौसम विभाग की वेधशाला में सन शाइन आवर शून्य दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में शहर में 77 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। रविवार रात से सोमवार सुबह आठ बजे तक 38.6 मिमी और सुबह आठ बजे से दोपहर ढाई बजे तक 38.4 मिमी बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी से नमी आने और मानसूनी द्रोणी तराई से निकलकर कानपुर परिक्षेत्र के नजदीक आने से मानसूनी बारिश शुरू हो गई। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि जुलाई की औसत बारिश 271.6 मिमी है। इस महीने अब तक 245.9 मिमी बारिश हो चुकी है जो औसत बारिश का 90.54 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि अगले दो दिन तक मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी दिखा। 24 घंटे में अधिकतम तापमान में चार डिग्री की गिरावट आई, जबकि न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री नीचे चला गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 7.6 डिग्री कम रहा। सुबह और दोपहर के समय वातावरण में नमी का स्तर 98 प्रतिशत दर्ज किया गया।

क्यारा ब्लॉक में नई पोषण किट का वितरण शुरू

अलीगंज। क्यारा ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब नई पोषण किट का वितरण शुरू हो गया है। शासनादेश के अनुसार, बच्चों, गर्भवतियों और धात्री महिलाओं को आटा-बेसन का मिश्रण और मूंग-चावल का मिश्रण दिया जा रहा है। अतिकुपोषित बच्चों के लिए विशेष हलवा दिया जा रहा है। क्यारा ब्लॉक में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) राजकुमारी ने बताया कि सभी केंद्रों पर आठ जुलाई से नई पोषण किट वितरित की जा रही है। पहले पुष्टाहार में रिफाइंड तेल, चना दाल और दलिया दिया जाता था। अब आयुवर्ग के अनुसार छह प्रकार की रेसिपी दी जा रही हैं। इनमें शिशु अमृत, शिशु आहार, बाल पुष्टिकर, संपूर्ण मातृ आहार, बाल संजीवनी और सक्षम पोषण शामिल की हैं। छह माह से तीन साल तक के बच्चों को आटा-बेसन हलवा के तीन पैकेट, तीन से छह साल के बच्चों को आटा-बेसन बर्फी का एक पैकेट व दलिया-मूंग दाल की खिचड़ी के दो पैकेट, गर्भवती व धात्री महिलाओं को आटा-बेसन बर्फी के दो पैकेट व दलिया-मूंग दाल खिचड़ी के दो पैकेट, छह माह से छह साल तक के अतिकुपोषित बच्चों को ऊर्जा युक्त हलवा के पांच पैकेट दिए जा रहे हैं।

सदन में जदयू विधायक ने सरकार को घेरा,

श्याम रजक ने टीचर्स की कमी का मुद्दा उठाया

पटना, एजेंसी। मानसून सत्र के दूसरे दिन जदयू विधायक श्याम रजक ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल पर मंत्री लखेंद्र कुमार के जवाब से असंतुष्टी जताते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराम अंबेडकर स्कूलों में 62 फीसदी शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी।

इस पर मंत्री लखेंद्र कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि स्कूलों में 3456 शिक्षक हैं। 91 विद्यालय अभी संचालित हो रहे हैं। माध्यमिक में 1456 पद स्वीकृत हैं। उच्च माध्यमिक में 950 पद स्वीकृत हैं। कुल 2406 पद स्वीकृत हैं। 1290 शिक्षक कार्यरत हैं। टीआरई-4 के जरिए बीपीएससी को वैकेंसी के लिए भेजा गया है। श्याम रजक ने कहा- कब होगा क्या होगा इसकी समय सीमा बताइए। मंत्री लखेंद्र कुमार ने कहा, आपकी चिंता बिल्कुल सही है। बीपीएससी जैसे ही बहाली करेगी शिक्षक बहाल हो जाएंगे। दोनों के बयानों के बीच अचानक सीएम सम्राट खड़े हुए और कहा कि मैं शिक्षा विभाग को इसे देखने के लिए कह रहा हूं। 1 महीने के अंदर यहां शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

पहली पंक्ति में बैठे निशांत कुमार: सदन में प्रश्नकाल चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार विधानसभा में मौजूद हैं। वो पहली पंक्ति में सीएम सम्राट चौधरी के साथ बैठे हैं। सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। विधानसभा पोर्टिको में विपक्षी विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। उनके हाथों में 'भ्रष्टाचार में नंबर वन बिहार', 'अपराध में नंबर वन बिहार' जैसे स्लोगन वाली तख्तियां दिखीं। माकपा विधायक अजय कुमार गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामला, वोट चोरी मामला, पेपर लीक जैसे मामलों में मोदी जी की सरकार चुप है। जो स्टूडेंट के राइट्स है, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे खत्म किया जा रहा है। सदन पहुंचे अनंत सिंह ने कहा, मैने आगे चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। जैसे मैं नीतीश जी के साथ था, मेरा बेटा निशांत जी के साथ रहेगा। वो बेहतर काम कर रहे हैं।

87383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, सदन के पटल पर रखे गए 12 विधेयक : बिहार विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सप्लीमेंट्री बजट सदन में पेश किया गया। 87383 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्लीमेंट्री बजट से 30000 करोड़ अधिक है। वार्षिक स्कीम मध्य में 57077195 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध में मद में 30265199 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक स्कीम मध्य में 57077195 करोड़: उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 87383143 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया है, जिस पर चर्चा होगी और फिर पास होगा। सप्लीमेंट्री बजट में वार्षिक स्कीम मध्य में 57 हजार 77195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से वार्षिक स्कीम मद में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 32707123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे अधिक 9335135 करोड़ 'जी राम जी' योजना के लिए है। 334211212 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए, 3308169 करोड़ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए और 2732 करोड़ रुपये सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावे 2780 करोड़ 94 लाख रुपये आंगनबाड़ी पोषण 2.0 कार्यक्रम के लिए, 2100111 करोड़ अमृत 2.0 योजना के लिए, 13591712 करोड़ मध्यान भोजन योजना के लिए, 1150 करोड़ आयुष्मान भारत के लिए प्रावधान किया गया है।

वहीं, 682167 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। 680 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम में 24377172 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे अधिक 6710123 करोड़ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए, 3665100 करोड़ सड़क और पुल के निर्माण के लिए, 1147184 करोड़ विकलांगता पेंशन के लिए, 105614 करोड़ लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, 952 करोड़ पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए, 940 करोड़ पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति योजना के लिए, 500 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए प्रावधान किया गया है। 927 करोड़ रुपये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना और बालिका पोशाक योजना के लिए भी राशि दी गई है तो वहीं 100 करोड़ रुपये हवाई अड्डा के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 30265199 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 13550 करोड़ आकस्मिकता निधि के लिए, 994134 को रुपये मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के लिए, 265815 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं के लिए, 2423147 करोड़ रुपये वेतन के लिए, 747198 करोड़ के पंचायती राज संस्थाओं के लिए बकाया राशि के राहत प्रावधान किया गया है। वहीं, केन्दीय क्षेत्र स्कीम के तहत 39148 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3615 करोड़ रुपये जनगणना के लिए, 0144 करोड़ रुपये महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध को रोकने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।

आवेदन से वंचित दंपती शिक्षकों को मिला दो सप्ताह का समय, हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर दिलाई बड़ी राहत

लखनऊ, एजेंसी। यूपी में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से सोमवार को परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण 2026-27 के मामले में आवेदन से वंचित दंपती शिक्षकों, दिव्यांग एवं अन्य पात्र शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इन्हें आवेदन के लिए दो सप्ताह का और समय दिया है। कोर्ट को बताया गया कि 20 जून के बाद जारी स्पष्टीकरण एवं पीटीआर के कारण कई शिक्षक आवेदन नहीं कर सके थे, जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लिया।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश ज्योति कुशवाहा एवं चार अन्य शिक्षकों की याचिका पर दिया। इसमें शिक्षक दंपती समेत अन्य पात्र शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने 22 जून के सर्कुलर से प्रभावित शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन देने का समय सोमवार से दो सप्ताह बढ़ा दिया है।

अदालत ने कहा कि अगर, याचीगण या उनके समान अन्य शिक्षक इसके लिए दो सप्ताह में आवेदन करें तो उनके मामले को कानून के अनुसार गौर करके निस्तारित किया जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों को अखबारों/वेबसाइट पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इन निर्देशों के साथ याचिका निस्तारित कर दी।

प्रदेश में खुला माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का मौका

21252 पदों पर होंगी नियुक्तियां

लखनऊ, एजेंसी। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के ई-अधियाचन पोर्टल पर कुल 21252 रिक्त पदों का अधियाचन अपलोड कर दिया। इनमें प्रवक्ता (पीजीटी) एवं संलग्न प्राइमरी सहायक अध्यापकों के 3512 पद तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के 17740 पद शामिल हैं।

पीजीटी के 2,615 और प्राइमरी सहायक अध्यापकों के 987 पदों का अधियाचन भी पोर्टल पर दर्ज किया गया है। इससे पहले 4,512 सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 2,643 रिक्त पदों का अधियाचन भी अपलोड किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने अधियाचन अपलोड होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है।

भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद : प्रवक्ता और प्राइमरी अध्यापकों के अधियाचन अपलोड होने से छात्रों में उम्मीद जगी है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने में जुट सकता है। सूत्रों के अनुसार, चयन आयोग पहले टीजीटी-पीजीटी और अन्य पदों पर भर्ती शुरू करेगा।

याची शिक्षकों को मिलेगा प्रधानाध्यापक के वेतन का तीन साल का एरियर : परिषदीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के खाली पद का कार्यभार संभाल रहे ऐसे सहायक अध्यापक जिन्होंने बकाया वेतन देने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। याचिका दाखिल करने की तिथि से उन्हें पिछले तीन साल का बकाया वेतन एरियर के रूप में दिया जाएगा। इस संबंध में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा है कि अगर किसी बीएसए द्वारा किसी याचिकार्ता शिक्षक को प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो। वहीं उस सहायक अध्यापक की ओर से प्रधानाध्यापक का वेतन प्राप्त करने के लिए बीएसए को प्रार्थना पत्र भी दिया गया हो। ऐसी स्थिति में बीएसए तथ्यात्मक रूप से जांच करेंगे कि क्या सहायक अध्यापक के रूप में शिक्षक ने पांच वर्ष का अनुभव पूरा कर लिया है? क्या वह वास्तव में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो याचिकाकर्ता को प्रधानाध्यापक के पद का बकाया वेतन याचिका करने की तारीख से अधिकतम तीन साल का ही दिया जाएगा। भले ही वह इससे ज्यादा समय से इस पद पर कार्य कर रहे हों।

अब एआई बताएगा कौन-सा गहना आप पर लगेगा सबसे खूबसूरत, बस करना होगा एक काम

लखनऊ, एजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अब सराफा कारोबार की तस्वीर बदलने जा रहा है। ग्राहक अब किसी ज्वेलरी को खरीदने से पहले उसे अपनी तस्वीर पर पहनकर देख सकेंगे। इतना ही नहीं, एआई उनके चेहरे की बनावट, पहनावे, अवसर और बजट के आधार पर उपयुक्त आभूषण, मेकअप, हेयर स्टाइल और परिधान तक सुझाएगा। इंडिया गोल्ड मेटावर्स (आईजीएम) की ओर से विकसित एलांजिया नामक एआई आधारित डिजिटल ज्वेलरी मार्केटप्लेस की शुरुआत यूपी से की जा रही है। यह एआई-संचालित क्यूरेटेड ज्वेलरी मार्केटप्लेस है जहां ग्राहक घर बैठे अलग-अलग ज्वेलर्स के आभूषण स्वयं पर वर्चुअल रूप से पहनकर देख सकेंगे।

ग्राहक एप पर सेल्फी या फोटो अपलोड करें : आईजीएम के प्रतिनिधि चेतन भंडारी ने बताया कि ग्राहक एप पर सेल्फी या फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद एआई उस फोटो पर विभिन्न हार, झुमके, कंगन और अन्य आभूषण वास्तविक रूप में दिखाएगा। यदि ग्राहक शादी, रक्षाबंधन, पार्टी, त्योहार या किसी अन्य अवसर के लिए ज्वेलरी तलाश रहे हैं तो एआई उसी के अनुरूप विकल्प सुझाएगा।

यह भी बताएगा कि हल्की ज्वेलरी ज्यादा फबेगी या भारी, किस रंग की ड्रेस और किस तरह का मेकअप उपयुक्त रहेगा। बजट बताने पर उसी सीमा के भीतर विकल्प भी सामने आएंगे।

सराफा कारोबारियों का पंजीकरण शुरू : उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्राफा कारोबारियों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। शुरुआती चरण में लगभग 250 ज्वेलर्स के जुड़ने के बाद यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए सर्राफा संगठनों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी में भरोसा बढ़ाने के लिए सत्यापन की अलग व्यवस्था है। ग्राहक द्वारा ऑर्डर किए गए आभूषण को पहले हॉलमार्क जांच केंद्र भेजा जाएगा।

ज्वेलरी बिक्री का तरीका बदल सकता है : शुद्धता प्रमाणित होने के बाद उसकी डिलीवरी की जाएगी। भंडारी के मुताबिक बाजार में नकली हॉलमार्क की शिकायतों को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने दावा किया कि सोने की शुद्धता जांचने के लिए एक उन्नत मशीन भी विकसित की गई है। सर्राफा कारोबारियों का मानना है कि यदि यह तकनीक व्यापक स्तर पर अपनाई जाती है तो ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह की ज्वेलरी बिक्री का तरीका बदल सकता है।

इंडिगो का विमान वाराणसी डायवर्ट

करीब एक घंटा 14 मिनट बाद दोबारा भरी उड़ान

वाराणसी, एजेंसी। कोलकाता एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण सोमवार को गुवाहाटी से कोलकाता जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। विमान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से अनुमति मिलने के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की।

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-729 गुवाहाटी से कोलकाता जा रही थी। कोलकाता में खराब मौसम के कारण विमान को निर्धारित समय पर उतरने की अनुमति नहीं मिल सकी। इसके बाद पायलट ने विमान को वाराणसी एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट किया। विमान ने शाम करीब 4:26 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। विमान में 173 यात्री और चार क्रू सदस्य सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित रहे। इस दौरान यात्रियों को विमान के भीतर ही रखा गया। मौसम सामान्य होने के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर विमान ने करीब एक घंटा 14 मिनट बाद, शाम लगभग 5:40 बजे वाराणसी से कोलकाता के लिए दोबारा उड़ान भरी। अधिकारियों के अनुसार, खराब मौसम के कारण एहतियातन विमान को वाराणसी डायवर्ट किया गया था। पूरी प्रक्रिया सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए संपन्न कराई गई।

पटना से सोमनाथ आस्था यात्रा शुरूः

सीएम सम्राट चौधरी ने 1100 श्रद्धालुओं से भरी विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

पटना, एजेंसी। बिहार से सोमनाथ आस्था यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पाटलिपुत्र जंक्शन से विशेष ट्रेन सोमनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस विशेष ट्रेन में 1100 से ज्यादा श्रद्धालु और यात्री सवार होकर भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा।

पाटलिपुत्र जंक्शन पर उत्सव का माहौल: पाटलिपुत्र जंक्शन पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सोमनाथ यात्रियों को कलश के साथ-साथ भगवा रंग के गमछे प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद ट्रेन के बोगी में जाकर सोमनाथ यात्रियों से मुलाकात किया है। स्टेशन परिसर श्रद्धालुओं के जयकारों, हर-हर महादेव की गूंज और धार्मिक उत्साह से गूंज उठा। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था।

बिहार के कई जिलों से संगठन हुए रवानाः इस भक्तिमय माहौल में ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस विशेष ट्रेन को हरा झंडा दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि इस विशेष ट्रेन से बिहार के कई जिलों के भाजपा कार्यकर्ता और कई संगठनों से जुड़े लोग सोमनाथ यात्रा पर गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने परिवारों के साथ स्टेशन पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की।

कई सांसद और विधायक रहे मौजूदः इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सहित कई सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने यात्रियों का स्वागत किया और उन्हें सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है।

सोमनाथ बाबा की कृपा से गुजरात का विकास: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज से 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, उस समय उद्घाटन के लिए कोई नहीं गया था। उस समय बिहार का बेटा डॉ। राजेंद्र प्रसाद ने जाने का काम किया था। सोमनाथ मंदिर से गुजरात का काफी विकास हुआ। एक समय था जब गुजरात में समुद्री डाकू और आर्थिक स्थिति खराब थी। गुजरात सरकार ने समुद्र को ताकत बनाया। आज सोमनाथ बाबा के आशीर्वाद से गुजरात आगे बढ़ रहा है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और रेलवे की व्यवस्था: वहीं ट्रेन रवाना होने से पहले स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। ट्रेन के प्रस्थान के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान सोमनाथ के जयकारे लगाए और कई यात्रियों ने इस पहल के लिए सरकार एवं रेलवे का आभार भी व्यक्त किया। धार्मिक आस्था और जनसहभागिता से जुड़े इस आयोजन ने जंक्शन को उत्सव जैसा माहौल दे दिया।

तीर्थ यात्रियों में खुशी: भागलपुर से आये तीर्थयात्री अनुज कुमार सिंह ने कहा यात्रा की शुरुआत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम सम्राट चौधरी और पर्यटन मंत्री को धन्यवाद है। बिहार से सोमनाथ यात्रा की शरुआत कर सम्राट चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया है।

वर्ष 2020 के प्रदर्शन में पंजाब के सीएम मान पर भीड़ को उकसाने का कोई आरोप नहीं : सुप्रीम कोर्ट

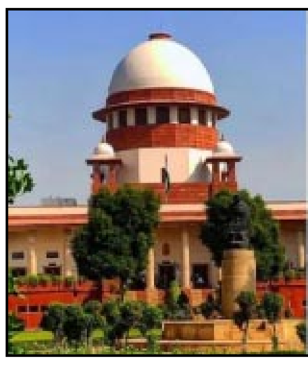

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से कहा कि वर्ष 2020 में चंडीगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ हुए प्रदर्शन के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित आरोपियों के खिलाफ भीड़ को उकसाने का कोई आरोप नहीं है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने चंडीगढ़ प्रशासन की अपील पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के माध्यम से पेश हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इस मामले में मान और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था। पीठ प्रदर्शन मार्च से जुड़े मामले में प्राथमिकी और आरोपपत्र रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली प्रशासन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने पूछा कि केवल मान और अन्य की मौजूदगी को आपराधिक साजिश रचने का आधार कैसे माना जा सकता है। पीठ ने कहा कि उनके (मान) खिलाफ भीड़ को उकसाने का कोई आरोप नहीं है। इस पर विधि अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को उकसाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ इन याचिकाओं पर 30 जुलाई को सुनवाई करेगी, जिस दिन प्रशासन की दूसरी याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले पीठ ने कहा था कि वह बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ वर्ष 2020 के प्रदर्शन से जुड़े मामले में मान और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने तब कहा था, लोकतंत्र में हर कोई नारेबाजी करता है। अब जबकि वह (मान) एक जिम्मेदार पद पर हैं, हमें विश्वास है कि वह अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि यदि आप मामले के गुण-दोष के आधार पर बहस करना चाहते हैं तो हम सुनेंगे, अन्यथा हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने इससे पहले कहा था कि आप नेताओं के खिलाफ प्रथम ष्टया कोई मामला नहीं बनता और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जिन धाराओं के तहत आरोप लगाये गये हैं, उनके आवश्यक तत्व इस मामले में मौजूद नहीं हैं। अदालत ने इसके साथ ही आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 332 (लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 353 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र को रद्द कर दिया था। यह प्राथमिकी वर्ष 2020 में कांस्टेबल मनप्रीत कौर की शिकायत पर दर्ज की गयी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में आप के प्रदर्शन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा, गुरमीतसिंह मीत हेयर, बलजिंदर कौर, अमन अरोड़ा और अन्य ने करीब 750-800 कार्यकर्ताओं को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सेक्टर-2 स्थित आवास की ओर मार्च करने के लिए उकसाया था। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन-कारियों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार किये जाने के बाद पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मियों को साधारण चोटें आयीं।

रिची मेहता की *फूलन* टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगी प्रदर्शित

मुंबई, 21 जुलाई (भा)। फिल्मकार रिची मेहता की फिल्म फूलन का विश्व प्रीमियर 51वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) में होगा। यह फिल्म चंबल की कुख्यात दस्यु से नेता बनीं फूलन देवी के जीवन पर आधारित है। एक विज्ञप्ति के अनुसार इस हिंदी फिल्म का प्रदर्शन 16 सितंबर को प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर में महोत्सव के विशेष प्रस्तुति खंड के तहत किया जाएगा। रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का निर्माण नमः पिक्चर्स के बैनर तले शरीन मंत्री केडिया, किशोर अरोड़ा, कंवल कोहली और मेहता ने किया है। वर्ष 1997 में प्रकाशित पुस्तक आई, फूलन-द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज़ बैंडिट क्वीन से प्रेरित यह फिल्म फूलन देवी के जीवन के उस निर्णायक अध्याय को पर्दे पर उतारती है, जब उन्हें मारने के इरादे से हजारों हथियारबंद लोगों ने एक गांव को घेर लिया था। भारत के ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म गरीब घर की 17 वर्षीय लड़की के सफर को दर्शाती है, जो आगे चलकर देश की सबसे कुख्यात दस्युओं में से एक बन गई। निर्माताओं के अनुसार फिल्म की कहानी 2,000 से अधिक हथियारबंद लोगों द्वारा किये गये 48 घंटे तक चले भीषण घेराव की घटना पर केंद्रित है। महोत्सव में प्रदर्शन के बाद फूलन का प्रीमियर प्राइम वीडियो पर होगा। फिल्म में स्नेहा कुमारी ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पचौरी और देव दत्त बुधोलिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। दुनिया के प्रमुख फिल्म आयोजनों में शामिल टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 10 से 20 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।

अरावली पर्वतमाला

न्यायालय की ओर से गठित समिति ने सुझावों के लिए 21 दिनों की समय-सीमा तय की

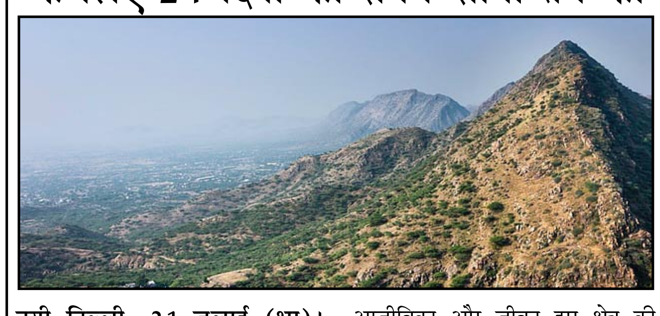

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भा)। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित अरावली समिति ने पर्वत श्रृंखला से जुड़े विभिन्न विषयों पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से उनके विचार, सुझाव और राय मांगी है।अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से तय करने और इसके दायरे को परिभाषित करने के संबंध में केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट की निष्पक्ष समीक्षा के लिए 25 मई को इस उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था।पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों के अलावा पर्यावरणविदों, खनन का पट्टा रखने वालों और स्थानीय समुदायों सहित सभी पक्षों से सुझाव आमंत्रित किये हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनकी आजीविका और जीवन इस क्षेत्र की प्राकृतिक जैव विविधता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि लोग इस सूचना के जारी होने के 21 दिनों के भीतर आधिकारिक गूगल फार्म अथवा ई-मेल के माध्यम से अपनी राय भेज सकते हैं। यदि संभव हो तो सुझावों के साथ उनसे जुड़े दस्तावेज़ या ऐसे प्रमाण भी संलग्न किये जा सकते हैं, जिनकी सत्यता की जांच की जा सके।यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब समिति में मुख्य रूप से पूर्व सरकारी अधिकारियों के शामिल होने के कारण इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।इस समिति को 31 अगस्त तक अपनी समीक्षा रिपोर्ट सौंपनी है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।

सुनिश्चित करें तृणमूल कांग्रेस के ममता गुट की शहीद दिवस रैली की सुरक्षा

कोलकाता, 21 जुलाई (भा)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज शहर की पुलिस को निर्देश दिया कि वह शहीद दिवस रैली के आयोजन के लिए तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी नीत खेमे की सुरक्षा सुनिश्चित करे। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने कार्यक्रम के मंच में तोड़फोड़ के ममता खेमे के आरोपों पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। पीठ ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) से 31 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने यह भी निर्देश दिया कि आज रात नौ बजे तक मंच और रैली से जुड़ा अन्य सामान हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस मंच को हटाये जाने और सामान ले जाए जाने के दौरान आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करेगी। ममता खेमे ने आज यह आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि कोलकाता में बिरला तारामंडल के सामने उसके शहीद दिवस रैली स्थल पर तोड़फोड़ की गयी। ममता खेमे ने बताया कि उसने इस सिलसिले में मध्यरात्रि को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती के समक्ष एक तत्काल याचिका दायर की थी। ममता खेमे के वकील अर्का नाग ने अदालत से मामले में तुरंत दखल देने और 15 जुलाई के आदेश में बदलाव करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आज सुबह उपद्रवियों ने मंच में तोड़फोड़ की और लाउडस्पीकर के कनेक्शन काट दिये। नाग ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैली स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के उच्च न्यायालय के 15 जुलाई के निर्देश के बावजूद मंच निर्माण सामग्री और बिजली उपकरण उपलब्ध कराने वाले लोगों को धमकियों का सामना करना पड़ा।

कर्नाटक सरकार ने आर्ट ऑफ लिविंग के भूमि अतिक्रमण की जांच के लिए बनायी एसआईटी

बेंगलुरु, 21 जुलाई (भा)। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु दक्षिण तालुक के कग्गलिपुरा गांव और उसके आस-पास सरकारी जमीन पर श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग, उससे संबंधित संगठनों और अन्य पक्षों के कथित कब्जे की व्यापक जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। समिति को तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। राजस्व विभाग ने कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम, 1964 और कर्नाटक भूमि कब्जा रोक अधिनियम, 2011 के तहत 17 जुलाई को यह आदेश जारी किया था, जिसे मंगलवार को राजस्व मंत्री के कार्यालय ने साझा किया। क्षेत्रीय आयुक्त अम्मन आदित्य बिस्वास की अध्यक्षता वाली एसआईटी में वरिष्ठ राजस्व अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, मुकदमेबाजी प्रबंधन सलाहकार के रूप में काम कर रहे एक सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारी शामिल हैं। येलाहंका के तहसीलदार कलीमुल्ला को सदस्य-सचिव बनाया गया है। आदेश के अनुसार एसआईटी कग्गलिपुरा और आस-पास के गांवों के सर्वे नंबर 46 से जुड़े आरोपों की जांच करेगी। इसमें वेद विज्ञान महा विद्यापीठ संस्थान, सुमेरु ग्लोबल सपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सुमेरु रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, रिट याचिका में अन्य प्रतिवादियों और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ दावों की जांच शामिल है। इसमें कहा गया है कि अक्तूबर 2025 में भूमि अभिलेखों के सहायक निदेशक द्वारा किये गये सर्वेक्षण से प्रथम ष्टया पता चला है कि द आर्ट ऑफ़ लिविंग के ट्रस्टियों ने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सरकारी पट्टा समझौतों और भूमि अनुदान प्राप्तकर्ताओं के साथ व्यवस्थाओं (जिसमें कथित तौर पर संदिग्ध अनुदान दस्तावेज भी शामिल हैं) के माध्यम से 290 एकड़ से अधिक सरकारी गोमाला (चरागाह) भूमि पर व्यवस्थित रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कब्ज़ा किया था।

स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी करने में कुछ भी गलत नहीं : जी. परमेश्वर

बेंगलुरु, 21 जुलाई (भा)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी राज्य सरकार के फैसले का बचाव करते हुए आज कहा कि यह पहल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में वास्तविक निवासियों की मदद के लिए की गयी है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ये प्रमाणपत्र उन लोगों के लिए लाभकारी होंगे, जो एसआईआर के दौरान मांगे जा रहे पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र से जुड़ी प्रक्रिया पूरी तरह कानून के अनुसार की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आवेदकों के कर्नाटक में जन्म के आधार पर स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी करने का फैसला किया है। (एसआईआर की प्रक्रिया में) ज्यादातर लोगों से 2002 की मतदाता सूची का विवरण मांगा गया है। करीब 50 से 60 प्रतिशत लोगों के पास ऐसे रिकॉर्ड हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के पास ये रिकॉर्ड नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्थायी निवास प्रमाणपत्र मददगार साबित होगा। परमेश्वर ने कहा कि तहसीलदार पहले भी जाति प्रमाणपत्र जारी करते रहे हैं और सरकार की इस पहल की आलोचना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमें इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना होगा। यदि आवेदक यह प्रमाण देते हैं कि वे 10 वर्षों से कर्नाटक में रह रहे हैं, तो उन्हें प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। क्या हम अपनी बेटियों की शादी बांग्लादेशियों से कर सकते हैं? नहीं। हम न तो केंद्र सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और न ही किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हम पूरी तरह कानून के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में सूखे की स्थिति पर उन्होंने कहा कि फैसला किसानों और आम लोगों के हित में होना चाहिए। यह उन लोगों की भी सहायता करने वाला होना चाहिए, जिन्हें रोजगार न मिल पाने के कारण काम की तलाश में पलायन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्तों को पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे तालुकों में सूखे जैसी स्थिति का आकलन करें, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पृष्ठ 1 का शेष

असम में बाढ़ से...

नदी की स्थिति गंभीर बाढ़ की श्रेणी में दर्ज की गयी। इसके अलावा जोरहाट के नीमातीघाट में ब्रह्मपुत्र और डिब्रुगढ़ के खोवांग में बूढ़ीदिहिंग नदी भी उफान पर हैं। कल राज्य के 15 जिलों में बाढ़ से 3.63 लाख से अधिक लोग प्रभावित थे। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने बताया कि बचाव एजेंसियों ने नौकाओं की मदद से विभिन्न इलाकों से 9,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमें शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिलों में तैनात हैं, जबकि राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें लखीमपुर, तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रुगढ़, शोणितपुर, नगांव, मोरीगांव, होजाई, कामरूप मेट्रो, कामरूप, नलबाड़ी और बरपेटा जिलों में राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। एएसडीएमए के अनुसार राज्य में 52 राहत शिविर संचालित किये जा रहे हैं, जहां 12,720 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ के कारण 14,411.267 हेक्टेयर कृषि भूमि भी जलमग्न हो गयी है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी मंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों को भी मौके पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि शिवसागर जिले के सिमलुगुड़ी शहर और आसपास के इलाकों में भीषण बाढ़ के कारण सिमलुगुड़ी-नामतियाली और सिमलुगुड़ी-सेलेंगहाट खंडों पर ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गयी हैं। एनएफआर ने कहा कि रेल सेवाओं में व्यवधान से प्रभावित यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेन चलायी जा रही हैं। एनएफआर के अधिकारी ने कहा कि ये अतिरिक्त विशेष ट्रेन शुक्रवार तक चलेंगी और इनके जरिए फंसे हुए यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मारियानी और गुवाहाटी के बीच कुछ अन्य एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन भी जारी है।

अपील प्रक्रिया शुरू करने...

उलेमा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14ए और इसके साथ पढ़े जाने वाले 2003 के नियमों के नियम 13 के तहत असम में प्रकाशित अंतिम एनआरसी में शामिल सभी व्यक्तियों को तुरंत राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करें। याचिका में यह भी अपील की गयी है कि असम में प्रकाशित अंतिम एनआरसी से बाहर किये गये लोगों के लिए अधिकारियों को अपील प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाए।

सेना ने...

गया है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ करीबी समन्वय बनाते हुए सेना के जवान उफनती नदियों में मोटरबोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। विशेष इंजीनियरिंग उपकरणों और जीवनरक्षक दवाओं से लैस यह दल फंसे हुए लोगों, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और असहाय नागरिकों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। फंसे हुए लोगों को निकालने के साथ ही सेना प्रभावित परिवारों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और जरूरी राहत सामग्री भी उपलब्ध करा रही है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के समय देशवासियों की मदद करना सेना की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हालांकि बाढ़ का पानी अब धीरे-धीरे उतरने लगा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना ऊपरी असम के प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए राहत अभियानों में मुस्तैदी से जुटी हुई है।

युवाओं के भविष्य...

की सहायता से यथासंभव कड़ी सजा दिलायी जानी चाहिए, ताकि ऐसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ नजीर पेश करने वाली कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए सख्त कार्रवाई की गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को दलगत भावना से ऊपर उठकर मिलकर काम करना होगा। यह राजनीति का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित का विषय है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों की बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास...

तो पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और कई अन्य नेताओं को बलपूर्वक हिरासत में लिया और उन्हें बस में बैठाकर ले गयी। पुलिस द्वारा उठाये जाने के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जोरदार प्रतिरोध भी किया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, इंसाफ की लड़ाई नहीं रुकने वाली है। उन्होंने कहा कि मोदी जी, हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके न रुकेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को बलपूर्वक और घसीटते हुए उठाया गया, जिससे उन्हें चोट भी आयी। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों को पुलिस ने घसीटकर हिरासत में लिया तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी बलपूर्वक वहां से ले जाया गया। खड़गे ने कहा कि तानाशाह सरकार डर कर कांप रही है और सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर करोड़ों बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि 150 से अधिक पेपर लीक हुए और 25 बच्चों की जान चली गयी और जब छात्र न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया और डंडे बरसाये कये। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि संसद के गेट बंद कर सांसदों को कैद किया गया, साझा विपक्ष की चर्चा की मांग नहीं मानी गयी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया गया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों पर हुए कथित अत्याचार के मुद्दे पर मौन रहे, जबकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के नियंत्रण में है और विपक्ष की मांग के बावजूद गृह मंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब जब कांग्रेस और विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे हैं, तो उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है। खड़गे ने सवाल किया कि ये कौन सा लोकतंत्र है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि तानाशाही का दूसरा नाम अमितशाही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) की नेता सुप्रिया सुले भी इस धरना में शामिल हुए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी और कई अन्य सांसद अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए 7 लोक कल्याण मार्ग के निकट पहुंच गये और वहीं धरने पर बैठ गये। धरने में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी तथा छात्रों को न्याय दो जैसे नारे लगाये। धरना शुरू होने के कुछ देर बाद ही लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, शशिकांत सेंथिल और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने हाथों में हथकड़ियां पहनकर छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का सांकेतिक विरोध किया। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन मौके पर पहुंचे तथा राहुल गांधी से धरना समाप्त करने का आग्रह किया। इस मुलाकात के बाद सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी को नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए आश्वासन दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी रख दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिक्ष का रवैया लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि यदि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है, तो वह धरना समाप्त कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व से अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को यह आश्वासन दिया गया कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सिंह ने आरोप लगाया कि इसके बाद राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी रख दी और कहा कि अब उनकी दो मांगें हैं। सिंह ने कहा कि जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि उन्होंने पहले केवल संसद में चर्चा की मांग की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब उनकी मांगें बदल गयी हैं। धरना शुरू होने के कुछ देर बाद राहुल गांधी ने छात्रों को न्याय दिलाने के इच्छुक लोगों से धरने में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है और सरकार को इस मामले में जवाबदेही लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार न तो घटना की जवाबदेही लेना चाहती है और न ही संसद में इस पर चर्चा की अनुमति दे रही है।

पिछले पांच सालों...

चूक करने वाले 15,577 लोगों के खिलाफ वसूली के लिए मुकदमे दायर किये गये थे और 10,894 मामलों में संबंधित कानून के तहत कार्रवाई शुरू की गयी। इसके अलावा 7,173 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयीं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 31 मार्च, 2026 तक जानबूझकर चूक करने वालों से कुल 52,360 करोड़ रुपये वसूल किये हैं। चौधरी ने कहा कि रिजर्व बैंक की जानकारी के अनुसार पिछले पांच वित्त वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 1,42,112 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गयी। वाणिज्यिक बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक शामिल हैं। चौधरी ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि वित्त वर्ष 2026 में रिकवरी एजेंसियों के संबंध में बैंकों के खिलाफ 18,021 शिकायतें मिलीं, जो पिछले साल की 8,623 शिकायतों से दोगुनी से भी अधिक हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने वाले लोगों को जबर्दस्ती वसूली से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों और जवाबदेही को मजबूत करने के मकसद से रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर, 2025 को एक अधिसूचना के जरिए बैंकों को निर्देश दिया है कि वे लोगों को अनुचित तरीके से परेशान नहीं करें और रिकवरी एजेंट रखने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाएं।

विपक्ष के भारी...

पर रोक लगेगी, शादी और तलाक दोनों का पंजीयन अनिवार्य होगा तथा विवाहित या अविवाहित माता-पिता के जैविक या उनके द्वारा गोद लिये जाने समेत सभी प्रकार के बच्चों को उत्तराधिकार में समान कानूनी दर्जा मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर इस विधेयक का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वह ऐसा कर रही है। यादव ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी भी करार दिया और कहा कि इस विधेयक के दायरे से आदिवासी समाज को बाहर रखा गया है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने कल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन यह विधेयक पेश किया था, जिस पर आज सदन में चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत में ही कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य आरिफ मसूद ने विधेयक में संशोधन पेश किया और अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मध्यप्रदेश में अभी समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे अधिक महत्वपूर्ण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजना चाहिए। इसके बाद सभी कांग्रेस सदस्य आसन के निकट आ गये और नारेबाजी आरंभ कर दी। हंगामे और नारेबाजी के बीच ही मुख्यमंत्री के जवाब के बाद तोमर ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले राजधानी भोपाल के बाहरी इलाके जगदीशपुर (पूर्व में इस्लामपुर) में रविवार को आयोजित मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गयी थी।

छह प्रतिशत अभ्यर्थी...

किया है कि यूजीसी नॉन-नेट फेलोशिप की राशि वर्ष 2006 से अब तक 8,000 रुपये प्रति माह पर ही बनी हुई है। मजूमदार ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के आधार पर जेआरएफ प्रदान करता है। नेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से छह प्रतिशत ही सहायक प्राध्यापक के लिए योग्य होते हैं और इन्हीं पात्र अभ्यर्थियों में से यूजीसी हर साल 11,750 को जेआरएफ प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कई मंत्रालय और संस्थान पीएचडी करने वाले शोधार्थियों की सहायता के लिए अलग-अलग फेलोशिप प्रदान करते हैं। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दिव्यांगों और एकल बालिका को विशेष फेलोशिप भी दी जाती है। मंत्री ने कहा कि पीएचडी शोधार्थी विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा विश्वविद्यालयों को मंजूर किये गये शोध कार्यो में शामिल होकर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छात्र बिना किसी आर्थिक सहायता के भी पीएचडी में दाखिला लेते हैं। ऐसे छात्रों की मदद के लिए यूजीसी ने नॉन-नेट फेलोशिप के रूप में आंशिक आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। थरूर ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताया। उन्होंने आज एक्स पर लिखा कि सरकार ने उनके सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के जवाब में केवल मौजूदा यूजीसी फेलोशिप व्यवस्था की सामान्य जानकारी दी गयी है, लेकिन नेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों और जेआरएफ प्राप्त करने वालों के वर्षवार आंकड़े नहीं दिये गये। थरूर ने कहा कि सरकार ने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि पात्र अभ्यर्थियों और उपलब्ध फेलोशिप के बीच बढ़ते अंतर को कम करने, जेआरएफ की संख्या बढ़ाने या पात्रता नियमों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है या नहीं।

अमिताभ ने सर्जरी...

प्रशंसकों से मिलने के तय कार्यक्रम में शामिल हुए थे और पूरी तरह ठीक नजर आये। वह हर सप्ताह अपने घर के बाहर जुटने वाले प्रशंसकों का अभिवादन करते हैं। बच्चन ने पोस्ट में लिखा है कि आप एक सम्मानित चैंपियन हैं और एक दिन आपके सामने हार आ खड़ी होती है। यह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर होता है। कुछ लोग इसका बहादुरी से सामना करते हैं, जबकि कुछ हार मान लेते हैं। जो संघर्ष करते हैं और साहस बनाये रखते हैं, वे हमेशा चैंपियन बने रहते हैं। उन्होंने लिखा कि जो ऐसा नहीं कर पाते, वे समझौता कर लेते हैं और अतीत की उपलब्धियों के सहारे जीते हैं। यह हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पसंद होती है। इनमें से किसी भी विकल्प में कुछ गलत नहीं है।

29 को प्रकाशित होगी...

किये गये सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम सीमा 20 अगस्त रखी गयी है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का औपचारिक प्रकाशन 24 अगस्त को किया जाएगा। आयोग ने यह भी साफ किया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के अलावा 30 जून की मूल अधिसूचना में दिये गये अन्य सभी नियम, शर्तें और प्रावधान पहले की तरह ही अपरिवर्तित रहेंगे।

त्रिपुरा के डीजीपी...

उन्होंने कहा कि हम कानून के अनुसार मामले की जांच करेंगे। हालांकि साहा ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में मामले की जांच कराने की विपक्ष की मांग पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने धनखड़ की मौत को न सिर्फ उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे त्रिपुरा के लिए भी एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं हैं। यह न सिर्फ उनके परिवार के लिए, बल्कि हमारे राज्य के लिए भी अपूरणीय क्षति है। हमारे बीच हमेशा सौहार्दपूर्ण बातचीत होती थी। उनके नेतृत्व में राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ था। साहा ने कहा कि18 जुलाई को पश्चिम त्रिपुरा के आरके नगर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड में शामिल होने के बाद हमने साथ में चाय पी थी। उनकी पत्नी भी हमारे साथ थीं। हमारे बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धनखड़ के साथ यह मेरी आखिरी मुलाकात होगी। डीआईजी रतिरंजन धर ने बताया कि धनखड़ का शव एयर एंबुलेंस के जरिये दिल्ली ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से उनका शव अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव बड़ौत ले जाया जाएगा। कार्यवाहक डीजीपी जीएस राव ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) मंचक इप्पर के नेतृत्व में तीन सदस्यीय दल धनखड़ के शव को लेकर दिल्ली गया है। विपक्षी दल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने लगभग 18 वर्षों तक पूर्वोत्तर राज्य में पुलिस के विभिन्न पदों पर सेवाएं देने वाले धनखड़ की मौत की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1994 बैच के अधिकारी धनखड़ ने नीरव मोदी से जुड़े 13,000 करोड़ के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई जांच और 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े मामले की पुन: जांच का नेतृत्व किया था। धनखड़ को मई 2025 में अतिरिक्त डीजीसी से डीजीपी के पद पर पदोन्नत किया गया था। वह 11 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले थे।

नेपाल सरकार ने...

यह 17 जुलाई से लागू हुआ था। शाह ने कहा कि इस कर का उद्देश्य कर आधार बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना था। हालांकि जनता, मीडिया और राजनीतिक दलों की ओर से तीखी आलोचना के बाद इस पर अमल रोक दिया गया। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सरकार जनकेंद्रित है और लोगों के भरोसे एवं अपेक्षाओं पर आधारित है। हमारा मुख्य लक्ष्य सुशासन स्थापित करना और सभी नागरिकों को बेहतर जीवन देना है। सरकार जनता की चिंताओं को सुनते हुए एक समतापरक समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी सरकारी फैसले से जनता असंतुष्ट होती है, तो सरकार उस फैसले में संशोधन के लिए हमेशा तैयार रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने...

के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विवाह के तुरंत बाद दंपति हनीमून मनाने मेघालय गया था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह (सोनम) अपने पति को बहला-फुसलाकर पहाड़ियों के एक सुनसान स्थान पर ले गयी। उसके प्रेमी के जरिए भाड़े पर रखे गये तीन लोग भी उसका पीछा कर रहे थे। अंततः पति की हत्या कर दी गयी, पत्नी भी इसमें शामिल हुई और शव को खाई में फेंक दिया गया। उनकी मृत्यु खाई में फेंके जाने से नहीं हुई थी। मेहता ने कहा कि पहले उनकी (राजा रघुवंशी) हत्या की गयी और उसके बाद शव को खाई में फेंका गया। जांच में यही सामने आया है। इसके बाद आरोपी फरार हो गये। जांच में उन तीन लोगों का भी पता चला, जिन्होंने सोनम की मदद की थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब रिकॉर्ड पर यह भी है कि सोनम के प्रेमी ने उसे सलाह दी कि अब आत्मसमर्पण करना उसके लिए सुरक्षित रहेगा।

आवास क्षेत्र में...

डॉलर था। इसी तरह डेटा सेंटर परियोजनाओं में जनवरी-जून, 2026 के दौरान 83.89 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में इस क्षेत्र में कोई निवेश नहीं हुआ था। कुशमैन एंड वेकफील्ड के कार्यकारी प्रबंध निदेशक (पूंजी बाजार) सोमी थॉमस ने कहा कि विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में पूंजी आवंटन का रुझान अब अधिक स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखायी दे रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यालय क्षेत्र अपनी परिपक्वता, नकदी और स्थिर आय से निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। वहीं, भारत के तेजी से विकसित हो रही डिजिटल अवसंरचना तंत्र का लाभ उठाने के लिए डेटा सेंटर क्षेत्र में भी निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। पूंजी का यह विविधीकरण निवेश परिश्य को और अधिक गहरा तथा मजबूत बना रहा है। थॉमस ने कहा कि 2026 की दूसरी छमाही में भी निवेश गतिविधियां मजबूत रहने की उम्मीद है और घरेलू निवेशक बाजार की गति बनाये रखने में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली छमाही में घरेलू संस्थागत निवेश 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर और विदेशी निवेश 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

डोभाल मिले...

से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। इस वर्ष डोभाल की सऊदी अरब की यह तीसरी यात्रा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि दोनों पक्षों ने क्षेत्र के ताजा घटनाक्रमों तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। बैठक में सऊदी अरब के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री सऊद अल-साती भी मौजूद थे। डोभाल की यह यात्रा ऐसे समय हुई है, जब यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी की घोषणा करते हुए बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में सऊदी अरब के जहाजों को रोकने की बात कही है।

सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त संदेश -अधिकारी बहाने नहीं बनाएं, समय पर काम पूरा कर जनता को राहत पहुंचाएं

राजीविका के संगठन की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट के निर्देश

प्रसूति सहायता योजना का समय पर लाभ नहीं मिलने पर 2 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई

जयपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकास परियोजनाओं को टाइमलाइन में पूरा कर जनता को समय पर लाभ पहुंचाना राज्य सरकार और हर कार्मिक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया कि वे कार्यों में देरी या लापरवाही को लेकर कोई बहाना नहीं बनाएं, बल्कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए विकास कार्यों की गति को तेजी से बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की सातवीं बैठक में सात विभागों की लगभग 15 हजार 890 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पंच गौरव योजना, और ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर की समीक्षा करते हुए यह दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राज उन्नति की गत बैठकों में दिए गए निर्देशों की समीक्षा भी की।

उन्होंने जयपुर रिंग रोड (उत्तरी) परियोजना की समीक्षा करते हुए वन विभाग एवं रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुए इस परियोजना से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान कर शीघ्र कार्य प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना जयपुर में यातायात दबाव कम करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप देकर केन्द्रीय कैबिनेट को अनुमोदन हेतु भिजवाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 11 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से बनने वाली जयपुर नॉर्दन रिंग रोड अजमेर हाइवे एनएच-48 (बगरू) से प्रारंभ होकर जयपुर-दिल्ली एनएच-48 एवं जयपुर-सीकर एनएच-52 से निकलकर जयपुर-बांदीकुई स्पर तक बनेगी।

मुख्यमंत्री ने पंच गौरव कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्य सचिव इसकी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी विस्तार की योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पाद हर जिले की आर्थिक समृद्धि के आधार हैं। इस योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर जिले की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। गत वर्ष जिन जिलों में योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का व्यय कम हुआ है, वे अभी से कार्यों को गति प्रदान करें। साथ ही, प्रत्येक जिले में चिन्हित पंच गौरवों (उपज, उत्पाद, वनस्पति प्रजाति, पर्यटन स्थल एवं खेल) के समग्र विकास, संवर्धन और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने पंच गौरव योजना में कम उपलब्धि वाले जिलों को निर्देश दिए कि वे अपने काम में तेजी लाएं और शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें।

दिसंबर तक सुनिश्चित करें रिम्स का लोकार्पण

एम्स दिल्ली की तर्ज पर आरयूएचएस को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में विकसित करने के काम में आ रही व्यावहारिक बाधाओं को दूर करते हुए इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरयूएचएस में 13 विभागों की सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं के विकास पर 750 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रथम चरण में यहां इस वर्ष के अंत तक लगभग 140 करोड़ रुपये की लागत से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, सीटीवीएस विभागों की सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इस संस्थान के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। दिसंबर माह तक इस संस्थान का लोकार्पण किया जाना सुनिश्चित करें।

राइजिंग राजस्थान में काम शुरू करने वाले निवेशकों का होगा सम्मान

मुख्यमंत्री ने रेलवे की लूणी-समदड़ी-भीलड़ी डबलिंग प्रोजेक्ट, राजसमंद व उदयपुर में नवीन प्रोटीन पशु आहार संयंत्र की स्थापना, कोटपूतली-बहरोड़ में बायोगैस प्लांट की स्थापना सहित राइजिंग राजस्थान समिट से संबंधित निवेश एमओयू की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत जिन निवेशकों ने एमओयू की शर्तों के अनुसार कार्य प्रारंभ कर दिया है, उनका एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया जाए। साथ ही, अन्य निवेशकों को भी जल्द कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिले और रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन हो।

राजीविका के उत्पादों की हो प्रभावी मार्केटिंग

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए डेयरी, टेक्सटाइल, फुटवियर, मिलेट्स, मसाले आदि के 50 नवीन उद्यमों की स्थापना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राजीविका से जुड़ी हुई महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए हर जिले में आयोजित होने वाले हाट बाजारों में उन्हें स्थान उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही, उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने दिल्ली में बीकानेर हाउस, जयपुर में जवाहर कला केन्द्र, नवी मुंबई में राजस्थान हाउस सहित जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर सहित अन्य स्थानों पर भी उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न मेलों एवं त्योहारों के अवसरों पर भी उनके उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए।

टीकाराम जूली का कानून व्यवस्था को सरकार पर हमला, कहा- अपराध होने से पहले प्रभावी कार्रवाई कर वारदात को रोकना पुलिस का काम

अलवर, एजेंसी। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने अलवर की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। जूली ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पुलिस का काम केवल अपराध होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि अपराध होने से पहले अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करके वारदात को रोकना है। उन्होंने कहा कि अलवर में लगातार गंभीर आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद अपनी पीठ खुद थपथपाने में लगी है।

जूली ने भूगोर के छत्र की हत्या, पेट्रोल पंप सेल्समैन पर गोलीबारी, व्यापारी की हत्या, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) अधिकारी के घर हुई लूट और शहर में हुई बड़ी चोरी जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी घटनाएं जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रमाण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की बीट कांस्टेबल व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है और खुफिया एजेंसी (आईबी) तंत्र भी प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा है। खुफिया तंत्र और बीट व्यवस्था मजबूत होती, तो कई वारदातों को होने से पहले रोका जा सकता था।

बाड़मेर में एसीबी की कार्रवाई : पटवारी 15,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर/बाड़मेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय राजस्थान, जयपुर के निर्देश पर बाड़मेर इकाई ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसीबी टीम ने जाल बिछाकर ईटादा पटवार मंडल (तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर) के पटवारी संजयकुमार मीणा को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एसीबी की बाड़मेर चौकी को इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी. परिवादी ने शिकायत में बताया था कि उसने और उसके भाई ने ग्राम ईटादा में स्थित अपनी कृषि भूमि (खेत) का कमर्शियल कन्वर्जन (व्यवसायिक रूपांतरण) करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. इस आवेदन पर तहसीलदार धनाऊ ने मौका जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश पटवारी हल्का ईटादा के नाम जारी किए थे. इसी भूमि का मौका निरीक्षण करने, मौका रिपोर्ट पेश करने और कन्वर्जन की आगे की कार्रवाई में सहयोग करने के बदले पटवारी संजयकुमार मीणा ने रिश्वत की मांग की थी.

एसीबी के मुताबिक, 17 जुलाई 2026 को शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी पटवारी ने परिवादी से कुल 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. इसमें से 5,000 रुपये आरोपी ने उसी समय प्राप्त कर लिए थे और शेष 15,000 रुपये आज (20 जुलाई) लिया जाना तय हुआ था.

शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी रेंज जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस नारायण टोगस के सुपरविजन में ट्रैप की रणनीति तैयार की गई. इसके बाद बाड़मेर एसीबी इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार और पुलिस निरीक्षक देवाराम ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर जाल बिछाया. जैसे ही आरोपी पटवारी संजयकुमार मीणा ने परिवादी से तयशुदा शेष 15,000 रुपये की रिश्वत राशि स्वीकार की, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया. एसीबी द्वारा आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

राजसमन्द में चिकित्सक (कनिष्ठ विशेषज्ञ सामान्य सर्जरी) 1,300 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

राजसमन्द, एजेंसी। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी डॉ पंकज जैन हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ (जनरल सर्जरी) आर. के. चिकित्सालय राजसमन्द को रिश्वत राशि 1300 रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

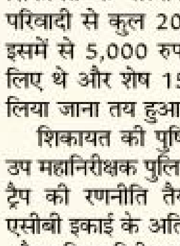

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि ए. सी.बी. चौकी राजसमन्द को परिवादी से एक शिकायत इस आशय की मिली कि 'मेरे लडके की दाहिनी आंख के पास सिस्ट (छोटी गांठ) का आरके राजकीय चिकित्सालय में ऑपरेशन के नाम पर डॉ पंकज जैन द्वारा 2,000 रूपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर डॉ रामेश्वर सिंह उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज, उदयपुर के सुपरवीजन में हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए. सी.बी. चौकी राजसमन्द द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई। जिस पर आरोपी डॉक्टर ने परिवादी से दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के 1800 रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ एवं 500 रूपये मांग सत्यापन की कार्यवाही के दौरान ग्रहण किए गए। रिश्वत राशि मांग सत्यापन के अनुसरण में 1300 रूपये लेते हुए आरोपी डॉ पंकज जैन हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ (जनरल सर्जरी) आर. के. चिकित्सालय राजसमन्द को रंगे हाथों ट्रेप किया गया। मांग सत्यापन के दौरान ग्रहण किए गए 500 रूपये की राशि भी बरामद की गई।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24म7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।

नए निजी स्कूलों की मान्यता के लिए 31 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन

जयपुर, एजेंसी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि राज्य में नए निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए 31 जुलाई से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सरल बनाया जाएगा तथा हर स्तर पर तय समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।

निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया और लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को सरकार के सभी नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मान्यता प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए दिलावर ने निर्देश दिया कि प्रथम स्तर की निरीक्षण समिति सात दिनों के भीतर निरीक्षण पूरा कर अपनी रिपोर्ट जमा करे। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) रिपोर्ट की जांच कर 15 दिनों के भीतर आगे भेजेंगे, जिसके बाद शिक्षा निदेशक मान्यता देने पर अंतिम निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि निरीक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाएं और समिति के गठन से लेकर रिपोर्ट जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूरी हो। अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान पाई गई हर कमी को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए और आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए मान्यता प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन कर सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाएगा, साथ ही नियमों को सरल बनाया जाएगा।

टोंक में शराब की दुकान में घुसकर तेंदुए का हमला, तीन घायल

टोंक, एजेंसी। टोंक जिले के टोडारायसिंह कस्बे में उस समय दहशत फैल गई जब एक तेंदुआ शराब की दुकान में घुस गया, तीन लोगों पर हमला किया और करीब पांच घंटे तक दुकान के अंदर फंसा रहा, जिसके बाद वन विभाग ने उसे बचाया। अधिकारियों के अनुसार, तेंदुए को सबसे पहले सोमवार सुबह करीब 8:45 बजे कस्बे के पास झाड़ियों में देखा गया। स्थानीय वन मित्र राकेश को निवासियों से सूचना मिली और वह तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचे, तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया और करीब 400 मीटर दूर पास की शराब की दुकान की ओर भाग गया। जानवर ने सबसे पहले दुकान के बाहर बैठे फतेह लाल कोली (40) पर हमला किया और फिर दुकान के अंदर घुसकर विक्रेता संजय गुर्जर (25) पर हमला कर दिया। घायल होने के बावजूद संजय ने सूझबूझ का परिचय दिया। भागते ही उन्होंने तुरंत दुकान का शटर गिरा दिया, जिससे तेंदुआ अंदर ही फंस गया और भीड़भाड़ वाले बाजार में आगे नहीं बढ़ पाया।

संजय ने बताया कि मैंने किसी तरह तेंदुए को धक्का देकर भगाया और बाहर निकलने की तरफ भागा। भागते समय मैंने शटर नीचे खींच दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया।

उनके हाथ, कंधे और नाक पर तेंदुए के पंजे से चोटें आईं और बाद में उन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया।

घायलों की पहचान राकेश, वन मित्र, फतेह लाल कोली (40) और संजय गुर्जर (25) के रूप में हुई। राकेश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि संजय और फतेह लाल को आगे के इलाज के लिए रेफर किया गया।

घटना के बाद, वन विभाग ने जयपुर के झालाना से एक विशेष बचाव दल को बुलाया। तेंदुआ दुकान के अंदर ही फंसा रहा, जबकि पुलिस ने इलाके को घेर लिया और लोगों को घटनास्थल के पास जाने से रोक दिया। घटना की खबर फैलते ही भारी भीड़ जमा हो गई।

दोपहर करीब 2 बजे, बचाव दल ने एक ही डार्ट से तेंदुए को सफलतापूर्वक बेहोश कर दिया और उसे सुरक्षित पकड़ लिया, जिससे पांच घंटे का तनावपूर्ण अभियान समाप्त हो गया।

टोंक के सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) अनुराग महर्षि के अनुसार, बचाया गया जानवर पांच साल का नर तेंदुआ है। उन्होंने कहा कि तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने से पहले उसकी चिकित्सा जांच की जाएगी।

सामाजिक सरोकारों के लिए डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ बैंक ऑफ बड़ौदा के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित

मुंबई/उदयपुर, एजेंसी। बैंक ऑफ बड़ौदा के 119वें स्थापना दिवस पर मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर (बीकेसी) में आयोजित भव्य समारोह में मेवाड़ के 77वें श्री एकलिंग दीवान श्रीजी हुजूर डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को सामाजिक सेवा एवं जनकल्याण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ग्रामीण उत्थान, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा भारतीय संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण-संवर्धन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देते हुए विशेषकर युवाओं और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सतत कार्यरत हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रदान किया गया यह सम्मान उनके

सामाजिक सरोकारों, जनसेवा और दीर्घकालीन सामाजिक प्रतिबद्धता का राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सम्मान माना जा रहा है। सम्मान ग्रहण करने के उपरांत डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने संबोधन में कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ उनके परिवार में चार पीढ़ियों का विश्वास और आत्मीयता का संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि अनेक वित्तीय संस्थानों के आकर्षक प्रस्ताव मिलने के बावजूद उनका विश्वास सदैव बैंक ऑफ बड़ौदा पर ही कायम रहा है। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के 119वें स्थापना दिवस पर बैंक परिवार को हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रतिष्ठित संस्था भविष्य में भी उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण के अपने संकल्प के साथ निरन्तर नई ऊँचाइयों को प्राप्त करती रहेगी।

इस भव्य समारोह में बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, विशिष्ट अतिथियों, उद्योग-जगत, सामाजिक क्षेत्र तथा देशभर से आमंत्रित सम्मानित ग्राहकों की गरिमामयी उपस्थिति के साथ ही क्रिकेट जगत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी विशेष रूप से सम्मिलित हुए।

बैंक ऑफ बड़ौदा के इस सम्मान समारोह में देश के कई जाने माने विद्वानों, समाज सेवियों को भी उनकी विशिष्ठ उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया जिनमें

जमुना टुडू (पर्यावरणविद्)

भुवनेश्वर की प्रसिद्ध पर्यावरणविद् श्रीमती जमुना टुडू ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वन संरक्षण को नई दिशा दी है। भारत में 'लेडी टार्जन' के नाम से विख्यात जमुना टुडू को अवैध कटाई रोकने और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं।

स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतरवाने और मारपीट के मामले का एनएचआरसी ने स्वत: संज्ञान लिया

जयपुर, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन खबरों पर संज्ञान लिया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में एक छात्रा के 1,000 रुपए खो जाने के बाद, टीचरों ने छात्राओं की तलाशी ली, उनके साथ मारपीट की और उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर किया। मानवाधिकारों की सर्वोच्च संस्था ने माना कि अगर ये खबरें सच हैं, तो ये पीड़ित छात्राओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसलिए, संस्था ने राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना लिवली गांव के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। वहां एक टीचर ने बताया कि 1,000 रुपए गायब हो गए हैं, जिसके बाद 9वीं और 11वीं क्लास की छात्राओं की तलाशी ली गई और उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया।

रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि तलाशी के दौरान दो टीचरों ने छात्राओं के साथ मारपीट भी की, हालांकि उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला। रिपोर्टों के मुताबिक, घर लौटने पर छात्राओं ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद अगले दिन बड़ी संख्या में माता-पिता विरोध करने के लिए स्कूल पहुंचे। इस बीच, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (सीबीईओ) की रिपोर्ट के आधार पर सीनियर टीचर सरस्वती मीणा को घटना के लिए सस्पेंड कर दिया। स्कूल की वोकेशनल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर वंदना शर्मा को भी उनके काम से हटा दिया गया और सर्विस देने वाली एजेंसी के पास वापस भेज दिया गया।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

गर्भवती महिलाओं के रेफरल सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश

जयपुर, एजेंसी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला को आवश्यकता पड़ने पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य सचिव ने बैठक में गत 24 घंटों के दौरान प्रदेश में हुए प्रसवों की समीक्षा करते हुए संतोष व्यक्त किया कि इस अवधि में कोई गंभीर स्थिति सामने नहीं आई। उन्होंने उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं वाले जिलों के सीएमएचओ से वन टू वन जानकारी ली,जिलों के सीएमएचओ ने बताया कि प्रदेशभर में सभी एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) एवं आशा सहयोगिनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर प्रत्येक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की नामवार सूची तैयार कर संबंधित एएनएम से मैपिंग की गई है। इससे ऐसी महिलाओं की नियमित निगरानी एवं समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया के मामलों की विशेष निगरानी की जाए तथा

त्वरित उपचार के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति में शीघ्र सुधार लाया जाए। इसके लिए सभी आवश्यक दवाइयों, रक्त एवं अन्य चिकित्सकीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि रेफरल की आवश्यकता होने पर संबंधित संस्था प्रभारी 104 अथवा 108 एम्बुलेंस की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा जिस चिकित्सा संस्थान में मरीज को भेजा जा रहा है, वहां पूर्व सूचना देकर उपचार की समुचित तैयारी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित रेफरल प्रणाली मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का महत्वपूर्ण आधार है। बैठक में जनाना अस्पताल की अधीक्षक डॉ. नुपुर तथा एसएमएस मेडिकल कॉलेज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अनिता ने गर्भवती महिलाओं के उपचार प्रबंधन, आपातकालीन देखभाल एवं मानक उपचार प्रोटोकॉल पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में स्थानीय स्तर पर दवाइयों एवं आवश्यक सामग्री की खरीद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) द्वारा निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुरूप करने के निर्देश दिए। साथ ही दवाइयों, टीकों एवं इंजेक्शनों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड चेन प्रबंधन को पूरी सतर्कता के साथ बनाए रखने पर भी जोर दिया। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने निर्देश दिए कि मुख्यालय स्तर से नियुक्त जिला प्रभारी अधिकारी नियमित रूप से एएनएम, सीएचओ एवं बीसीएमओ से संवाद स्थापित करें तथा प्रतिदिन प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा सुनिश्चित करें।

अभिषेक नंबर-1 दूसरे पर गिल

जिम्बाब्वे के खिलाफ T20- में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट

नई दिल्ली। इंग्लैंड दौरा समाप्त होने के बाद भारतीय टीम 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच गई है। 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच यह सीरीज होगी। श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम में संजू सैमसन को नहीं चुना गया है। उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते देखा जाएगा। वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में डेब्यू किया, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। भारतीय टीम इससे पहले जिम्बाब्वे दौरे पर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद गई थी। तब कोच गौतम गंभीर टीम से नहीं जुड़े थे। इस बार भी वह दौरे पर नहीं आए हैं।

अभिषेक ने किया था डेब्यू

वीवीएस लक्ष्मण तब की तरह इस दौरे के लिए अब भी कोच हैं। अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए इसी सीरीज में डेब्यू किया था। शुभमन गिल कप्तान थे। उस सीरीज में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ भी खेले थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन की बात करें तो अभिषेक शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने 5 पारियों में 179 रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने 5 पारियों में 170 रन बनाए हैं।

टॉप-10 में केएल राहुल भी

यशस्वी जायसवाल ने 3 पारियों में 141 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 पारियों में 133 रन बनाए। केएल राहुल के नाम 4 पारियों में 120 रन हैं। संजू सैमसन ने 4 पारियों में 113 रन बनाए हैं। सुरेश रैना ने 2 पारियों में 100 रन बनाए हैं। मुरली विजय ने 4 पारियों में 98 और सूर्यकुमार यादव ने 2 पारियों में 91 रन बनाए हैं।

कुशाग्र का शतक

यश और मनल ने ठोके पचासे

नई दिल्ली। इंडिया अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 के बीच दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। पहले दिन के खेल में 65 ओवर ही हो पाए और शुरुआत में बारिश के कारण मैच प्रभावित रहा। भारतीय टीम की टॉस हारकर पहले खेलते हुए शुरुआत डगमगा गई थी। 0 रन पर भारत ने 2 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद कुशाग्र ओझा ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। वहीं कप्तान यशवर्धन चौहान और मनल चौहान ने अर्धशतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर 253 रन बनाए हैं। श्रीलंका ने इस मैच में टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी चुनी थी। भारतीय टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत बेहद खराब रही। दोनों ओपनर्स खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए। पहले 6 ओवर में भारत ने एक भी रन नहीं बनाया था।

दिग्गज को आया गुस्सा, टीम इंडिया के हेड कोच को घेरा

'रोहित नहीं गौतम की जगह पर सवाल उठने चाहिए'

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में 138 रन की पारी खेलते हुए सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी है। मगर टीम इंडिया की हार के बाद मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत के पूर्व ओपनर ने तो साफतौर पर उनकी जगह पर ही सवाल कर दिया है।

नई दिल्ली। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में 138 रन की बेहतरीन पारी से सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। उन्होंने अपने वनडे करियर के खत्म होने की चल रही अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। जबकि पिछले एक साल में भारत की यह तीसरी बड़ी टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में हार भी है। इसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच और चयन समिति पर सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में भारत के पूर्व ओपनर कृष्णमचारी श्रीकांत ने गौतम गंभीर को बुरी तरह लताड़ा है।

श्रीकांत ने यहां तक यह भी कहा कि रोहित शर्मा की जगह पर नहीं बल्कि गौतम गंभीर की जगह पर सवाल उठने चाहिए। भारत ने गंभीर के कार्यकाल में चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप 2026 जरूर जीता है लेकिन इस दौरान घर पर साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार, न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हार, न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर टेस्ट सीरीज हार, आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार और अब इंग्लैंड में टी20 और वनडे सीरीज में बुरी तरह हार, देखने के मिली हैं।

- **श्रीकांत ने हेड कोच गंभीर पर किया हमला-** कृष्णमचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो में टीम इंडिया के मैनेजमेंट को बुरी तरह लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा, 'यह भारतीय टीम के सबसे खराब समय में से एक है। मैनेजमेंट और उसकी चयन प्रक्रियाओं में लगातार की जा रही गलतियां हैरान कर रही हैं। गौतम गंभीर को हर मैच में नए खिलाड़ी चाहिए हैं। आप कैसे इस मैनेजमेंट के कार्यकाल में टिक पाएंगे। आप जबरन रोहित शर्मा को बाहर करना चाहते हैं, आपको कौन बाहर करेगा?

रोहित शर्मा ने 'लॉर्ड' के बल्ले से लॉर्ड्स में लगाया शतक, बचपन के दोस्त ने खुद किया खुलासा

भारत के पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी ने यह भी कहा, 'हम घर पर टेस्ट मैच हारे, टी20 में हमारी बेइज्जती हुई और ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड में जाकर हम वनडे भी हारे। उनकी (गौतम गंभीर की) टीम के अंदर पोजिशन पर सवाल उठने चाहिए, रोहित शर्मा की नहीं। मैंने कभी इस तरह का टीम सेलेक्शन और मैनेजमेंट का हाल अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक दो अच्छे परफॉर्मेंस के अलावा इंग्लैंड में हम बुरी तरह फेल हुए।' उन्होंने इसके अलावा केएल राहुल को नीचे बल्लेबाजी के लिए उतारने पर भी सवाल उठाए हैं। श्रीकांत का मानना है कि इशान किशन और श्रेयस अय्यर को नीचे आना चाहिए। केएल राहुल नंबर 4 के बल्लेबाज हैं। वह आते ही हिट नहीं कर सकते हैं बल्कि वह पारी को संभालने और स्थिरता देने में सक्षम हैं। अब देखना होगा कि इतनी आलोचनाओं के बाद मौजूदा भारतीय टीम मैनेजमेंट की आंखे कब खुलती हैं? लगातार टीम के अंदर चयन और प्लेइंग कॉम्बिनेशन पर सवाल उठ रहे हैं।

हारने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों पर बैन होने का खतरा

FIFA कर रहा खिलाड़ियों से लड़ाई की जांच

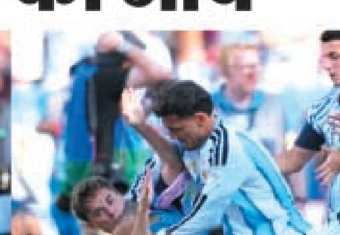

नई दिल्ली। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद स्पेन के खिलाड़ियों से अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने लड़ाई कर ली थी। इसके कारण लियोनल मेसी की अगुआई वाली टीम के खिलाड़ियों पर प्रतिबंधित होने का खतरा मंडरा रहा है। फीफा ने न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में रविवार (20 मई) को फाइनल के बाद हुई लड़ाई की जांच शुरू कर दी है।

स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता, लेकिन आखिरी सीटी बजने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हुई लड़ाई ने जश्न को फीका कर दिया। स्पेन के जश्न के दौरान उनके खिलाड़ियों से अर्जेंटीना के कई खिलाड़ी भिड़ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को क्या मिल सकती है सजा

फीफा के अनुशासन संहिता के अनुच्छेद 14 के तहत, हिंसक व्यवहार के दोषी पाए जाने वाले खिलाड़ियों को कम से कम तीन मैचों का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है। हमला, कोहनी मारना, मुक्का मारना, लात मारना, काटना, थूकना, विरोधी टीम या मैच ऑफिशियल के अलावा किसी और को मारने पर भी तीन मैचों का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

और क्या सजा मिल सकती है- कोई भी प्रतिबंध तब लागू होगा जब अर्जेंटीना अगली बार आधिकारिक मैच खेलेगा। खिलाड़ियों के प्रतिबंध के अलावा अगर फीफा यह नतीजा निकालता है कि राष्ट्रीय टीम ने गलत व्यवहार किया है तो अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) पर भी अनुशासनिक कार्रवाई हो सकता है।

'इस जख्म को भरने में समय लगेगा'

विश्व कप हारने के बाद लियोनल मेसी का भावुक पोस्ट

नई दिल्ली। अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट करते हुए कहा कि स्पेन से वर्ल्ड कप फाइनल हारने का जख्म भरने में समय लगेगा। उन्होंने अपने साथियों और पूरे टूर्नामेंट में टीम को सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने स्पेन को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई भी दी। गौरतलब है कि स्पेन ने 20 जुलाई को एक्स्ट्रा टाइम में एक गोल करके अर्जेंटीना का खिताब रक्षा करने का सपना तोड़ दिया।

मेसी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'दुख बहुत ज्यादा है। इस जख्म को भरने में समय लगेगा, लेकिन मैंने अच्छी यादों को संजोकर रखने का फैसला किया है, उन सभी मैचों को जिन्हें हमने सबकुछ झोंककर पलट दिया। ऐसे पल हमेशा याद रहेंगे। मैं हमेशा पूरे देश के सपोर्ट को याद रखूंगा, जिसने इस ग्रुप के काम और कोशिशों के साथ मिलकर हमें एक बार फिर दुनिया की सबसे अच्छी टीमों में वापस ला दिया।'

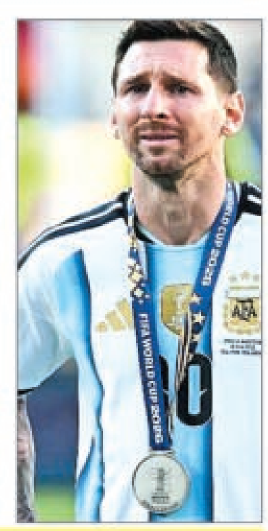

स्पेन को विश्वकप जीतने पर बधाई

मेसी ने लिखा, 'आज, हमने जो हासिल किया, उसकी तारीफ करना मुश्किल है... लेकिन यह ग्रुप सच में लगातार दो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है। हर बधाई और हर मैसेज के लिए दिल से शुक्रिया। एक बार फिर, हम एक देश के तौर पर एक साथ आए और अर्जेंटीना होने का बहुत गर्व महसूस करते हुए एक साथ खड़े रहे। मैं स्पेन को भी वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देना चाहता हूं।'

हार के बाद क्या बोले थे मेसी- मेसी ने रविवार को मेटलाइफ स्टेडियम में स्पेन के खिलाफ दिल तोड़ने वाली हार बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रनर-अप सिल्वर मेडल लिया। अर्जेंटीना के इस स्टार खिलाड़ी ने अलविदा कहते हुए आंसू बहाए और फिर प्लेयर्स टनल से नीचे चले गए।

साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में छाया असम

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 19 जुलाई को संपन्न हुई 10वीं कैडेट, जूनियर, अंडर-21 और सीनियर साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2026 तथा दूसरी अंडर-14 साउथ एशियन कप कराटे चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए असम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। असम के एथलीटों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 14 पदक अपने नाम किये। इस शीर्ष प्रतियोगिता में असम के कुल 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनमें से 4 खिलाड़ियों ने 10वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में और 7 खिलाड़ियों ने दूसरी अंडर-14 साउथ एशियन कप कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। पदक विजेताओं में अर्णव बोरा ने कैडेट बालक कुमिते -70 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मधुस्मिता दैमारी ने जूनियर बालिका कुमिते -66 किग्रा में रजत पदक हासिल किया, जबकि हेमफू बंगजांग ने सीनियर पुरुष कुमिते -60 किग्रा वर्ग में रजत और अंडर-21 बालक कुमिते -60 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। हानी अली ने सीनियर महिला टीम काटा में रजत पदक और सीनियर महिला कुमिते -61 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं दूसरी अंडर-14 साउथ एशियन कप कराटे चैंपियनशिप 2026 में रायना सिन्हा ने अंडर-10 बालिका काटा में स्वर्ण पदक और अंडर-10 बालिका कुमिते -30 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। आह्ती भराली ने अंडर-10 बालिका कुमिते -30 किग्रा में स्वर्ण पदक और अंडर-10 बालिका काटा में कांस्य पदक हासिल किया। दीक्षा डेका ने अंडर-12 बालिका कुमिते +40 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता, काबान बंगजोंग ने अंडर-14 बालिका कुमिते -40 किग्रा वर्ग में एक रजत तथा अंडर-14 बालिका टीम काटा में एक कांस्य पदक प्राप्त किया। धरित्री बोरा ने अंडर-14 बालिका काटा, अंडर-14 बालिका कुमिते -40 किग्रा और अंडर-14 बालिका टीम काटा प्रतियोगिताओं में कुल तीन कांस्य पदक अर्जित किये। उल्लेखनीय है कि 10वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ दल बनने का गौरव हासिल किया, जबकि नेपाल की टीम शीर्ष स्थान पर रही।

कोकराझाड़ को हराकर कामरूप महानगर बना चैंपियन

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। मोरिगांव के दंदोवा खेल मैदान में आयोजित पिलिक चौधरी स्मृति राज्य स्तरीय अंतर-जिला स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 का खिताब कामरूप महानगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपने नाम कर लिया है। बेहद रोमांचक और कड़े मुकाबले वाले फाइनल मैच में कामरूप महानगर ने कोकराझाड़ के पाटगांव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को टाईब्रेकर के जरिये कुल 6-5 (पेनाल्टी में 4-3) के अंतर से हराकर चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, जिसके बाद परिणाम के लिए रेफरी ने टाईब्रेकर का सहारा लिया। असम सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मोरिगांव जिला खेल अधिकारी कार्यालय की मेजबानी में आयोजित इस अंडर-15 बालक वर्ग के फाइनल मैच में कामरूप महानगर के कल्याण राजखोवा ने खेल के 32वें मिनट में पहला गोल दागा। हालांकि, तुरंत पलटवार करते हुए कोकराझार के आकाश नार्जारी ने 32वें मिनट में ही गोल कर मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। हाफ टाइम के बाद, दूसरे हाफ के 43वें मिनट में प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गये निर्भय फुकन ने गोल कर कामरूप महानगर को 2-1 की बढ़त दिलायी, लेकिन कोकराझाड़ के आंसुला नार्जारी ने 49वें मिनट में शानदार गोल कर मैच को फिर 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा किया। इसके बाद टाईब्रेकर चरण में कामरूप महानगर की ओर से निर्भय, सनातन राहांग, सम्राट गोगोई और अब्दुल अली ने गोल दागे, जबकि कोकराझाड़ की ओर से केवल एस ब्रह्म, मेहेर बसुमतारी और आंसुला ही गोल कर सके। राज्य चैंपियन बनने के साथ ही कामरूप महानगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने आगामी सितंबर में भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित सुब्रतो कप अंडर-15 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में असम का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी हासिल कर लिया है। इससे पहले सुबह खेले गये सेमीफाइनल मुकाबलों में पाटगांव स्कूल ने धेमाजी के पीएम श्री गोगामुख को 2-1 से और कामरूप महानगर ने कार्बी आंग्लांग के न्यू होप हाई स्कूल को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। विजेता टीम में गोलकीपर दीपज्योति पोद्दार, अब्दुल अली, निर्भय, सनातन, भार्गव लाहन, अजय कैवर्त, सम्राट, भाषिक शरणीया, सौरव सोनोवाल, चार्ल्स मिंज, धनबीर कुमार ब्रह्म, कल्याण राजखोवा, अंगद गोगोई, जितेन रामसियारी, कौशिक बसुमतारी और हियुवेनचुन स्वर्गीयारी शामिल थे। टीम के कोच कार्तिक बोड़ो और मैनेजर आंसाई ब्रह्म थे, जबकि मैच का संचालन मुख्य रेफरी दुलाल अहमद ने रंजीत गोगोई, चिन्मय सोनोवाल और गीताली मोरन के सहयोग से किया।

ऋतुराज कप्तान, पृथ्वी शॉ, सरफराज खान और मुशीर भी शामिल

रेड बॉल टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन टीम का ऐलान

नई दिल्ली। भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालने वाले ऋतुराज को अब रेड बॉल क्रिकेट में भी लीडरशिप रोल मिल चुका है। आगामी दलीप ट्रॉफी के लिए उन्हें वेस्ट जोन की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। मुंबई के चीफ सेलेक्टर राजेश पवार की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक के बाद सोमवार 20 जुलाई को टीम का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि पिछले सीजन शार्दुल ठाकुर इस टीम के कप्तान थे। अब यह जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है। हाल ही में इंडिया ए के श्रीलंका दौरे पर भी वह टीम के उपकप्तान थे। उन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों सीरीज में इंडिया ए की उपकप्तानी की थी। अब दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन के लिए वह बतौर कप्तान नजर आएंगे। इस रेड बॉल टूर्नामेंट का आयोजन 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा।

टूर्नामेंट में कुल 5 मुकाबले होंगे

वेस्ट जोन की टीम सीधे क्वार्टरफाइनल 2 में नॉर्थ जोन की टीम से भिड़ेगी। यह मुकाबला 23 से 26 अगस्त 2026 तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 5 मुकाबले होंगे जिसमें 6 से 10 सितंबर तक सीओई के ग्राउंड 1 में खेला जाने वाला फाइनल मैच भी शामिल है। इस टीम में ऋतुराज के अलावा कई चर्चित भारतीय नाम हैं। पृथ्वी शॉ और सरफराज खान भी इस टीम में शामिल हैं। जबकि मुशीर खान को भी स्क्वाड में जगह मिली है। पूर्व कप्तान शार्दुल ठाकुर भी इस टीम का हिस्सा हैं।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में तेजी का रुख

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्लोबल मार्केट से आज मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए थे। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। वहीं एशियाई बाजार में आज आमतौर पर तेजी का रुख बना हुआ है।

अमेरिका स्टॉक मार्केट पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुआ। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 307.16 अंक यानी 0.59 प्रतिशत टूट कर 51,839.26 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.19 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,443.28 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 0.05 प्रतिशत फिसल कर 25,508.07 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 116.42 अंक 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,955.68 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 75.61 अंक यानी 0.72 प्रतिशत लुढ़क कर 10,524.76 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

लोगो और फेसिया का अनावरण

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। पूर्वोत्तर के बुनकरों और कारीगरों की आजीविका को बढ़ावा देने और उनकी कला को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ओतिज्जो ग्रामीण विरासत एम्पोरियम (ओजीएचई) ने आज महानगर के आमबाड़ी में अपने आधिकारिक लोगो और फेसिया का अनावरण किया। यह पहल नाबार्ड के सहयोग से एवीए क्रिएशन सोशल इम्पैक्ट फाउंडेशन द्वारा शुरू की गयी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शिल्पकारों को निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक जी रमेश कुमार, हथकरघा एवं वस्त्र निदेशिका मयूरी ओझा और सांस्कृतिक मामलों के निदेशक बाहुल चंद्र दास उपस्थित रहे। जी रमेश कुमार ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म से अब तक 700 कारीगर जुड़ चुके हैं और जल्द ही इसे 2,000 कारीगरों तक बढ़ाने का लक्ष्य है, ताकि बिक्री का मुख्य हिस्सा सीधे उनके पास पहुंचे। वहीं, फाउंडेशन की प्रबंध निदेशिका अनु मंडल ने असमिया लिपि और स्थानीय डिजाइनों से प्रेरित लोगो का अनावरण करते हुए इसे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का प्रतीक बताया। यह एम्पोरियम ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को सीधे बाजार से जोड़कर असली हथकरघा, हस्तशिल्प और जी आई टैग प्राप्त उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद ज्ञापन में प्रणव कुमार शर्मा ने कहा कि यह कदम ग्रामीण आजीविका के एक नये युग की शुरुआत है, जिससे पूर्वोत्तर की विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

देश के 570 जिले बनेंगे निर्यात हब

यूपी के 12 जिलों से होगी शुरुआत, भारतीय उत्पादों की बढ़ेगी वैश्विक पहुंच

नई दिल्ली, एजेंसी। वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने और नए मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने के लिए केंद्र 2030 तक 570 जिलों को नए निर्यात हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी कर रहा है। उभरते निर्यातकों को ई-कॉमर्स निर्यात मंचों से जोड़ने का काम होगा, जिससे वैश्विक बाजार तक उनकी पहुंच और बिक्री बढ़ सके।

जिला स्तरीय निर्यात केंद्र के जरिये स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की रणनीति पर तेजी से काम हो रहा है। ओडीओपी उत्पादों पर खास जोर है। हर जिले के अनूठे और पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का काम होगा। कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, जीआई टैग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई उद्योग पर जोर होगा। निर्यातकों को गुणवत्ता सुधार, अंतरराष्ट्रीय पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स सुविधा,

टेस्टिंग लैब, ग्लोबल मार्केटिंग आदि का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यूपी में मेरठ और गोरखपुर समेत 12 जिले चिह्नित- प्रथम चरण में यूपी में 12 जिले निर्यात हब के तौर पर विकसित होंगे। इनमें भदोही, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर, वाराणसी, शामिल हैं। निर्यात केंद्र बनाने की पहल अन्य राज्यों में भी शुरू की गई है। हर जिले से निर्यातकों की संख्या बढ़ाने का काम शुरू हो गया है।

मिशन मोड पर काम

अब जिला निर्यात हब ढांचे के अंतर्गत पहले से निर्मित मजबूत संस्थागत आधार को नई चुनौतियों के मद्देनजर वास्तविक और दिखाई देने वाले निर्यात परिणामों में परिवर्तित करने का काम होगा। इस अभियान से नए निर्यातकों को मौका मिलेगा। ?एमएसएमई की भागीदारी मजबूत होगी। ?स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और जिलों की निर्यात क्षमता बढ़ेगी।

ओडीओपी योजना बन रही आधार

यूपी की ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) योजना को केंद्र की जिला-आधारित निर्यात रणनीति के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इसके तहत पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगरी के अलावा नए उभरते क्षेत्र भी चिह्नित किए जा रहे हैं, ताकि उद्यमी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ सकेंगे। हाल में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में व्यापार परिषद की बैठक में इस पर रणनीति बनाई गई।

संकट में हॉलीवुड का सबसे बड़ा विलय

81 अरब डॉलर की डील

न्यूयॉर्क, एजेंसी। हॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी कारोबारी डील पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के बीच प्रस्तावित 81 अरब डॉलर के मेगा मर्जर पर अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने दोनों कंपनियों को कम से कम दो सप्ताह तक इस सौदे को आगे नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। यह फैसला अमेरिका के उन 12 राज्यों के पक्ष में आया है, जिन्होंने इस डील को अदालत में चुनौती दी है। राज्यों का कहना है कि अगर दोनों मीडिया दिग्गज एक हो गए तो हॉलीवुड में प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी और इसका सीधा असर दर्शकों की पसंद व जेब पर पड़ेगा।

क्यों लगी रोक?

फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज अरासेली मार्टिनेज-ओल्गुइन ने राज्यों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अस्थायी रोक लगाई। अदालत का कहना है कि राज्यों को अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इसी वजह से फिलहाल मर्जर प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।

12 राज्यों ने क्यों किया विरोध?

कैलिफोर्निया की अगुवाई में 12 राज्यों ने पिछले सप्ताह कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उनका तर्क है कि इस विलय के बाद मनोरंजन उद्योग में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी और कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा बढ़ जाएगा।

राज्यों का यह भी दावा है कि इससे:-

दर्शकों के पास कंटेंट के विकल्प कम हो सकते हैं।
केबल टीवी और मनोरंजन सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।
फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ सकती है।
कंपनियों ने नहीं मानी थी राज्यों की मांग

राज्यों ने पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी से अनुरोध किया था कि अदालत का फैसला आने तक डील को अंतिम रूप न दिया जाए। लेकिन दोनों कंपनियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्यों ने कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड ने निवेशकों को दिया झटका

फ्लैट लिस्टिंग के बाद लगा लोअर सर्किट

नई दिल्ली, एजेंसी। फैब्रिक की डाइंग और प्रोसेसिंग के काम में लगी अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट ने फ्लैट एंट्री कर अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 105 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग बिना किसी उतार चढ़ाव के 105 रुपये के स्तर पर ही हुई। लिस्टिंग के बाद हुई बिकवाली के कारण कंपनी के शेयर कुछ देर में ही गिर कर 99.75 रुपये के लोअर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 5.25 रुपये यानी पांच प्रतिशत का नुकसान हो गया।

कंपनी का 126.25 करोड़ रुपये का आईपीओ 14 से 16 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.40 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 1.09 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में भी 1.09 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.54 गुना सब्सक्राइब हो सका था।

इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 1,20,24,000 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ में नए शेयरों की बिक्री के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नयी वीविंग यूनिट लगाने, पुराने कर्ज के बोझ को हल्का करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी को 8.63 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ कर 21.72 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इस दौरान कंपनी की कुल आय में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2024-25 में इसे 237.66 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ कर 350.18 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में कंपनी पर 166.09 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो अगले वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ कर 177.60 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

इंडिगो के विस्तार को नई उड़ान

510 एयरबस विमानों के लिए खरीदेगी 1,000 से ज्यादा इंजन

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने सोमवार को घोषणा की कि वह अपने 510 एयरबस ए320 नियो फैमिली विमानों के लिए सीएफएम इंटरनेशनल से 1,000 से अधिक इंजन खरीदेगी। इंडिगो और सीएफएम इंटरनेशनल ने ब्रिटेन में आयोजित फार्नबरो इंटरनेशनल एयरशो के दौरान इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सीएफएम इंटरनेशनल, जीई एयरोस्पेस और सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी ने बताया कि 510 एयरबस ए320 नियो फैमिली विमानों के लिए 1,000 से अधिक लीप-1ए इंजन का यह ऑर्डर सीएफएम इंटरनेशनल के इतिहास में लीप इंजनों का अब तक का सबसे बड़ा एकल ऑर्डर होगा।

हालांकि, इस सौदे की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ए320 नियो फैमिली में ए320 नियो, ए321 नियो और ए321 एक्सएलआर विमान शामिल हैं। ये सभी नैरो-बॉडी विमान हैं।

समझौते में और क्या-क्या शामिल- समझौते के तहत सीएफएम इंटरनेशनल बंगलूरू में इंडिगो की इंजन एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) सुविधा स्थापित करने में भी व्यापक सहयोग देगा। इसके अलावा कंपनी स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति सहित दीर्घकालिक सामग्री सेवा समझौते के माध्यम से इंडिगो के विमान बेड़े को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में इंडिगो के पास 400 से अधिक विमान परिचालन में हैं और एयरबस के 900 से अधिक विमानों का ऑर्डर पहले से लंबित है।

सीएफएम के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार

वर्ष 2016 में एयरलाइन सीएफएम56-5बी इंजन से लैस एयरबस ए320 सीईओ फैमिली विमानों का संचालन कर रही थी। इसके बाद 2019 में उसने अपने नए एयरबस ए320/321 नियो फैमिली विमानों के लिए लीप-1ए इंजन का ऑर्डर दिया था। सीएफएम इंटरनेशनल के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। वर्तमान में भारत की पांच एयरलाइंस 400 से अधिक लीप इंजन वाले विमानों का संचालन कर रही हैं और 2,000 इंजनों का ऑर्डर पहले से दिया जा चुका है। जीई एयरोस्पेस के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच. लॉरेंस कल्प जूनियर ने कहा कि पुणे में विनिर्माण सुविधा, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क और बेंगलूरू में उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ कंपनी इंडिगो के विस्तार और भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समझौते पर किसने क्या कहा?

सैफ्रॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवियर एंड्रीस ने कहा, 'भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है और हमारे लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। लीप इंजन उत्पादन और एमआरओ क्षमता में लगातार निवेश के जरिए हम इंडिगो की तेज वृद्धि और भारतीय एयरोस्पेस उद्योग के विकास के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहे हैं। '

इस बीच, प्रैट एंड व्हिटनी (पीएंडडब्ल्यू) इंजनों से जुड़ी समस्याओं के कारण कई विमान अब भी ग्राउंडेड हैं। सोमवार को ही हनीवेल एयरोस्पेस ने भी घोषणा की कि इंडिगो ने आने वाले वर्षों में मिलने वाले 810 नए एयरबस ए320 नियो फैमिली विमानों के लिए उसके एवियोनिक्स और पावर सिस्टम का चयन किया है।

स्टॉक मार्केट में एसबीआई फंड्स की मजबूत शुरुआत

फायदे में आईपीओ निवेशक

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूती के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 574 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 6.27 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 610 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग 6.85 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 613.30 रुपये के स्तर पर हुई।

लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से ये शेयर 624.90 रुपये तक चढ़ गया, वहीं बिकवाली का दबाव बनने पर ये टूट कर 610 रुपये के स्तर तक भी आया। सुबह 10:30 बजे तक का कारोबार होने के बाद एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर 617.80 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 43.80 रुपये यानी 7.63 प्रतिशत का फायदा हो गया है।

इस कंपनी का 9,812.91 करोड़ रुपये का आईपीओ 14 से 16 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 41.73 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 140.11 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 22.51 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 3.76 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसके अलावा एंप्लॉयीज के लिए रिजर्व पोर्शन में 4.65 गुना और शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व पोर्शन में 9.52 गुना सब्सक्रिप्शन आया था।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला मेटालिक टेक्नोफोर्ज का आईपीओ, 28 जुलाई को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली, एजेंसी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी मेटालिक टेक्नोफोर्ज का 49.96 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 23 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 24 जुलाई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 27 जुलाई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 28 जुलाई को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर 11:30 बजे तक ये आईपीओ 16 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 72 रुपये से लेकर 77 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,600 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 3,200 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा।

मिलवर्क्स टेक के शेयरों ने निवेशकों को किया मालामाल

नई दिल्ली, एजेंसी। एयरोस्पेस, डिफेंस, रेलवे और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए हाई-एक्यूरेसी वाले मशीनी पार्ट्स और सब असेंबली बनाने वाली प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट ने जबरदस्त मजबूती के साथ एंट्री कर अपने आईपीओ निवेशकों के पैसे को लगभग दोगुना कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 331 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे।

आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 90 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 628.90 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद हुई लिवाली के कारण कंपनी के शेयर थोड़ी देर में ही उछल कर 660.30 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 329.30 रुपये यानी 99.49 प्रतिशत का फायदा हो गया।

मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज का 160.34 करोड़ रुपये का आईपीओ 14 से 16 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से बंपर रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 219.54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 194.05 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 260.37 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 216.60 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

अदाकारी की बेमिसाल मल्लिका पूरबी शर्मा

यादों में अमर रहेंगी सबकी चहेती बेबी

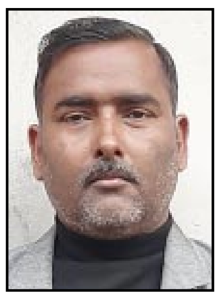

अजहर आलम

असमिया कला और रंगमंच जगत के इतिहास को अपनी अनूठी आभा से रोशन करने वाली मशहूर अभिनेत्री पूरबी शर्मा, जिन्हें प्यार से *बेबी* कहा जाता था, अब हमारे बीच नहीं रहीं। 14 जुलाई 2026 को गुवाहाटी में 65 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका आकस्मिक निधन हो गया।

अपनी सहज मुस्कान, जीवंत अभिनय और बेमिसाल अदाकारी से दशकों

तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली इस जादुई अदाकारा का इस तरह अचानक चले जाना न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि समूचे असमिया सांस्कृतिक जगत के लिए एक ऐसा शून्य छोड़ गया है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा।

कला के प्रति उनका समर्पण और मंच पर उनकी उपस्थिति हमेशा दर्शकों की स्मृतियों में जीवित रहेगी। वर्ष 1961 में पाठशाला में जन्मीं पूरबी शर्मा बहुमुखी प्रतिभा की धनी थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मंगलदै प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की थी। वह विज्ञान विषय की छात्रा थीं और बचपन में एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती थीं, लेकिन अभिनय, संगीत और नृत्य के प्रति उनका गहरा लगाव था। वह खुद हारमोनियम बजाकर बरगीत और लोकगीत गाया करती थीं और उनके माता-पिता भी हमेशा इस बात के लिए उत्साहित रहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में अभिनय करे।

उनके फिल्मी सफर की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। 22 फरवरी 1980 को उनकी पहली फिल्म *आजली नबौ* रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने *बेबी* नाम से अभिनय किया। इस फिल्म में असम की सुप्रसिद्ध गायिका रुनजुन फुकन द्वारा गाए गए लोकप्रिय गीत *सकु मेली नासाबा* पर पूरबी ने अपनी खूबसूरत अदाओं और बेहतरीन लिप-सिंक से दर्शकों का दिल जीत लिया और रातोंरात एक बड़ी स्टार बन गईं।

इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और *सोनमइना, पूजा, मधुचंदा, संकल्प, एंथनी मोर नाम, प्रथम रागिनी, पिता पुत्र, सिराज, भाई भाई, शेवाली, अभिमान, पहाड़ी कन्या, वंशधर, प्रभाती पखीर गान* और *अशांत प्रहर* जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। साल 1987 में आई फिल्म *प्रथम रागिनी* में उनके द्वारा निभाया गया *मिनी एंड्रयूज़ बरबोरा* का किरदार आज भी मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने साल 1997 में *संस्कार* फिल्म में भी काम किया था, जो सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो सकी।

अपनी एकमात्र बेटी की परवरिश के कारण पूरबी ने कुछ समय के लिए बड़े पर्दे से दूरी बना ली थी, लेकिन इस लंबे अंतराल को प्रसिद्ध निर्देशक तौफीक रहमान ने खत्म किया। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म *एई मरम तोमार बाबे* में पूरबी को एक बेहद खास किरदार के लिए चुना।

साल 2001 में आई इस फिल्म से पूरबी की रुपहले पर्दे पर शानदार वापसी हुई और यह दौर भी उनके करियर का एक बेहद सफल पड़ाव साबित हुआ, जिसमें उन्होंने *नायक, कन्यादान, विधाता, हृदय कपोवा गान, बारूद, कदम तले कृष्ण नाचे, अहिर भैरव* और *रक्तबीज* जैसी फिल्मों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।

सिनेमा के साथ-साथ पूरबी ने दूरदर्शन, वीडियो फिल्मों और हिंदी सिनेमा में भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी। दूरदर्शन के लिए निर्मित और चारुकमल हजारिका द्वारा निर्देशित चर्चित हिंदी धारावाहिक *मृत्युंजय* में उन्होंने *गोंसानी* का यादगार किरदार निभाया था।

वर्ष 1979 के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखक बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के उपन्यास पर आधारित इस धारावाहिक में उन्हें रामायण के प्रसिद्ध राम यानी अभिनेता अरुण गोविल के साथ स्क्रीन साझा करने का अवसर मिला। इसके अलावा उन्होंने चारुकमल हजारिका के ही एक और पांच कड़ियों वाले हिंदी धारावाहिक *ग्रहणंत* और लोकप्रिय वीडियो फिल्मों *लखीमी* तथा *रिंगा रिंगा मन* में काम कर घर-घर में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई।

हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने अपनी अदाकारी की अमिट छाप छोड़ी, जिसमें साल 1988 में सेंसर सर्टिफिकेट पाने वाली फिल्म दूर *नहीं सवेरा* उनके करियर की एक बेहद खास कड़ी थी। फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित और चारुकमल हजारिका द्वारा निर्देशित इस दो घंटे की फिल्म में उनके साथ प्रांजल सैकिया, तपन दास और मिंटू बरुआ जैसे असम के कई दिग्गज कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं।

चूंकि यह फिल्म पूरी तरह हिंदी में थी और असम के कलाकारों का हिंदी उच्चारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए तपन दास को छोड़कर पूरबी सहित बाकी सभी कलाकारों की आवाज को पेशेवर डबिंग आर्टिस्ट्स से डब कराया गया था। फिल्म *प्रभाग* की आधिकारिक फिल्म होने के कारण देश के सुदूर गांवों और कस्बों में ले जाकर इसकी विशेष स्क्रीनिंग की गई थी।

पूरबी के करियर का एक बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण अध्याय असम के प्रसिद्ध भ्राम्यमाण थिएटर से भी जुड़ा रहा। नब्बे के दशक में पूरबी शर्मा ने पहले कवि बीरिंची कुमार भट्टाचार्य से शादी की थी। वह उस समय एक बेहद आकर्षक युवा अभिनेत्री थीं, लेकिन दो अलग-अलग दुनिया के दो बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व होने के कारण यह शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी। बाद में उन्होंने विख्यात अभिनेता तपन दास से विवाह कर लिया, जिनसे उनकी एक इकलौती बेटी है। शादी के बाद इस जीवनसाथी जोड़ी ने रंगमंच पर भी सफलता का एक नया इतिहास रचा।

कोहिनूर थिएटर (1993-94) में तपन-पूरबी की जोड़ी का नाटक *अनारकली* मील का पत्थर साबित हुआ और इसी साल *हैमलेट* और *रातिर जुई*

कोहिनूर थिएटर (1993-94) में तपन-पूरबी की जोड़ी का नाटक *अनारकली* मील का पत्थर साबित हुआ और इसी साल *हैमलेट* और *रातिर जुई* जैसे नाटकों में भी दोनों के अभिनय को जमकर सराहा गया। *माजनिशार चींयर* में निभाया गया पूरबी का संवेदनशील किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है।

जैसे नाटकों में भी दोनों के अभिनय को जमकर सराहा गया। इसके बाद हेंगुल थिएटर (1994-95) में अभिनेता जतीन बोरा के साथ नाटक *माजनिशार चींयर* में निभाया गया पूरबी का संवेदनशील किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है।

आगे चलकर श्रीमंत शंकरदेव थिएटर और राजतिलक थिएटर के *लैला मजनू, ताल, काबुलीवाला, शहीद खरगेश्वर, जिलमिल तरार* दरे और *रुद्रसागर* जैसे नाटकों के जरिए भी इस जोड़ी ने दर्शकों पर अपनी जादुई कला का जादू बिखेरा। राजतिलक थिएटर के उस ऐतिहासिक सफर के बाद यह मशहूर जोड़ी फिर कभी भ्राम्यमाण थिएटर के मंच पर साथ नजर नहीं आई। हालांकि तपन दास ने रंगमंच पर अपनी यात्रा जारी रखी और एक लंबे अंतराल के बाद इतिहास थिएटर के साथ वर्ष 2026-27 के नाट्य सत्र के लिए अनुबंध किया।

नियति का खेल देखिए कि इस नए सफर के पूर्वाभ्यास शिविर के शुभारंभ से ठीक एक दिन पहले तपन दास और उनकी बेटी राधा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब पूरबी का आकस्मिक निधन हो गया। इस गहरे आघात के कारण तपन दास थिएटर के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो सकें। अब अपनी बेटी की जिम्मेदारी और कला के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए उन्हें फिर से मंच पर लौटना होगा। इस गहरे व्यक्तिगत दुख से उबरने के लिए उन्होंने प्रबंधन से कुछ दिनों का समय लिया है, जिसके बाद वे दोबारा अभ्यास शिविर में शामिल होंगे।

पूरबी भले ही आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन असमिया कला, सिनेमा, रंगमंच और देश के सांस्कृतिक पटल पर उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा अमर रहेगा, और उनके अभिनय की सादगी तथा मुस्कान दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी।

सेंदूर में काम न कर पाने का रहा मलाल

बीते जमाने की खूबसूरत और दिग्गज अभिनेत्री पूरबी शर्मा के शानदार करियर के बावजूद उनके दिल में एक खास फिल्म में काम न कर पाने का मलाल हमेशा के लिए रह गया। वह फिल्म थी पुलक गोगोई के निर्देशन में बनी सुपरहिट व्यावसायिक फिल्म *सेंदूर* (सिंदूर)।

इस फिल्म के मुख्य किरदार के लिए पहले पूरबी शर्मा को ही अनुबंधित किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ पारिवारिक मजबूरियों और बाधाओं के कारण उन्हें इस फिल्म का ऑफर ठुकराना पड़ा।

सेंदूर के उस मुख्य किरदार को न निभा पाने का दुख उन्हें हमेशा सालता रहा, जिसे बाद में अभिनेत्री विद्या राव ने निभाया था। आज भले ही पूरबी शर्मा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन असमिया सिनेमा में उनका योगदान और उनकी बेहतरीन फिल्में दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।

पूरबी शर्मा को ही अनुबंधित किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ पारिवारिक मजबूरियों और बाधाओं के कारण उन्हें इस फिल्म का ऑफर ठुकराना पड़ा। *सेंदूर* के उस मुख्य किरदार को न निभा पाने का दुख उन्हें हमेशा सालता रहा, जिसे बाद में अभिनेत्री विद्या राव ने निभाया था।

हैरान करने वाली बात यह रही कि इतने विवादित दृश्य के बावजूद सेंसर बोर्ड ने उदारता दिखाते हुए इस फिल्म को यू प्रमाण-पत्र दिया था। यह फिल्म न केवल असमिया सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई।

एक टेक में फिल्माया गया था असमिया सिनेमा का पहला लिप किस दृश्य

सिनेमा में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चुंबन का सहारा हमेशा से लिया जाता रहा है, लेकिन असमिया सिनेमा में पहली बार एक साहसिक और ऐतिहासिक बदलाव 12 जनवरी 1990 को देखने को मिला।

निर्देशक मृदुल गुप्ता की फिल्म *अभिमान* में असमिया सिनेमा के इतिहास का पहला ऑनस्क्रीन लिप किस दृश्य फिल्माया गया था। उस दौर के रूढ़िवादी माहौल में मुख्य कलाकार तपन दास और पूरबी शर्मा के बीच फिल्माए गए इस अंतरंग दृश्य ने फिल्म जगत और दर्शकों के बीच एक तीखी बहस और भारी हंगामा खड़ा कर दिया था।

इस चर्चित दृश्य के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। फिल्म की पटकथा के अनुसार दोनों कलाकार इस दृश्य के लिए पहले से पूरी तरह सहमत थे। शिलांग के एक खूबसूरत झरने के पास हुई इस शूटिंग के समय पूरबी शर्मा ने दृश्य को और जीवंत बनाने के लिए अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कने की गुजारिश की थी, जिसके बाद दोनों ने बिना किसी रीटेक के महज एक ही टेक में इस पूरे रोमांटिक सीन को बेहद सहजता से पूरा कर लिया।

हैरान करने वाली बात यह रही कि इतने विवादित दृश्य के बावजूद सेंसर बोर्ड ने उदारता दिखाते हुए इस फिल्म को यू प्रमाण पत्र दिया था। यह फिल्म न केवल असमिया सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई, बल्कि इसने दोनों मुख्य कलाकारों की असल जिंदगी को भी एक खूबसूरत मोड़ दे दिया।

शूटिंग के दौरान परवान चढ़ा तपन दास और पूरबी शर्मा का यह रीयल-लाइफ रोमांस आगे चलकर विवाह के पवित्र बंधन में बदल गया। इस तरह *अभिमान* फिल्म असमिया सिनेमा में साहसिक बदलाव की शुरुआत करने के साथ-साथ दो कला प्रेमियों के एक होने की खूबसूरत गवाह भी बन गई।

नमस्कार अपर असम

प्रातः खबर

बुधवार, 22 जुलाई 2026

मौसम

स्थान	अधिकतम	न्यूनतम
जोरहाट	30°	19°
डिब्रूगढ़	29°	17°
तिनसुकिया	30°	18°
शिवसागर	30°	19°

लखीमपुर में जनगणना 2027 की तैयारी तेज़

लखीमपुर, 21 जुलाई (ख.सं)। लखीमपुर जिला प्रशासन ने जनगणना 2027 की तैयारियां तेज़ कर दी हैं।, जिले के सात राजस्व चक्रों और चार शहरी क्षेत्रों के गणनाकर्मियों तथा पर्यवेक्षकों के लिए 21 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।, जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी चयनित गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जनगणना 2027 को सटीक, पारदर्शी और सफल ढंग से संपन्न कराना है।

Ph. : 2548109, 2730431
L. GOPAL JEWELLERS
9-11-14, Kuber A.C. Market
Guwahati - 781001
शुद्ध चांदी के बर्तनों एवं शुद्ध चांदी की सिल्ली व चांदी के सिक्कों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान
22/22 KDM Gold Jewellery, Hallmark Gold Jewellery Branded Diamond Jewellery, Platinum & Silver Utensils & Articles

0361-2601385
9678211156
D. M. Jeweller's
(As You Like We are)
7/8 (L) Akram's Business
Fancy Bazar, Guwahati-1
शुद्ध सील चांदी के बर्तन एवं असली सिक्कों का प्रतिष्ठित स्थान
We also deal in 22/22 KDM hallmark Jewelleries

शिवसागर के नाजिरा में अभूतपूर्व फ्लैश फ्लड ऑयलफील्ड में फंसे कर्मचारी, राहत-बचाव जारी

खबर संवाददाता

शिवसागर 21 जुलाई। लगातार कई दिनों से शिवसागर जिला हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण असम के शिवसागर जिले के नाजिरा क्षेत्र में 19 जुलाई से आई भीषण फ्लैश फ्लड ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। क्षेत्र के अनेक हिस्सों में अचानक जलस्तर बढ़ने से सड़कें, घर, वाहन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा जलमग्न हो गया है। हाल के वर्षों की सबसे गंभीर बाढ़ में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। इस आपदा से ओएनजीसी के ऑयलफील्ड क्षेत्र में वर्कओवर संचालन में लगे क्रिस ड्रिलिंग प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने से कार्यस्थल तक जाने वाले सभी मार्ग डूब गए, जिससे कर्मचारी वहीं फंस गए।बाढ़ का पानी इमारतों में प्रवेश करने के बाद कई कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए भवनों की छतों पर शरण लेनी पड़ी। बाढ़ शुरू होने के बाद से वे बेहद कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए थे। उनके पास भोजन, स्वच्छ पेयजल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्वच्छता सुविधाएं और चिकित्सा सहायता जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लगातार हो रही भारी बारिश, बसों और ट्रकों तक के डूब जाने की स्थिति तथा संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप होने से उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। बाढ़ का असर केवल ऑयलफील्ड तक सीमित नहीं है। क्षेत्र के अनेक घर जलमग्न हो गए हैं, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है तथा परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कई बसें और अन्य वाहन पानी में डूबकर अनुपयोगी हो गए हैं। अनेक गांवों में लोगों को अपने घर छोड़कर छतों, ऊंचे स्थानों और पेड़ों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन और आजीविका पर भी गहरा असर डाला है। दिहाड़ी मजदूर, स्थानीय व्यापारी, परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोग और आम नागरिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं और संचार सुविधाओं तक पहुंच भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। प्रभावित परिवार राहत और मौसम में सुधार की उम्मीद में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। नाजिरा ऑयलफील्ड क्षेत्र की यह स्थिति दूरस्थ औद्योगिक कार्यस्थलों पर चरम मौसम से उत्पन्न चुनौतियों को उजागर करती है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।क्रिस ड्रिलिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि वह ओएनजीसी और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। कंपनी अपने प्रभावित कर्मचारियों की सुरक्षा और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है तथा सामान्य स्थिति बहाल होने तक राहत प्रयास जारी रखे हुए है।।

असम बजट 2026-27 के संबंध में भाजपा के विधायकों ने किया संयुक्त रूप से पत्रकार सम्मेलन संबोधित

खबर संवाददाता

तिनसुकिया, 21 जुलाई। असम बजट 2026-27 को लेकर मंगलवार 21 जुलाई को तिनसुकिया बड़गुरी स्थित भारतीय जनता पार्टी,तिनसुकिया जिला समिति के मुख्य कार्यालय,अटल बिहारी वाजपेयी भवन में भारतीय जनता पार्टी तिनसुकिया जिला समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया।पत्रकार सम्मेलन में तिनसुकिया जिले के भाजपा चार विधायको ने संयुक्त रूप से पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर बजट को जनकल्याणकारी,विकासमुख और सभी वर्गो के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट बताया। पत्रकार सम्मेलन में तिनसुकिया विधायक पुलक गोहाईं, माकुम विधायक संजय

किसान,दूमदूमा विधायक रूपेश ग्वाला,सदिया विधायक बलिन चेतिया सहित जिला अध्यक्ष कुशकान्त बोरा,तिनसुकिया विकाश प्राधिकरण के अध्यक्ष काजल गोहाई,पार्टी के वरिष्ठ सदस्य शिवजी दुबे,भवेन शर्मा सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा विधायकों ने कहा कि असम बजट 2026-27 में किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और समाज के सभी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के समग्र विकास को नई गति देगा और आने वाले वर्षों में असम को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा।विधायकों ने विश्वास जताया कि सरकार की योजनाओं और बजट प्रावधानों का लाभ राज्य के प्रत्येक जिले तक पहुंचेगा,जिससे रोजगार, आधारभूत संरचना,शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी।उन्होंने इसे विकसित असम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अंत में भाजपा विधायकों ने कहा कि यह बजट प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगा और जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरेगा।

रोटरी क्लब आफ तिनसुकिया का एचपीवी टीकाकरण एवं वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

खबर संवाददाता

तिनसुकिया, 21 जुलाई। रोटरी क्लब आफ तिनसुकिया के तत्वावधान में आज बरदोलोई नगर स्थित रोटरी कम्युनिटी सेंटर में एचपीवी टीकाकरण अभियान का सफल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 17 वर्ष तक की कुल 28 लड़कियां लाभांवित हुई! इसमें से 1

लड़की को एचपीवी टीके की पहली खुराक,7 लड़कियों को दूसरी खुराक तथा 20 लड़कियों को तीसरी ख़ुराक प्रदान की गयी। कार्यक्रम में रोटरी क्लब की सदस्य रोटेरियन डॉ नीना दास दे और रोटेरियन डॉ जीएस गोगोई ने एचपीवी का टीका लगाया,और साथ ही गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (सर्वाइकल कैंसर) की रोकथाम में एचपीवी टीकाकरण के महत्व पर एक जागरूकता भाषण दिया। यह जानकारी रोटेरियन अंजनी गोयल ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ तिनसुकिया के काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। यह कार्य प्रतिश्रुति कैंसर एंड पैलिएटिव ट्रस्ट,डिब्रूगढ़ के साथ मिलकर आयोजित किया गया है।

लखीमपुर लायंस क्लब प्रेरणा की नई अध्यक्ष बनीं तजवर सुल्ताना तालुकदार डॉ. नीना दत्ता ने दिलाई शपथ, नई टीम ने संभाला कार्यभार

खबर संवाददाता

लखीमपुर, 21 जुलाई। विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन 'लायंस क्लब इंटरनेशनल' की लखीमपुर शाखा लायंस क्लब लखीमपुर प्रेरणा के सत्र 2026-27 के लिए नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम लखीमपुर बाईपास स्थित 'रेनबो फैमिली रेस्टोरेंट' के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इसमें श्रीमती तजवर सुल्ताना तालुकदार ने क्लब की नई अध्यक्षा के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ पूरी नई टीम ने भी शपथ ग्रहण की। लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322 की नवनियुक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन

डॉ. नीना दत्ता मुख्य अतिथि एवं चीफ इंस्टालेशन ऑफिसर के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर डॉ. मंदिरा शर्मा चालिया को सचिव और श्रीमती उर्मिला दिनोदिया को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। सभा की शुरुआत पारंपरिक 'फूलन गमछा' से अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। डॉ. निशांत राजकाकोती ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ. नीना दत्ता के जीवन परिचय और सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। वहीं निवर्तमान सचिव उर्मिला दिनोदिया ने सत्र 2025-26 की उपलब्धियों और गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ. नीना दत्ता को सम्मान स्वरूप पारंपरिक पीतल की 'जपी' और 'चैलेंग चादर' भेंट की गई। कार्यक्रम में प्रमुख लायंस पदाधिकारी उपस्थित रहे लायन रक्तिम गोगोई रीजन चेयरपर्सन,रीजन दो लायन माणिक लाल दमानी जोन चेयरपर्सन,जोन चार लायन पल्लवी तमोली कोंवार जोन चेयरपर्सन, जोन तीन लायन संजीव चटर्जी सचिव, लायंस क्लब डिब्रूगढ़ श्री राजीव दत्ता अध्यक्ष, लायंस इंटरनेशनल बंदरदेवा ग्रेटर अनिला अग्रवाल, कमला हरलालका, रंजू बाकलीवाल सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रीजन और जोन चेयरपर्सन ने नई टीम को बधाई दी और समाज सेवा में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। अंत में लायन गोपाल चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सामूहिक राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ और सभी सदस्यों ने भोजन किया।

टिगखांग में मतदाता सूची से पांच गांवों के नाम गायब,

सोनोवाल कछारी परिषद चुनाव से पहले ग्रामीणों में रोष

संवाददाता

मोरानहाट, 21 जुलाई। सितंबर में प्रस्तावित सोनोवाल कछारी स्वायत्त परिषद चुनाव से पहले टिंगखांग क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि आवश्यक दस्तावेज होने के बावजूद पांच गांवों के लगभग 60 से 70 परिवारों के नाम मतदाता सूची से पूरी तरह गायब कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, दिरोई आलिकिनार, डिकसम ब्लॉक, नंबर-2 बरबिल (ठेकेरागुड़ी), लोंगबोई और पुवाली बाघमारा गांव के अनेक पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। इससे प्रभावित सोनोवाल कछारी समुदाय के लोगों ने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से प्रशासन से इन पांच गांवों को सोनोवाल कछारी स्वायत्त परिषद के अधिसूचित गांव के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उनका आरोप है कि अधिसूचित गांव का दर्जा नहीं मिलने से आने वाली पीढ़ियां शिक्षा, कृषि तथा अन्य आर्थिक सुविधाओं से भी वंचित रह सकती हैं। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक बिमल बोरा तथा सोनोवाल कछारी स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य टंकेश्वर सोनोवाल से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की मांग की है।

चाय जनजाति-आदिवासी समुदाय के मुद्दों को संसद में उठाने की मांग

असम प्रदेश चाय मजदूर आदिवासी कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

मोरानहाट, 21 जुलाई (सं)। असम प्रदेश चाय मजदूर आदिवासी कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री एतोवा मुंडा ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा जोरहाट लोकसभा सांसद गौरव गोगोई और धुबरी लोकसभा सांसद रकीबुल हुसैन को एक ज्ञापन सौंपकर चाय जनजाति-आदिवासी समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद के वर्तमान सत्र में उठाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि चाय जनजाति-आदिवासी समाज की भावनाओं से जुड़े तीन प्रमुख विषयोंसमुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्रदान करना, चाय श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि तथा भूमि पट्टा एवं भूमि अधिकार सुनिश्चित करनाको कांग्रेस की ओर से संसद में प्रभावी ढंग से उठाया जाना चाहिए। एतोवा मुंडा ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में काजीरंगा के हाथीखुली चाय बागान सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चाय जनजाति-आदिवासी समुदाय के लोग, जो पिछले 30 से 40 वर्षों से भूमि पर कब्जे और उपयोग में थे, उनकी जमीन विभिन्न कारणों का हवाला देकर सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे अनेक परिवार भूमिहीन हो रहे हैं और इस प्रक्रिया में असम सरकार की सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है। ज्ञापन में कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह किया गया है कि संगठन के जनाधार और समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा संसद के माध्यम से इनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाए। ज्ञापन पर असम प्रदेश चाय मजदूर आदिवासी कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री एतोवा मुंडा के हस्ताक्षर हैं।

बाढ़ से डिब्रूगढ़ का रेल संपर्क बुरी तरह प्रभावित

डिब्रूगढ़-तिनसुकिया की कई ट्रेनें डायवर्ट व रद्द

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़ 21 जुलाई। शिवसागर जिले के सिमलुगुड़ी क्षेत्र में दिखौ नदी के उफान से रेलवे ट्रैक, स्टेशन यार्ड, रेलवे कॉलोनी तथा आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा असर डिब्रूगढ़ से चलने वाली और डिब्रूगढ़ आने वाली रेल सेवाओं पर पड़ा है। लगातार भारी वर्षा को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने सिमलुगुड़ीनामति आली तथा सिमलुगुड़ीसेलेंघाट रेलखंड पर ट्रेन परिचालन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। बाढ़ के कारण डिब्रूगढ़ की लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी गंभीर रूप से बाधित हुई है। डिब्रूगढ़नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़चंडीगढ़ एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस और कामरूप एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों को रंगिया रंगापाड़ा मार्ग से डायवर्ट किया गया है। कई सेवाओं को नामति आली, मरियानी, डिमापुर, फरकाटिंग, लमडिंग, गुवाहाटी और रंगिया में आंशिक रूप से समाप्त किया गया है या वहीं से प्रारंभ किया जा रहा है। डिब्रूगढ़ से संबंधित कई स्थानीय और लंबी दूरी की ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। इनमें डिब्रूगढ़ सिमलुगुड़ी पैसेंजर, सिमलुगुड़ीडिब्रूगढ़ पैसेंजर, डिब्रूगढ़राजेंद्र नगर एक्सप्रेस तथा डिब्रूगढ़हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस सहित कई सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा तिनसुकियाजोरहाट टाउन पैसेंजर, तिनसुकिया लमडिंग डीईएमयू, लिडो गुवाहाटी इंटरसिटी और लिडोरंगिया इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया है। फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने प्रभावित स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। भोजन के पैकेट, पेयजल और टिकट वापसी की व्यवस्था की गई है। नामति आली से यात्रियों को एएसटीसी बसों और स्थानीय वाहनों द्वारा शिवसागर टाउन रेलवे स्टेशन पहुंचाया जा रहा है। वहां से डिब्रूगढ़ और न्यू तिनसुकिया के लिए विशेष ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 22503 विवेक एक्सप्रेस के 217 यात्रियों को सेलेंघाट से सड़क मार्ग द्वारा मरियानी भेजा जा रहा है। वहीं 15959 कामरूप एक्सप्रेस के 570 और 15934 अमृतसर तिनसुकिया एक्सप्रेस के 490 यात्रियों को मरियानी में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने बताया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद रेलवे ट्रैक और अन्य ढांचे को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। इंजीनियरिंग टीमों, मशीनरी और मरम्मत सामग्री को तैयार रखा गया है। सुरक्षा जांच पूरी होने और अनुमति मिलने के बाद ही प्रभावित रेलखंडों पर सेवाएं बहाल की जाएंगी। डिब्रूगढ़ से यात्रा करने वाले यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन की नवीनतम स्थिति अवश्य जांचने की सलाह दी गई है।

मार्घेरिटा सह-जिला में राहत कार्य तेज; बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविरों का संचालन जारी

संवाददाता

मार्घेरिटा, 21 जुलाई। मार्घेरिटा सह-जिला प्रशासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत मार्घेरिटा राजस्व सर्किल के सर्किल अधिकारी के कार्यालय के समन्वय से, वर्तमान बाढ़ की स्थिति से प्रभावित परिवारों के लिए युद्धस्तर पर राहत एवं पुनर्वास कार्य जारी रखे हुए है।आज की स्थिति के अनुसार, मार्घेरिटा राजस्व सर्किल के अंतर्गत कुल 14 राहत शिविर एवं राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। ये शिविर मार्घेरिटा टाउन एल.पी. स्कूल, मार्घेरिटा ओल्ड कॉलोनी पीडब्ल्यूडी वेयरहाउस संख्या-1, आलूबाड़ी एल.पी. स्कूल, नं. 1 फकियाल एल.पी. स्कूल, खागोरीपाथर एल.पी. स्कूल, लिखाजन एल.पी. स्कूल, सत जॉयमोटी एल.पी. स्कूल, महाराम बोरो एल.पी. स्कूल, नवज्योति एल.पी. स्कूल, मुल्लांग एल.पी. स्कूल, बाशबाड़ी एल.पी. स्कूल, जागुन एल.पी. स्कूल, नामफाई तापू राहत वितरण केंद्र तथा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एम.ई. स्कूल राहत शिविर में स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में वर्तमान में 1,133 बाढ़ प्रभावित परिवारों के कुल 2,829 लोग आश्रय लिए हुए हैं, जिनमें 2,051 वयस्क और 778 नाबालिग शामिल हैं। सभी शिविरवासियों को चावल, दाल, खाद्य तेल, नमक, अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री, स्वच्छ पेयजल, तिरपाल तथा दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशासन द्वारा प्रत्येक राहत शिविर में पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था, प्रकाश एवं अन्य बुनियादी सुविधाएँ भी सुनिश्चित की गई हैं।राहत शिविरों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए केतेतोंग बीपीएचसी की चिकित्सा टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य जांच, उपचार तथा आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, शिशुओं एवं छोटे बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें पौष्टिक भोजन एवं पूरक पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। बाढ़ से पशुधन पर पड़े प्रभाव को देखते हुए सह-जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहा है, ताकि पशुपालकों की आजीविका की सुरक्षा की जा सके।आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए मार्घेरिटा राजस्व सर्किल के सर्किल अधिकारी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नागरिकों से अनुरोध है कि बाढ़ से संबंधित किसी भी आपात स्थिति, जलभराव, आधारभूत संरचना को हुए नुकसान अथवा बचाव एवं राहत सहायता की आवश्यकता होने पर 6001239068 या 9101098627 पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें।

लखीमपुर महेश्वरी महिला संगठन ने की गुप्त नवरात्रि पर सेवा

खबर संवाददाता

लखीमपुर 21 जुलाई। गुप्त नवरात्रि अष्टमी पर सोमवार को महेश्वरी महिला संगठन लखीमपुर शाखा द्वारा स्थानीय दुर्गा मंदिर में सेवा कार्य किया गया। अध्यक्षा सरिता तापड़िया के नेतृत्व में मंदिर को गुप्त दान स्वरूप अलमारी भेंट की गई और 35 कन्याओं व 2 भैरव जी को भोजन कराया गया। सभी को उपहार स्वरूप जूस,फल व छाते वितरित किए गए। साथ ही लखीमपुर मिलन नगर स्थित श्री श्री जगन्नाथ मंदिर में 15 किलो खिचड़ी का बनाने का सामग्री प्रसाद चढ़ाया भंडारे के लिए भेट किया गया।उक्त कार्यक्रम में सरोज मालपानी, सरिता लाहोटी, रेखा चांडक, ममता गग्गर, संतोष राठी, अंजू बजाज, सुनीता झावर, सुमन तापड़िया व सरिता जाजू उपस्थित रही।

टिओक में राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न

गुवाहाटी डिब्रूगढ़ मार्ग पर वाहनों का रूट बदला गया

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़, 20 जुलाई। असम में जारी भीषण बाढ़ के बीच डिब्रूगढ़ की सड़क संपर्क व्यवस्था भी प्रभावित होने लगी है। जोरहाट जिले के टिओक क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण गुवाहाटी डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान्य यातायात बाधित हो गया है। स्थिति को देखते हुए डिब्रूगढ़ के जिला आयुक्त बिक्रम कैरी ने महत्वपूर्ण ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया है।डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन के अनुसार, गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ आने वाले सभी वाहनों को फिलहाल कलियाबोर से डायवर्ट किया जा रहा है। यह निर्णय शिवसागर और जोरहाट जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों के जलमग्न हो जाने के बाद एहतियात के तौर पर लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि डिब्रूगढ़ आने वाले वाहनों को तेजपुरबिश्वनाथ चारियाली बोगीबील पुल मार्ग से होकर डिब्रूगढ़ भेजा जा रहा है। इस वैकल्पिक मार्ग पर जिला प्रशासन, पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग संयुक्त रूप से यातायात की निगरानी कर रहे हैं ताकि आवश्यक सेवाओं और सामान्य वाहनों की आवाजाही सुरक्षित एवं सुचारु बनी रहे। जैसे ही बाढ़ का पानी घटेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षित घोषित होगा, मूल मार्ग पर यातायात पुनः बहाल कर दिया जाएगा। जिला आयुक्त कैरी ने सभी वाहन चालकों से प्रशासन द्वारा निर्धारित डायवर्जन का पालन करने, ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का सहयोग करने तथा बाढ़ प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति पर जिला प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है और हालात के अनुसार आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने लोगों से यात्रा शुरू करने से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। साथ ही अफवाहों से बचने और केवल जिला प्रशासन एवं संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। डिब्रूगढ़ प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हालात सामान्य होते ही यातायात को पूर्ववत बहाल कर दिया जाएगा।

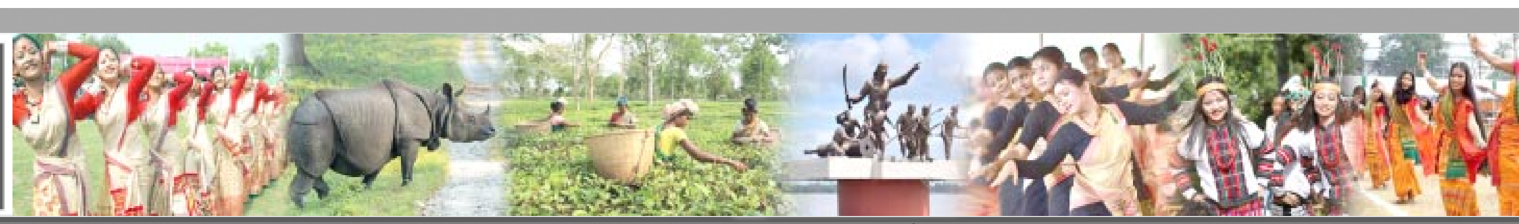

जोरहाट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मिले सांसद गौरव गोगोई

खबर संवाददाता

जोरहाट, 21 जुलाई। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं जोरहाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद गौरव गोगोई ने मंगलवार को जोरहाट जिले के विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा प्रशासन से राहत एवं सहायता कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया। सांसद ने गड़मुर स्थित निगमानंद आश्रम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने 3 नंबर मथाउरी, 2 नंबर मथाउरी, 1 नंबर वार्ड, सेंगेली गेली, एलेंगमोरा, शालमोरा सहित कई क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। इसी बीच पत्रकारों से बातचीत में गौरव गोगोई ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोरहाट और ऊपरी असम में इस प्रकार की भीषण बाढ़ पहले कम देखने को मिली है, जिसके कारण लोग भी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग किसी तरह अपनी जान बचाने और थोड़ा-बहुत सामान सुरक्षित निकालने में ही सफल हुए हैं। गोगोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बाढ़ प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता करने के निर्देश

दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जोरहाट शहर और आसपास के क्षेत्रों में नालियों और जल निकासी व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण शहरी क्षेत्रों में कृत्रिम बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने जिला कांग्रेस से जल निकासी व्यवस्था का सर्वेक्षण कराने को भी कहा। सांसद ने कहा कि लोगों को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है और प्रशासन किस तरह राहत कार्य कर रहा है, इसका आकलन किया जाएगा तथा लोगों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराकर समाधान के लिए दबाव बनाया जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की उपलब्धता को लेकर पूछे गए सवाल पर गोगोई ने कहा कि इस विषय पर कई तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से मिलने वाली एनडीआरएफ की सहायता पर्याप्त नहीं रही है तथा एसडीआरएफ के संसाधनों के उपयोग में भी कई कमियां हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर राज्यों के बीच बाढ़, मौसम और आपदा संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान में समन्वय की कमी है। उनके अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। फोरलेन सड़कों के निर्माण के दौरान जल निकासी मार्ग बाधित होने संबंधी प्रश्न पर सांसद ने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के अभाव और वैज्ञानिक योजना की कमी के कारण बाढ़ की समस्या और गंभीर हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सड़क और फ्लाईओवर निर्माण पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन प्रभावी जल निकासी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई है।जोरहाट के बाद सांसद गौरव गोगोई तिताबर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली।

टियोक के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में एनडीआरएफ का साहसिक अभियान, 5 लोगों की बचाई जान

खबर संवाददाता

जोरहाट 21 जुलाई। जोरहाट जिले के टियोक राजस्व चक्र के अंतर्गत सेलेंग चाय बागान के समीप सेलेंगहाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा बचाव बल और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से पांच लोगों की जान बचाई गई। यह सफल बचाव अभियान 19 जुलाई की शाम को चलाया गया। जिला प्रशासन के अधीन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जोरहाट से प्राप्त आपात सूचना के आधार पर एनडीआरएफ की प्रथम बटालियन के डिप्टी कमांडेंट एन. के. तिवारी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण तथा इंस्पेक्टर के. वी. नाथ के नेतृत्व में एक टीम को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था और कई लोग ऊंचे स्थानों पर फंसे हुए थे। इसके बाद शाम करीब 7:35 बजे खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। अभियान के दौरान टीम को एक जलमग्न घर से मदद की पुकार सुनाई दी। वहां पहुंचने पर देखा गया कि एक किशोरी घर की छत के बांस के खंभे से लटकी हुई थी। बाढ़ का पानी उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था और उसका सिर छत से टकरा रहा था। एनडीआरएफ के जवानों ने साहस, त्वरित निर्णय और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी दौरान बचाव दल ने एक व्यक्ति को तेज बहाव में केले के पेड़ का सहारा लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते देखा। जवानों ने बिना समय गंवाए उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाई गई किशोरी ने टीम को बताया कि पास ही तीन महिलाएं भी केले के पेड़ों का सहारा लेकर बाढ़ के तेज बहाव में फंसी हुई हैं। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने खोज अभियान चलाकर तीनों महिलाओं को भी सुरक्षित बचा लिया। इनमें एक वृद्ध महिला लंबे समय तक ठंडे पानी में रहने के कारण हाइपोथर्मिया से पीड़ित हो गई थीं। उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद सभी पांचों लोगों को सुरक्षित राहत शिविर भेज दिया गया। जोरहाट जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई, साहस, कर्तव्यनिष्ठा और पेशेवर दक्षता की सराहना करते हुए कहा कि समय रहते चलाए गए इस अभियान से पांच अमूल्य जीवन बचाए जा सके। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनडीआरएफ की इस प्रभावी कार्रवाई ने एक संभावित बड़ी त्रासदी को टाल दिया।

डिब्रूगढ़ में किराए के मकान से कारतूस संदिग्ध चोरी के जेवर और नकदी बरामद

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़, 21 जुलाई। अपराध और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से डिब्रूगढ़ पुलिस ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की। डीएसपी (मुख्यालय) के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने पांच आली क्षेत्र स्थित एक किराये के मकान में तलाशी अभियान चलाया, जहां से तीन राउंड जीवित कारतूस, संदिग्ध रूप से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण, कई मोबाइल फोन, नकदी तथा अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, तलाशी अभियान पूर्व में प्राप्त खुफिया सूचना और चल रही जांच के आधार पर संचालित किया गया। बरामद किए गए आभूषणों और अन्य सामान के चोरी की विभिन्न घटनाओं से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सभी बरामद वस्तुओं का सत्यापन कर रही है ताकि उनके वास्तविक मालिकों का पता लगाया जा सके और संबंधित मामलों का खुलासा हो सके। इसी अभियान के दौरान पुलिस ने अमोलापट्टी क्षेत्र से लावारिस अवस्था में खड़ी एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। प्रारंभिक जांच में आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस वाहन का उपयोग आपराधिक गतिविधियों में किया गया हो सकता है। बाइक को जब्त कर फोरेंसिक एवं तकनीकी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

काकोजान क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के बीच छात्र संगठन और मारवाड़ी सम्मेलन ने बढ़ाया मदद का हाथ

खबर संवाददाता

टियोक, 21 जुलाई। टियोक क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति आज दूसरे दिन कुछ सामान्य होने लगी है, लेकिन कई स्थानों पर सड़क किनारे और अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को अब भी पर्याप्त सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है। विशेष रूप से टियोक और काकोजान क्षेत्र के कई राहत शिविरों में खाद्य सामग्री की कमी देखने को मिल रही है। इस परिस्थिति को देखते हुए काकोजान आंचलिक छात्र संस्था ने मंगलवार को सिपाहीखोला बाजार में रह रहे बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान खिचड़ी, पीने का पानी, खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई गईं। छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है तथा प्रशासन से जल्द से जल्द सभी पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने की मांग की है। राहत वितरण कार्यक्रम में पूर्व छात्र नेता देवजीत बोरा, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य संकल्प गोगोई, काकोजान आंचलिक छात्र संस्था के सलाहकार बेदांत भराली, संस्था के अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदाधिकारी और स्वयंसेवक उपस्थित रहे। वहीं, मारवाड़ी सम्मेलन, टियोक शाखा ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान चलाकर फंसे हुए लोगों के बीच खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। बाढ़ से जिन परिवारों के घर जलमग्न हो गए हैं, उनके घरों तक पहुंचकर सम्मेलन के सदस्यों ने हरसंभव सहायता प्रदान की। मारवाड़ी सम्मेलन, टियोक शाखा के सचिव बीजू कुमार तुनवाल ने बताया कि संस्था आगे भी बाढ़ पीड़ितों की हरसंभव सहायता के लिए राहत कार्य जारी रखेगी।

मंत्री केशव महंत ने लिया जोरहाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा

खबर संवाददाता

जोरहाट, 21 जुलाई। असम सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन तथा सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री केशव महंत ने दो दिवसीय दौरे के दौरान जोरहाट जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की, राहत शिविरों का जायजा लिया तथा प्रशासन को राहत कार्यों में किसी प्रकार की कमी न रहने के निर्देश दिए। दौरे के पहले दिन मंत्री ने टियोक के विधायक विकास सैकिया तथा जोरहाट के जिला आयुक्त जय शिवानी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दूसरे दिन उनके साथ मरियानी के विधायक रूपज्योति कुर्मी, तिताबर के विधायक धीरज गोवाला, जिला आयुक्त जय शिवानी, सहायक जिला आयुक्त, राजस्व चक्र अधिकारी एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने

सेलेंगहाट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित राहत शिविर तथा तिताबर राजस्व चक्र के अंतर्गत नारायणपुर पानबाड़ी चाय बागान के दैनिक बाजार भवन में शरण लिए बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल, खाद्य सामग्री, बच्चों के लिए पोषाहार, स्वास्थ्य सेवाएं तथा पशुओं के चारे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जोरहाट सर्किट हाउस तथा तिताबर के सहायक जिला आयुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठकों में मंत्री ने बाढ़ की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों तथा सहायता वितरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने तथा बाढ़ का पानी उतरने के बाद हुए नुकसान का सही आकलन करने के निर्देश दिए। मंत्री केशव महंत ने तिताबर राजस्व चक्र के अंतर्गत नारायणपुर पानबाड़ी चाय बागान में बाढ़ के तेज बहाव में जान गंवाने वाली 16 वर्षीय सोनिया पहाड़िया और 15 वर्षीय सुस्मिता मिर्धा के परिजनों से भी मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा एवं राज्य सरकार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दोनों मृतक छात्राओं के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसी घटना में घायल होकर जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाजरत 15 वर्षीय बबीता छेत्री के परिजनों से भी मंत्री ने मुलाकात की और आश्वासन दिया कि उनके उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि बाढ़ से बेघर और प्रभावित परिवारों को सरकारी मानकों के अनुसार कपड़े तथा घरेलू उपयोग के बर्तन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है।

डिब्रूगढ़ के कमाख्या सैकिया भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के मैनेजर नियुक्त, जिम्बाब्वे दौरे पर संभालेंगे अहम जिम्मेदारी

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़, 21 जुलाई। डिब्रूगढ़ के खेल जगत के लिए एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। डिब्रूगढ़ जिला खेल संघ (डीडीएसए) के महासचिव कमाख्या सैकिया को 20 जुलाई से 28 जुलाई, तक आयोजित होने वाले भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है। उनकी इस प्रतिष्ठित नियुक्ति से न केवल डिब्रूगढ़, बल्कि पूरे असम में खुशी और गर्व का माहौल है। कमाख्या सैकिया लंबे समय से क्रिकेट प्रशासन और खेल विकास के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। डीडीएसए के महासचिव के रूप में उन्होंने डिब्रूगढ़ में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, खेल अधोसंरचना को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खेल प्रशासन में उनके अनुभव, नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक दक्षता को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के मैनेजर के रूप में कमाख्या सैकिया पूरे जिम्बाब्वे दौरे के दौरान टीम के

प्रशासनिक, समन्वय और लॉजिस्टिक प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाएंगे। खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सहयोगी अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ टीम की यात्रा, आवास, अभ्यास और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी भी उनके दायित्वों में शामिल होगी। यह जिम्मेदारी किसी भी अंतरराष्ट्रीय दौरे की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खेल जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि कमाख्या सैकिया की नियुक्ति भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा उनकी कार्यकुशलता और प्रशासनिक अनुभव पर जताए गए विश्वास का प्रमाण है। असम में क्रिकेट के विकास के लिए उनके प्रयासों को पहले भी व्यापक सराहना मिल चुकी है और उन्होंने अनेक युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। डिब्रूगढ़ जिला खेल संघ के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों, विभिन्न खेल संगठनों तथा सामाजिक संस्थाओं ने कमाख्या सैकिया को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है। उनका कहना है कि यह नियुक्ति पूरे जिले और राज्य के लिए सम्मान की बात है तथा इससे पूर्वोत्तर भारत के खेल प्रशासकों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।डिब्रूगढ़ के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़ने वाले खेल प्रशासकों की संख्या बहुत सीमित होती है। कमाख्या सैकिया की नियुक्ति से यह संदेश भी जाता है कि समर्पण, अनुभव और कुशल प्रशासनिक क्षमता के बल पर पूर्वोत्तर भारत के खेल प्रशासक भी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। उनकी इस सफलता को डिब्रूगढ़ और पूरे असम के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

डिब्रूगढ़ शहर में घूम रहे जंगली घोड़ों को वन विभाग ने किया बरामद

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़ 21 जुलाई। डिब्रूगढ़ शहर में पिछले कुछ दिनों से खुलेआम घूम रहे जंगली घोड़ों को असम वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वन विभाग ने किसी भी संभावित दुर्घटना तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी स्थिति से बचने के लिए सभी घोड़ों को सिसू सापोरी में स्थानांतरित कर दिया है। विभाग ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ घोड़ों को भी सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना था। असम के वन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अभियान की जानकारी साझा करते हुए कहा कि डिब्रूगढ़ शहर में जंगली घोड़ों के घूमने

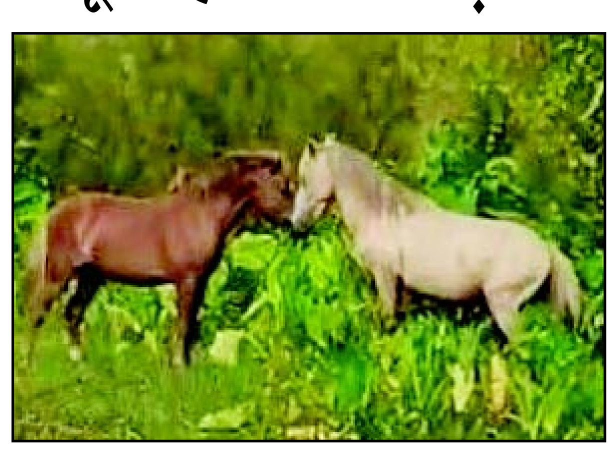

की सूचना मिलते ही वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। प्रशिक्षित टीमों ने सावधानीपूर्वक अभियान चलाकर सभी घोड़ों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि न तो किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचे और न ही जानवरों को किसी प्रकार की चोट आए।वन मंत्री ने बताया कि घोड़ों के वास्तविक मालिकों का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति ने उन पर अपना दावा नहीं किया है। ऐसे में विभाग ने उनके दीर्घकालिक संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सिसू सापोरी में बसाने का निर्णय लिया, जहां पर्याप्त चरागाह, प्राकृतिक वनस्पति, चारे की उपलब्धता तथा सुरक्षित आवास मौजूद है। इससे घोड़े प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे और उनके स्वास्थ्य व संरक्षण की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सिसू सापोरी घोड़ों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक आवास है और वहां नियमित निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी। विभाग समय-समय पर उनके स्वास्थ्य, भोजन तथा सुरक्षा की समीक्षा करेगा ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वन विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि भविष्य में किसी जंगली अथवा आवारा पशु के आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश की सूचना मिले तो स्वयं उन्हें पकड़ने या भगाने का प्रयास न करें। इसके बजाय तत्काल वन विभाग या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दें, ताकि प्रशिक्षित दल सुरक्षित ढंग से आवश्यक कार्रवाई कर सके।

Onyx®
high technology batteries
An ISO 9001 : 2015 Certified Company
SUPREME POWER INDUSTRIES
Mfg. of all types of Inverter, Automotive & E-Rick Batteries
Mariani Road, Cinnamara, Jorhat (Assam) 785008
E-mail : onyxbatteries@gmail.com
For Trade Enquiry Dial :
94350-52877/91018-74862
DEALER
JORHAT- 99546-01024, 98540-10510, 70026-10137, 94350-96629 NAGAON-94351-62696 LAKHIMPUR- 94351-82787 BORPATHAR- 94357-42389 SARUPATHAR- 70020-37117 BOKAJAN- 94351-82777, 70026-02799, 75770-99894, 99545-87019, 70028-58905 AMGURI- 73990-23273 SIVASAGAR- 99545-65426, 99545-55870, 94351-56225, 70027-45052 DIBRUGARH- 99544-75308 TINSUKIA- 70027-10942 MOKOKCHUNG- 98626-72609, 84138-48878 DIMAPUR- 94366-02206, 98561-08750, 70051-20250

सिमलगुड़ी के निकट बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रो में रेलवे ने शुरू किए व्यापक बहाली कार्य

डीआरएम पराग कातरे ने यात्रियों के लिए दिया खास इंतजाम का भरोसा

खबर संवाददाता

तिनसुकिया, 21 जुलाई। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण दिखौ नदी सिमलगुड़ी के पास उफान पर है।इसके चलते रेलवे ट्रैक,रेलवे कॉलोनी तथा आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है।एहतियातन सुरक्षा उपाय के तहत तिनसुकिया मंडल के सिमलगुड़ीनामटी और सिमलगुड़ीसिलापाथर खंडों पर रेल सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं तथा प्रभावित खंड में ट्रेनों का परिचालन नियंत्रित किया गया है।यह जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभाकक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीआरएम पराग कातरे द्वारा दी गई। एडीआरएम अजय प्रधान,सीनियर डीसीएम तेचि कुमार,सीनियर डीओएम सबजार अहमद सहित अन्य रेलवे विभाग के अन्य पदाधिकारीयो की मौजूदगी में पत्रकार को संबोधित करते डीआरएम ने बताया कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और रेल सेवाओं की शीघ्र बहाली के लिए तत्काल व्यापक राहत एवं पुनर्स्थापन कार्य युद्धस्तर शुरू कर दिए हैं। भीषण बाढ़ से उत्पन्न व्यवधान के कारण कई ट्रेनों को रद्द,शॉर्ट टर्मिनेट,नियंत्रित अथवा मार्ग परिवर्तित (डायवर्ट) किया गया है।उन्होंने बताया यात्रियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमे सड़क मार्ग से परिवहन के तहत प्रभावित क्षेत्र में फंसे यात्रियों को सड़क मार्ग से सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है।वही विशेष ट्रेन सेवा के तहत प्रभावित यात्रियों की आगे की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए शिवसागर टाउन और न्यू तिनसुकिया के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है।यात्री सहायता केंद्र प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं,जहां यात्रा संबंधी जानकारी और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।प्रभावित यात्रियों को रेलवे के प्रचलित नियमों के अनुसार टिकट राशि का शीघ्र और सुगम रिफंड दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार रेल सेवाओं को पूरी तरह सामान्य करने में लगभग 15 दिन लग सकते हैं।रेलवे की टीमें युद्धस्तर पर चौबीसों घंटे बहाली कार्य में जुटी हुई हैं ताकि सुरक्षा के सर्वोच्च मानकों का पालन करते हुए जल्द से जल्द परिचालन सामान्य किया जा सके। बहाली कार्य के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भोजो और डिब्रूगढ़ के बीच प्रतिदिन एक विशेष ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है,जो

परिचालन की व्यवहार्यता और आवश्यक स्वीकृतियों के अधीन होगी।वरिष्ठ रेलवे अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं तथा बहाली कार्यों का समन्वय कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं यात्रियों से सहयोग करने के साथ ही अनुरोध किया गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक रेलवे पूछताछ माध्यमों से अपनी ट्रेन की नवीनतम स्थिति अवश्य जांच लें।